चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 10 अक्टूबर– 16 अक्टूबर 2016 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

अमित शाह जी, राजस्थान की तरफ देखिए

चित्रापति

राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसे भारतीय जनता पार्टी अपने सुशासन का बेहतर उदाहरण मानती है. ऐसा ही दूसरा उदाहरण मध्य प्रदेश है. मध्यप्रदेश में इतनी हत्याएं हो चुकी हैं कि उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए हैं, लेकिन सीबीआई अगले सौ वर्षों तक भी उसका कुछ हल निकाल पाएगी, पता नहीं. लेकिन, यह सुशासन, भारतीय जनता पार्टी मार्का सुशासन बनता जा रहा है. पहला उदाहरण राजस्थान को मानते हैं और जब राजस्थान में झांकते हैं, तब वहां जो खामियां नजर आती हैं, उन्हें उठाने का साहस न पत्रकार कर रहे हैं, न विधायक और आश्चर्यजनक रूप से न कांग्रेस के नेता ही कर रहे हैं. इसका मतलब है कि जिन प्रदेशों में भी शासन को लेकर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, वहां का विपक्ष बिल्कुल मूक, निष्क्रिय और दूसरे शब्दों में कहें तो अकर्मण्य है. हम जानते हैं कि बात राजस्थान की हो या मध्य प्रदेश की, केंद्र में बैठे भाजपा के बड़े नेता इस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब विपक्ष ही इसे नहीं उठा रहा है या उद्वेलित हो रहा है, तो उन्हें इस पर सोचने की क्या जरूरत है. पर, अमित शाह जी से इतना अनुरोध तो अवश्य किया जा सकता है कि आने वाला चुनाव ऐसा ही परिणाम देगा, जैसा उन्हें इस बार मिला है, इसमें संदेह है. इसलिए, अगर वो चाहें तो राजस्थान में उठ रहे सवालों को लेकर राजस्थान की मुख्यमंत्री से बात करें और राजस्थान के प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने में पार्टी अध्यक्ष का जैसा रोल होता है, उसे निभाएं. दरअसल ये पूरी रिपोर्ट अमित शाह जी को राजस्थान में चल रहे लुंज-पुंज प्रशासनिक अवस्था से अवगत कराने के लिए है.

राजस्थान में अभी पिछले साठ साल के इतिहास का सबसे बुरा गवर्नेंस (प्रशासन) देखने को मिल रहा है. प्रशासनिक तौर पर राज्य बिल्कुल डगमगाया हुआ है. सरकार और प्रशासनिक तंत्र (ब्यूरोक्रेसी) की हालत खराब है. ब्यूरोक्रेसी और सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार चार लोग, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू सीएम, डीओपी सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी हैं. ये चारों संस्थाएं चरमराई हुई स्थिति में हैं.

पहले बात करते हैं मुख्य सचिव चंद्रशेखर राजन की, जो जून 2016 तक अपने पद पर रहे. चंद्रशेखर राजन जब तक अतिरिक्त सचिव थे, सफल रहे, लेकिन मुख्य सचिव के तौर पर वे बिलकुल फेल हो गए. मुख्य सचिव का काम होता है योजनाएं बनाना, विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना और आईएएस अधिकारियों के कस्टोडियन के तौर पर काम करना. इस काम में वे बिलकुल असफल साबित हुए. कोई भी जिलाधिकारी आकर उनसे कुछ कहे, अपनी समस्या बताए, लेकिन राजन उन अधिकारियों की समस्याओं का समाधान निकालने में असफल रहे. फेल इसलिए हुए, क्योंकि वे मुख्यमंत्री के गुलाम बनकर रह गए. दरअसल, वे दिसंबर 2015 में रिटायर होने वाले थे. दिसंबर के बाद अगर वे एक दिन भी इस पद पर रहते तो सातवें वेतन आयोग के हकदार हो जाते और उन्हें करीब चालीस लाख रुपए मिलते. इसलिए वे किसी भी तरीके से अपना कार्यकाल बढ़ाना चाहते थे. इसलिए ब्यूरोक्रेसी में जो भी गलत हो रहा था, उस कार्य का उन्होंने विरोध नहीं किया. इसके बाद जब उनका तीन महीने का कार्यकाल बढ़ गया, तो उन्होंने उस दौरान कोई कार्य ही नहीं किया. इसके बाद फिर तीन महीने का उनका कार्यकाल बढ़ा और इस दौरान भी उन्होंने कुछ नहीं किया.

इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही कि उनके बाद ओपी मीणा को मुख्य सचिव बनाया गया. ओपी मीणा सीनियर अधिकारी थे, लेकिन वे प्रशासनिक तौर पर अपने करियर में कभी अहम पदों पर नहीं रहे और हमेशा साइड लाइन रहे. उनका प्रशासनिक अनुभव काफी कम रहा. योग्यता और क्षमता में पीछे होने के बाद भी वे जातिगत तौर पर काफी मजबूत स्थिति में थे, क्योंकि वे मीणा समुदाय से आते हैं. मीणा जाति को खुश करने के लिए राज्य सरकार ने ओपी मीणा को मुख्य सचिव बना दिया. ओपी मीणा 1 जुलाई 2016 से लेकर आज की तारीख तक मुख्य सचिव के पद पर हैं. गौरतलब है कि मीणा के खिलाफ उनकी पत्नी और बेटी ने ही गंभीर आरोप लगाए हैं, फिर उन्हें कैसे इस महत्वपूर्ण पद पर तैनात किया गया? ओपी मीणा की पत्नी ने अपराध शाखा, महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग में केस दर्ज कराया हुआ है. वहीं, उनकी बेटी ने लंदन से अपने पिता द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया है. मुख्य सचिव की छवि ही खराब है. जाहिर है, वे भले ही मुख्य सचिव की कुर्सी पर हों, लेकिन उनका प्रशासन में इकलाब कायम नहीं है. जब मुख्य सचिव ही कमजोर हैं, तो प्रशासन में उनकी क्या भूमिका होगी और मुख्यमंत्री उन्हें कितनी तवज्जो देती होंगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. यानी, राजस्थान में मुख्य सचिव नाम की संस्था ही पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है.

ओपी मीणा, मुख्य सचिव, राजस्थान

दूसरे नंबर पर हैं, सेक्रेटरी टू सीएम. एक जमाने में सुनील अरोड़ा, श्रीमंत पांडेय, पीके मैथ्यू, आदर्श किशोर जैसे लोग सेक्रटरी टू सीएम हुआ करते थे. इस बार मुख्यमंत्री ने आते ही तन्मय कुमार, जो पिछले कार्यकाल में सीएमओ में कार्यरत थे, को अपना सचिव बना लिया, जबकि सेक्रेटरी लेवल के कई सीनियर अधिकारी इस पद के दावेदार थे. लेकिन प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि तन्मय कुमार का काम और कमांड बहुत ही कमजोर है. एक तो वे बहुत जूनियर हैं, इस कारण सीनियर अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, और न ही सीएमओ का इकबाल जिलों में कलेक्टरों पर कायम कर सकते हैं. इसलिए सारे विधायक भी उनसे नाराज हैं और कई बार मुख्यमंत्री से गुजारिश कर चुके हैं कि तन्मय की जगह पर कोई अच्छा अधिकारी लाइए. लेकिन मुख्यमंत्री तन्मय कुमार की अंधभक्त हैं. उन्होंने सारा कमान तन्मय कुमार को सौंप रखा है. मुख्य सचिव के कमजोर होने के कारण तन्मय कुमार ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफर-पोस्टिंग में जमकर अपनी मनमर्जी चला रहे हैं. किसी जमाने में वहां दक्षिण भारतीय अधिकारी होते थे. तन्मय कुमार बिहार से हैं, इसलिए उन्होंने जितने बिहार के अधिकारी हैं, उन्हें अच्छी-अच्छी जगहों पर स्थापित कर दिया है. इसके अलावा 1993 बैच के सात अधिकारियों को बढ़िया जगह पर तैनाती दिला दी है. मतलब यह है कि सीएमओ नाम की संस्था भी भगवान भरोसे ही चल रही है. अब बात डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल (डीओपी) की, जो सभी कर्मचारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग देखता है. लेकिन वे भी तन्मय कुमार के यस मैन बन कर रह गए हैं. इसके बाद नंबर आता है गृह सचिव का. ए मुखोपाध्याय गृह सचिव हैं, लेकिन वे भी प्रभावशाली नहीं रहे. उनके अधीन एक सेक्रेटरी संजीव वर्मा लाए गए. दोनों में छत्तीस का आंकड़ा होने के कारण एक साल तक गृह विभाग पूरी तरह से निष्क्रिय बना रहा. यानी, पिछले कुछ समय तक राज्य सरकार के ये चारों महत्वपूर्ण विभाग चरमराई हुई स्थिति में रहे.

अब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की. राज्य में कई अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे थे. प्रशासनिक स्तर पर सभी अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी कि चार-पांच जिला

(शेष पृष्ठ 2 पर)

गौमाता के नाम पर...

गायों को लेकर राजनीति चरम पर है. लेकिन, एक दिलचस्प जानकारी ये निकल कर सामने आई है कि बीजेपी शासित राज्यों में (राजस्थान और हरियाणा को छोड़ कर) सरकारी गौशाला है ही नहीं. राजस्थान के अलावा भाजपा शासित राज्य असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में एक भी सरकारी गौशाला नहीं है. हरियाणा में जहां सिर्फ 2 सरकारी गौशालाएं हैं, वहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार 1304 गौशालाएं चला रही है. राजस्थान अकेला ऐसा राज्य है, जहां गौरक्षा मंत्रालय और मंत्री भी हैं. ओटाराम यहां के गौरक्षा मंत्री हैं. इसके बावजूद, राजस्थान में गायों की हालत का खुलासा पिछले कुछ दिनों तब हुआ, जब हिंगोनिया गोशाला में गायों के मरने की लगातार खबरें आईं. वैसे, एक अनुमान के मुताबिक राजस्थान में साल 2004 से लेकर अब तक करीब एक लाख गायें दम तोड़ चुकी हैं. जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में 1 जनवरी से 31 जुलाई 2016 के बीच 8 हजार से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है. गौरतलब है कि राजस्थान गौ टैक्स लगाने वाला पहला राज्य है, जहां सरकार को इससे करीब 100 करोड़ रुपए मिले हैं. लेकिन सवाल ये है कि टैक्स के इस पैसे को कहां खर्च किया जा रहा है? ■

कश्मीर अविश्वास के बीच स्थिति सामान्य हो रही है... | P-3

बीजेपी का साथ बाबा का विकास | P-4

स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी संस्था के बारे में भेजी फर्जी रिपोर्ट | P-5

अमित शाह जी, राजस्थान की तरफ देखिए

पृष्ठ 1 का शेष

अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन उनको सीएमओ का प्रश्रय मिला हुआ था. हालात ऐसे बन गए कि मुख्य सचिव भी उन्हें अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते थे. जब चार-पांच जिला अधिकारी खुलकर भ्रष्टाचार करने लगे तो इससे दूसरे जिला अधिकारियों का भी मनोबल बढ़ा. खुलेआम भ्रष्टाचार होने लगा. सबसे बड़ी बात यह है कि एसीबी ने चार बड़े डिपार्टमेंटल छापे मारे. खनन विभाग में छापेमारी के दौरान अशोक सिंह पकड़े गए. वे सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी थे, उनके पकड़े जाने से पूरा प्रशासन अमला हिल गया. इसके बाद नीरज के पवन, जो काफी जूनियर आइएएस और सीएम के खास थे, उनको भी भ्रष्टाचार में पकड़ा गया.

चिकित्सा विभाग में भी बड़े-बड़े अधिकारियों को पकड़ा गया. पीएचडी में भ्रष्टाचार का आलम ये था कि वहां एक दर्जन से ज्यादा अधिकारी भ्रष्टाचार में पकड़े गए. सवाल है कि राज्य सरकार ढाई साल बाद भ्रष्टाचार करने वालों को पकड़ रही है तो उनको अब तक क्यों छूट मिली हुई थी? इसका साफ मतलब यह है कि प्रशासन तंत्र पर न मुख्यमंत्री की पकड़ है, न मुख्य सचिव की और न ही सीएमओ की. इस तरह से पूरा प्रशासन तंत्र भ्रष्ट अधिकारियों से पटा हुआ है.

मुख्यमंत्री को राजनीतिक कार्यों से फुरसत नहीं है. मुख्य सचिव और सीएमओ प्रशासन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. किस अधिकारी को कहां लगाया जाए, किसी को नहीं मालूम. अच्छे अधिकारियों को साइड लाइन कर दिया गया है और मध्यम कद के अधिकारियों को प्राइम पोजीशन पर रखा गया है. उदाहरण के तौर पर जयपुर मेट्रो की बात करते हैं. जयपुर मेट्रो में पिछले ढाई साल के दौरान निहालचंद गोयल ने शानदार काम किया और इसे तय समय पर चालू कराया. जयपुर मेट्रो का काम काफी कठिन था, जिसे चुनौती की तरह लेकर निहालचंद गोयल ने बेहतर काम किया. और जब इसका दूसरा चरण चल रहा है, तो निहालचंद गोयल का ट्रांसफर कर, अश्विनी भगत को लगाया गया. अश्विनी भगत, निहालचंद गोयल के मुकाबले काबिलियत में कहीं नहीं ठहरते हैं. लेकिन, ऐसा हुआ क्योंकि यहां सीएमओ की मर्जी चलती है. किस अधिकारी को कहां लगाया जाए, इसे देखने वाला कोई नहीं. जो व्यक्ति सीएमओ का नजदीकी है वह अच्छी जगह पा रहा है और अच्छे अधिकारी हतोत्साहित हो रहे हैं. मुख्य बात यह है कि एक दर्जन अच्छे अधिकारी हाशिए पर हैं और कम प्रतिभाशाली अधिकारी प्राइम पोजीशन पर बैठे हैं. इससे पूरा प्रशासन हतोत्साहित है और अच्छे अधिकारियों में काम करने के लिए कोई उत्साह नहीं रह गया है. राजस्थान सरकार के दिसंबर में तीन साल पूरे हो जाएंगे. अभी सरकार के पास दो साल और बचे हैं. लोगों का कहना है कि अगर दो साल में प्रशासन ठीक नहीं हुआ तो यह प्रशासन ही सरकार को ले डूबेगा. एक अहम उदाहरण हमारे सामने है. वर्तमान में मुख्य सचिव ओपी मीणा, जो बिलकुल अप्रभावी हैं. उन पर कई आरोप भी लग चुके हैं. उनके खिलाफ उनकी पत्नी ने प्रताड़ना का मुकदमा कर रखा है. हाईकोर्ट में उनकी पत्नी ने कहा कि मीणा मुख्य सचिव बन गए हैं और उनका प्रभाव पुलिस में है (पुलिस ने चालान पेश करने की तैयारी की थी, जिसे उनके मुख्य सचिव बनते ही रोक दिया गया है) इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए. हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार से हाल में पूछा है कि क्यों न मुख्य सचिव के खिलाफ जांच सीबीआई को सौंप दी जाए? उनके खिलाफ यदि सीबीआई जांच सौंपी जाती है, तो नैतिक रूप से मुख्य सचिव के पद पर बने रहना सही नहीं होगा. और, अगर वे इस पद पर बने भी रहेंगे तो उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा. अब नया मुख्य सचिव कौन होगा, इसे लेकर ब्यूरोक्रेसी में काफी चर्चा है. इस पद के लिए आठ अधिकारी दावेदार हैं, लेकिन आठों मुख्य सचिव बनने के योग्य नहीं हैं. नौंवे और दसवें नंबर पर जो अधिकारी हैं, वे मुख्य सचिव बन सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री फिर उन आठ अधिकारियों को सचिवालय से बाहर करेंगी. क्योंकि, जब जूनियर मुख्य सचिव बनेगा तो सीनियर को सचिवालय से बाहर निकालना पड़ता है. तो क्या डीबी गुप्ता, जो सबसे योग्य हैं और दसवें नंबर पर हैं, मुख्य सचिव बनेंगे? अगर डीबी गुप्ता मुख्य सचिव बनते हैं, तो वे मुख्यमंत्री के भी करीबी हैं. वे सरकार के बाकी बचे कार्यकाल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं और सबको साथ लेकर चल सकते हैं. उनकी छवि भी अच्छी है. लेकिन मुख्यमंत्री को इसके लिए ऊपर के नौ अधिकारियों को किनारे करना होगा. वर्तमान मुख्य सचिव का कार्यकाल अगले वर्ष जून तक है. अगर उनके खिलाफ सीबीआई जांच होती है तो उन्हें बीच में ही पद से हटना होगा. यदि डीबी गुप्ता मुख्य सचिव बनते हैं, तो ऊपर के आठ-नौ अधिकारी काम नहीं कर पाएंगे. उमेश कुमार 1983 बैच के सीनियर अधिकारी हैं. उमेश कुमार भी मुख्य सचिव पद के दावेदार थे. वे एडीबी में पांच साल तक रहे थे और जब उनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो वे दिल्ली आ गए थे. वे भारत सरकार में बैंकिंग सचिव बनने जा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से एनओसी नहीं दिया और उनको राजस्थान बुला लिया और राजस्थान में एसीएस उद्योग बना दिया. उमेश कुमार को बैंकिंग सचिव बनना था, उन्हें दिल्ली रहना था. वे पांच साल विदेश में रहे, इसलिए राजस्थान में आकर वे कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं. उद्योग, जो एक प्रमुख फ्रंट है, उसे उमेश कुमार के हाथों में देने से वहां कुछ काम होगा, इसकी उम्मीद कम ही लग रही है.

फिलहाल, राजस्थान भाजपा के अंदर सब वन मैन शो हैं. मंत्री करीब-करीब स्टाम्प बने हुए हैं. घनश्याम तिवारी प्रभावी राजनेता थे. वे बगावत कर सरकार से बाहर हैं और अपनी ही पार्टी की सरकार का विरोध कर रहे हैं. मुख्यमंत्री का विकल्प आज के विधायकों में कोई नहीं है. मुख्यमंत्री का विकल्प गुलाबचंद कटारिया हुआ करते थे, लेकिन अब वे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे. वो बहुत सज्जन और सीधे आदमी हैं. वे पिछली वसुंधरा सरकार में विरोधी खेमे में थे, लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है. वो मुख्यमंत्री के दावेदार भी नहीं हैं और वे मुख्यमंत्री बनेंगे भी नहीं. मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं किरण माहेश्वरी. जब ललित मोदी कांड हुआ था तो यह कहा जा रहा था कि किरण माहेश्वरी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा. लेकिन तब से वसुंधरा राजे की आंख की किरकिरी बनी हुई हैं किरण माहेश्वरी. जलवायु विभाग में हुए घूस कांड के कुछ छींटे किरण माहेश्वरी पर भी पड़े हैं, इस मामले में उनके ओएसडी पकड़े गए हैं. ऐसे में, अब किरण माहेश्वरी दावेदार होते हुए भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकती हैं. अब सवाल यह है कि यदि वसुंधरा राजे हटती हैं, तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? 173 विधायकों में 100 विधायक खिलाफ हैं, लेकिन सवाल है कि विकल्प क्या है? जितने विकल्प थे, वे सब धाराशायी हो गए हैं और दूसरे विकल्प खड़े नहीं होने दिए गए. राजेंद्र राठौर भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे और पिछली सरकार में विकल्प के तौर पर बहुत उभरे थे. लेकिन राजेंद्र राठौर भी शरणागत हो गए मुख्यमंत्री के सामने. अशोक परनामी, जो पिछले पंद्रह वर्षों से अध्यक्ष रहे हैं, वे मुख्यमंत्री की जगह ले सकते हैं, लेकिन अशोक परनामी मुख्यमंत्री के मैटेरियल नहीं हैं. वे बहुत ही साधारण किस्म के राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए कह सकते हैं कि यहां वसुंधरा राजे का कोई विकल्प नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 08 अंक 32
10 अक्टूबर- 16 अक्टूबर 2016
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय	0120-6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022-42296060
	+91-8451050786
	+91-9266627379
फैक्स न.	0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

त्वरित नियुक्ति

सरकार को लगभग एक महीने लग गए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के नए प्रमुखों की नियुक्ति करने में. यह देरी आश्चर्य की बात तो थी, लेकिन शायद उड़ी आतंकी हमले ने सरकार को त्वरित कार्रवाई के लिए प्रेरित किया. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ओपी सिंह, 1983 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, का नाम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक और सुधीर प्रताप सिंह, 1983 बैच के राजस्थान कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी का नाम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक (एनएसजी) के रूप में तय किया. दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड सराहनीय रहा है. दिलचस्प है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) में 32 साल के दौरान 29 महानिदेशक हुए हैं यानी एक वर्ष का औसत कार्यकाल रहा है. कई महानिदेशक तो बस कुछ ही महीनों की सेवा दे सके. आशा है कि नई नियुक्ति का सेवाकाल अधिक होगा. इस बीच, एक और उच्चस्तरीय नियुक्ति के तहत, आर के पचनन्दा, 1983 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, को राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ) का महानिदेशक बनाया गया है. अब देखना है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और खुफिया ब्यूरो के (आईबी) के नए मुखिया कौन होते हैं, जिनका कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो रहा है.

सीबीएसई पर बोझ

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि कई ऐसी परीक्षाओं, जो इसके दायरे से बाहर हैं, का संचालन करने से उस पर बाहरी बोझ बढ़ गया है. सूत्रों का कहना है कि सीबीएसई अध्यक्ष आर चतुर्वेदी ने कहा है कि सीबीएसई स्कूल स्तर की परीक्षाओं का आयोजन ठीक से कर ही रहा है और ऐसे में जब इसे अन्य परीक्षाओं का संचालन करना होता है तो इसके संसाधनों का बेजा इस्तेमाल होता है. इस पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है. चतुर्वेदी ने ये पत्र तब लिखा है जब अगले साल की शुरुआत में यूजीसी-नेट परीक्षा आयोजित होने की संभावना है. ज्यादातर का मानना है कि चतुर्वेदी की चिंताओं के बावजूद, बोर्ड को वैकल्पिक प्रणाली मिलने तक परीक्षा का संचालन करने के लिए कहा जाएगा. लेकिन चतुर्वेदी की चिंता से सीबीएसई के कई लोग सहमत हैं कि बोर्ड को अपनी मूल जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए. सीबीएसई केन्द्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का संचालन करने पर सहमत हो गया है, लेकिन यह सुझाव दिया है कि एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए.

खानाबदोश जीवन

पहले अशोक खेमका थे, जिनका कितनी बार तबादला किया गया, उन्हें याद भी नहीं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि राज्य में किसकी सत्ता है, लेकिन अब इस लिस्ट में हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी प्रदीप कासनी का भी नाम जुड़ गया है. हाल में कासनी को राज्य के वित्त विभाग में सचिव के रूप में कार्यभार संभालने के 12 घंटे के भीतर स्थानांतरित किया गया. दो दिन पहले ही उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से यहां लाया गया था. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में भी वे महज तीन महीने रह सके थे. 1984 में राज्य सिविल सेवा में शामिल होने के बाद से अब तक उनका 66 बार स्थानांतरण हो चुका है. दिसंबर 2014 में वे गुड़गांव के संभागीय आयुक्त थे. खट्टर सरकार के आने के बाद कासनी ने एक रिपोर्ट दी थी कि कैसे कुछ राजस्व अधिकारियों ने भूमाफिया के साथ मिल कर काम किया है. इस रिपोर्ट के मिलने के दो दिनों के भीतर ही उनका तबादला कर दिया गया. इससे पहले 2006 में कासनी जब सचिव, राज्य विद्युत नियामक आयोग बने, तब पदभार संभालने के 30 मिनट के भीतर ही उनका तबादला हो गया था. 2012 में वे सिर्फ तीन दिनों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण के निदेशक बने.

कश्मीर

अविश्वास के बीच स्थिति सामान्य हो रही है...

मोहल्ले की मस्जिदों में नारेबाजियों का सिलसिला थम चुका है. पथराव की घटनाओं में भी काफी कमी आई है. यहां सवाल पैदा होता है कि क्या कश्मीर के लोगों की भावनाएं भी ठंडी पड़ गई हैं और क्या उन्होंने संघर्ष करना बंद कर दिया है? ऐसा नहीं लगता. सच तो यह है कि लगातार हिंसा की वजह से कश्मीरी निढाल ज़रूर हो गए हैं, लेकिन उनके राजनीतिक विचार में कोई बदलाव नहीं आया है. कश्मीरी जनता की थकावट अपेक्षित थी. पिछले तीन महीनों के दौरान कश्मीरी जनता के ऊपर जो कुछ बीता है उसे सहने के बाद ऐसा ही कुछ होना था. तीन महीने कश्मीर बंद रहने का मतलब यह था कि एक अरबपति व्यापारी से लेकर एक खोमचे लगाने वाला शख्स तक बड़े आर्थिक नुक़सान से दो चार हुए.

हारून रेशी

तीन महीने तक लगातार हड़ताल और कर्फ्यू की वजह से कश्मीर घाटी की जनता अपने घरों में क़ैद है. इस अवधि में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान 88 लोग मारे गए हैं और करीब 13 हजार लोग जख्मी हुए हैं. पैलेट गन की वजह से कई बच्चों समेत 300 लोगों की आंखों की रौशनी चली गई है. पुलिस अब तक प्रदर्शन करने वाले चार हज़ार नौजवानों को गिरफ्तार कर चुकी है. पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 500 लोगों को जेल भेज दिया गया है. इसका सीधा मतलब यह है कि इन 500 लोगों को किसी अदालत में पेश किए बिना दो साल तक जेल में रखा जा सकता है. उन्हें कोई कानूनी मदद नहीं मिल सकती है. यह वो स्थिति है, जिसका सामना कश्मीर के लोग लगातार तीन महीने से कर रहे हैं. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तीन महीने तक संकट से लगातार जूझ रहे लोग अब पस्त हो गए हैं. यही वजह है कि बस्तियों, सड़कों व राजमार्गों पर होने वाले प्रदर्शनों में कमी देखने को मिल रही है. मोहल्ले की मस्जिदों में नारेबाजियों का सिलसिला थम चुका है. पथराव की घटनाओं में भी काफी कमी आई है. यहां सवाल पैदा होता है कि क्या कश्मीर के लोगों की भावनाएं भी ठंडी पड़ गई हैं और क्या उन्होंने संघर्ष करना बंद कर दिया है? ऐसा नहीं लगता. सच तो यह है कि लगातार हिंसा की वजह से कश्मीरी निढाल ज़रूर हो गए हैं, लेकिन उनके राजनीतिक विचार में कोई बदलाव नहीं आया है. कश्मीरी जनता की थकावट अपेक्षित थी. पिछले तीन महीनों के दौरान कश्मीरी जनता के ऊपर जो कुछ बीता है उसे सहने के बाद ऐसा ही कुछ होना था. तीन महीने कश्मीर बंद रहने का मतलब यह था कि एक अरबपति व्यापारी से लेकर एक खोमचे लगाने वाला शख्स तक बड़े आर्थिक नुक़सान से दो चार हुए.

सरकार पिछले तीन महीनों के दौरान सरकारी कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी पर आने के लिए राजी नहीं कर सकी है. यहां के बैंक भी हुर्रियत के प्रोग्राम पर अमल करते हुए सिर्फ हड़ताल में ढील के दौरान ही काम करते हैं. कश्मीर पुलिस में शामिल लोगों के अपने रिश्तेदार भी विरोध-प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं. इस तरह से साफ जाहिर है कि नई दिल्ली ने सुरक्षाबलों के जरिए लगातार कश्मीरी जनता के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया है. उन्हें लगातार घरों के अंदर कैद रहने पर मजबूर किया गया. कश्मीरियों के दिलों में अब नई दिल्ली के लिए नाराजगी के वो बीज बो दिए गए हैं, जिन्हें उखाड़ना अब काफी मुश्किल होगा.

हजारों ज़ख्मियों में से सैकड़ों ऐसे हैं, जिनकी हालत अब भी नाज़ुक बनी हुई है. हताहत होने वालों की संख्या में अभी और इजाफा हो सकता है. इसके अलावा, उन लाखों आम मरीजों को नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता है, जिनका हालत ख़राब होने की वजह से इलाज नहीं हो सका. चूंकि पिछले तीन महीने के दौरान आम हड़ताल, कर्फ्यू और नौजवानों के पथराव की वजह से कश्मीर घाटी की तमाम सड़कें और राजमार्ग आम तौर से बंद रहे हैं, इसलिए मरीजों को अस्पतालों या प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाना मुमकिन नहीं हो पाया. सच तो यह है कि हालात खराब रहने की वजह से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के शिकार लोगों को भी सामान्य उपचार नहीं मिल सका. श्रीनगर और घाटी के दूसरे कस्बों के ज्यादातर अस्पतालों में इस अवधि में ओपीडी विभाग आम तौर पर बेअसर रहा. इस दौरान डॉक्टर पैलेट गन से ज़ख्मियों का ही इलाज करते रहे. आम मरीजों का इलाज नहीं हो पाया.

दरअसल, तीन महीने के इस प्रदर्शन के दौरान कश्मीरी जनता हर तरह के मुसीबतों और समस्याओं का सामना कर रहे हैं. यही वजह कि अब वे निढाल हो गए हैं. इस मुसीबत पर एक और मुसीबत यह है कि इतनी विपरीत स्थिति में कश्मीर के लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद भी नई दिल्ली की सरकार टस से मस नहीं हो रही है. आम तौर पर इन परिस्थितियों में अवाम के ज़ख्मों पर मरहम रखने का एकमात्र तरीका बातचीत शुरू करना होता है. लेकिन केंद्र सरकार, चाहे वे खुद प्रधानमंत्री मोदी हों या कोई अन्य भाजपा नेता, अपने बातचीत के अंदाज़ और तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर कश्मीरी जनता के ज़ख्मों पर मरहम के बजाय नमक छिड़कते नज़र आ रहे हैं. इस स्थिति का सबसे अधिक नुकसान ज़ाहिर है कि कश्मीरी जनता का ही हो रहा है.

यहां यह बात दावे से कही जा सकती है कि इन तीन महीनों में नई दिल्ली के प्रति कश्मीरी जनता की जितनी नाराज़गी बढ़ गई है, उतनी पहले कभी देखने को नहीं मिली थी. कश्मीर में 10 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के वृद्ध तक के दिलों में नई दिल्ली के लिए गुस्सा नफ़रत की हद तक दिख रहा है. हालांकि कश्मीरी जनता राजनीतिक विचारधारा, धार्मिक पंथों और क्षेत्रीय भेदभाव के कारण कई टुकड़ों में बंटी है, लेकिन तीन महीनों के दौरान कश्मीरियों में नई दिल्ली से नाराजगी को लेकर समानता देखने को मिल रही है. केंद्र सरकार को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि अपने हठधर्मी रवैये की वजह से वे आम कश्मीरियों को तो खो ही चुके हैं, साथ ही यहां की मुख्यधारा के राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के भरोसे और सहायता से भी हाथ धोना पड़ा है. नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं के हालिया बयानों का अगर बारीकी से आकलन किया जाए तो पता चलता है कि मौजूदा सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से यह देश इन लोगों का विश्वास खो चुका है. ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 70 साल से कश्मीर और भारत के रिश्तों को मजबूत बनाये रखने में बड़ी भूमिका निभाई है. फारूक अब्दुल्ला ने दो दिन पहले अपने बयान में नई दिल्ली को महाराजा हरी सिंह के एक्सेशन (अधिग्रहण) की याद दिलाते हुए कहा कि अगर नई दिल्ली ने एक्सेशन की शर्तों के साथ छेड़छाड़ नहीं की होती तो आज कश्मीर में ऐसी हालत देखने को नहीं मिलती. उमर अब्दुल्ला पिछले तीन महीने के दौरान अपने बयानों से लगातार भारत की कश्मीर पॉलिसी की आलोचना करते रहे हैं. पीडीपी के नेता और सरकार के प्रवक्ता नईम अख्तर ने अपने एक हालिया बयान में कश्मीर की जनता से शांति बहाल करने की अपील करते हुए कहा कि पीडीपी हालात ठीक होते ही कश्मीर समस्या को हल कराने की कोशिशें तेज करेगी. साथ ही सरकार में अपने सहयोगी भाजपा के साथ तय एजेंडे को अमलीजामा पहनाने की कोशिश करेगी. साफ जाहिर है, जिसने पहली बार जम्मू-कश्मीर में भाजपा को सत्ता तक पहुंचने में मदद की, उसने भी नई दिल्ली के लिए सख्त रवैया अख्तियार करने का इशारा दिया है. वैसे भी पीडीपी के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं है. अगर उसे अपने को राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखना है, तो कश्मीर की जनता की भावनाओं का ख्याल रखना ही होगा. दक्षिण कश्मीर पीडीपी का गढ़ माना जाता है, कश्मीर के इसी इलाके में सबसे ज्यादा हिंसा हुई और सबसे ज्यादा मौतें भी हुईं. यानी, जिन लोगों ने 2014 के असेंबली चुनाव में पीडीपी को वोट दिया था उन्हीं पर सबसे ज्यादा कयामत बरपी. इसके नतीजे में यकीनन पीडीपी की लोकप्रियता और विश्वसनीयता को गहरा धक्का लगा है. जनता को फिर से लुभाने और उनका विश्वास हासिल करने में पीडीपी को अब वर्षों लग जाएंगे. लीडर चाहे जितना भी बड़ा हो, जनता के समर्थन के बिना उसकी कोई अहमियत नहीं होती है. पीडीपी नेतृत्व ये बात अच्छी तरह से जानती है कि नई दिल्ली भी उसकी तभी तक इज्जत करेगा, जब तक उसे अवाम का समर्थन हासिल होगा. आज हालत ये है कि जनता में पीडीपी की साख पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. इसलिए, पीडीपी के नेता जनता को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे उनकी भावनाओं को देखते हुए कश्मीर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे. यही वे हालात हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि नई दिल्ली कश्मीर में अपने सहयोगियों का भी भरोसा खो चुका है. सरकार पिछले तीन महीनों के दौरान सरकारी कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी पर आने के लिए राजी नहीं कर सकी है. यहां के बैंक भी हुर्रियत के प्रोग्राम पर अमल करते हुए सिर्फ हड़ताल में ढील के दौरान ही काम करते हैं. कश्मीर पुलिस में शामिल लोगों के अपने रिश्तेदार भी विरोध-प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं. इस तरह से साफ जाहिर है कि नई दिल्ली ने सुरक्षाबलों के जरिए लगातार कश्मीरी जनता के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया है. उन्हें लगातार घरों के अंदर कैद रहने पर मजबूर किया गया. कश्मीरियों के दिलों में अब नई दिल्ली के लिए नाराजगी के वो बीज बो दिए गए हैं, जिन्हें उखाड़ना अब काफी मुश्किल होगा. मुमकिन है कि आने वाले चंद दिनों में कश्मीर के लोग विरोध-प्रदर्शन बंद कर सामान्य जीवन जीना शुरू कर देंगे. लेकिन, पिछले तीन महीनों के दौरान कश्मीरियों की नई पीढ़ी पूरी तरह से इस आंदोलन के साथ जुड़ चुकी है और मोदी सरकार के सख्त रवैये ने कश्मीरियों की नई पीढ़ी को यह एहसास दिलाया है कि उनका संघर्ष तर्कसंगत है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कश्मीर के लिए गैरसरकारी संवाद अधिक महत्वपूर्ण है

परवेज मजीद

सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल को कश्मीर में व्यापक उदासीनता का सामना करना पड़ा था. इसकी वजह ये रही कि इस प्रतिनिधिमंडल से न सिर्फ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने मिलने से इंकार कर दिया, बल्कि सिविल सोसायटी के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों ने भी इस प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इंकार कर दिया. इसके बाद, यह अंदाजा था कि अब दिल्ली से जो भी कश्मीर की हालात का जायजा लेने और हुर्रियत या सिविल सोसायटी के लोगों से मिलने आएगा, उसे उदासीनता का सामना करना पड़ेगा. लेकिन मुझे तब हैरानी हुई, जब दिल्ली से आए वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय की अगुवाई में तीन सदस्यीय पत्रकारों का एक दल श्रीनगर पहुंचा. इस दल के साथ श्रीनगर के अलग-अलग विचारधारा से जुड़े व्यक्तियों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मुलाकात की. इन पत्रकारों की मुलाकात न सिर्फ राज्य की मुख्यधारा के पार्टियों के लोगों से हुई, बल्कि अलगाववादी हुर्रियत नेता प्रोफेसर अब्दुल गनी बट ने भी अपने घर पर इन पत्रकारों से लंबी बातचीत की. सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हार्डलाइनर समझे जाने वाले हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी ने भी इनसे टेलीफोन (चूंकि, पुलिस ने पत्रकारों को गिलानी के घर पर जाने से रोक दिया था, जबकि गिलानी ने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया था) पर बात की. इसके अलावा, अलगाववादी विचार रखने वाले सिविल सोसायटी के कई लोग और व्यापारी संगठनों के कई प्रतिनिधियों ने भी इन पत्रकारों से मुलाकात की और अपनी बात सामने रखी.

ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हुर्रियत के नेताओं और सिविल सोसायटी के लोगों ने भारत सरकार द्वारा भेजी गई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से बात करने से इंकार कर एक ऐसा माहौल बनाया था, जिसमें दिल्ली से आए किसी भी शख्स के लिए इन लोगों से बातचीत की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई थी. लेकिन संतोष भारतीय और उनके साथ आए पत्रकारों के साथ अलगाववादियों ने जिस गर्मजोशी से बातचीत की वह मेरी राय में एक अहम घटना थी. कुछ राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तियों ने इस प्रतिनिधिमंडल से बात करवाने की इच्छा भी मेरे सामने रखी थी, लेकिन, वक्त की कमी के कारण सभी लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी.

मैंने और अन्य आधा दर्जन पत्रकारों ने संतोष भारतीय की अगुवाई वाले दल के साथ लगभग दो घंटे तक खुलकर बातचीत की. मुझे लगा कि ये लोग खुले दिल के साथ हालात का जायजा लेने आए हैं और पूरी गंभीरता के साथ मामले को समझना चाहते हैं. लिहाजा, संतोष भारतीय, उनके साथी प्रोफेसर अभय दुबे और अशोक वानखेड़े ने बताया कि मुल्क की मीडिया, खास तौर पर टीवी चैनलों ने कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में जो

रवैया अपनाया हुआ है, वो न सिर्फ गलत है, बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी है.

इस संदर्भ में संतोष भारतीय ने प्रधानमंत्री के नाम जो खुला खत लिखा है, वो कश्मीर के मौजूदा हालात और यहां घटित घटनाओं की एक ईमानदाराना और सहानुभूतिपूर्ण आकलन है. उन्होंने जज्बाती अंदाज में प्रधानमंत्री को अवगत कराया है कि कश्मीर की मौजूदा स्थिति के लिए पूरी तरह से पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना गलत है और ये कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान के लिए बौद्धिक दलाली कर रहा है. मेरी राय में संतोष भारतीय की यह चिट्ठी कश्मीर की मौजूदा गमगीन हालात को सही तरीके से दर्शाती है.

उम्मीद है कि संतोष भारतीय और उनके पत्रकार साथियों ने कश्मीर की असल हालत जानने और कश्मीरी लोगों से सीधी बातचीत करने का जो प्रयास किया है, वो आगे भी जारी रहेगा क्योंकि कश्मीर के लिए गैर सरकारी बातचीत किसी भी सरकारी बातचीत से अधिक महत्वपूर्ण है. ■

बीजेपी का साथ बाबा का विकास

चंदन राय

बाबा रामदेव का इन दिनों एकमात्र लक्ष्य है अगले दो-तीन वर्षों में हर्बल उत्पाद व उपभोक्ता वस्तुओं की कारोबारी कंपनी पतंजलि के मुनाफे को 50 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचाना. बाबा इस कंपनी के ब्रांड एंबेसडर हैं और उनके करीबी सहयोगी बालकृष्ण इस कंपनी का संचालन करते हैं. पतंजलि उत्पादों के प्रचार के लिए योग गुरु अपने राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल करने में माहिर हैं. यही कारण है कि कुछ ही वर्षों में यह कंपनी देश व विदेश की नामी-गिरामी कंपनियों को टक्कर देने लगी.

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने हाल में भाजपा शासित राज्यों से केंद्र के गरीब समर्थक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कहा था. भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस सबक का मतलब यह निकाला कि पतंजलि के स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देना ही उनका गरीब समर्थक कार्यक्रम है. तब से पतंजलि के उत्पादों के प्रचार की ऐसी होड़ लगी कि असम, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा से लेकर छत्तीसगढ़ तक सभी भाजपा के मुख्यमंत्रियों का यह एकसूत्रीय अभियान बन गया.

मुनाफे के इस धंधे में भाजपा शासित राज्य बाबा रामदेव के प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देने में जुटे हैं. पतंजलि ट्रस्ट को सस्ती दरों पर या मुफ्त में जमीन मुहैया कराई जा रही है, करों में छूट दी जा रही है और सबकुछ स्वदेशी के नाम पर. पतंजलि के उत्पादों में वृद्धि को बाबा रामदेव 'आर्थिक स्वाधीनता अभियान' का नाम देते हैं. वे अक्सर अपने उत्पादों का प्रचार करने के लिए देशभक्ति व स्वदेशी का सहारा लेते हैं. विज्ञापन में पतंजलि लोगों से अपील करती है कि आप हमारे उत्पादों का उपयोग करें, जैसे करोड़ों देशभक्त कर रहे हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्या स्वदेशी का मतलब केवल पतंजलि के प्रॉडक्ट ही हैं? क्या पतंजलि के उत्पादों का उपयोग नहीं करने वाले लोग देशभक्त नहीं हैं? या हमें अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए पतंजलि के उत्पादों का उपयोग करना होगा. इतना ही नहीं, बाबा रामदेव चाहते हैं कि दूसरी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों की चुनौतियों से निपटने के लिए उनके प्रॉडक्ट को हर राज्य में सरकारी प्रोत्साहन मिले. यही कारण है कि बाबा सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहन देने की नीतियों के कारण 'मेक इन इंडिया' की कई बार सार्वजनिक रूप से खिल्ली भी उड़ा चुके हैं.

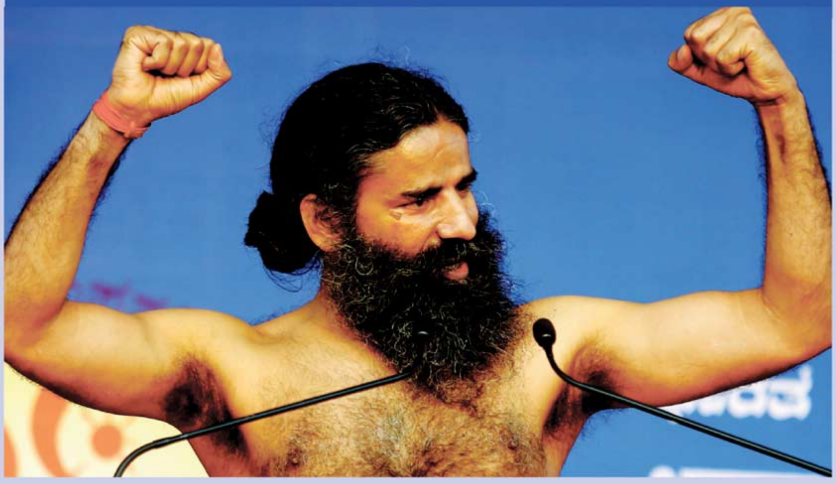

असम में चिरांग जिले में पतंजलि ट्रस्ट को सरकार ने 3800 हेक्टेयर जमीन आवंटित क्या की, क्षेत्र में विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए. कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) से जुड़े अखिल गोगोई कहते हैं कि ट्रस्ट को जमीन देने के पीछे आरएसएस का छिपा राजनैतिक एजेंडा है. असम में भाजपा की सहयोगी पार्टी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट(बीपीएफ) ने पतंजलि ट्रस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए जमीन का आवंटन किया है. दरअसल चिरांग जिले की जो जमीन पतंजलि ट्रस्ट को आवंटित की गई है, वह छोटे किसानों की है, जो बेहद उपजाऊ है. बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हगरामा मोहिलरी ने यह जमीन मुफ्त में पतंजलि ट्रस्ट को सौंप दी है.

योगगुरु बाबा रामदेव के करीबी सहयोगी व पतंजलि ट्रस्ट के प्रमुख आचार्य बालकृष्ण ने जून 2016 में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की थी. उन्होंने मुख्यमंत्री से चिरांग जिले में कृषि व औषधीय पौधों व जड़ी-बूटियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए जमीन की मांग की थी. वे कहते हैं कि असम के चिरांग जिले में गरीब आदिवासियों के जीवन में समृद्धि लाने के लिए हम यहां प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं. गरीब किसान जड़ी-बूटी उगाएंगे और हम इसे मिनीमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद लेंगे. इससे यहां के आदिवासी समाज के लोगों को घर में ही रोजगार उपलब्ध होगा और उन्हें अन्य राज्यों में कमाने के लिए नहीं जाना होगा. लेकिन देखना है कि जिस तरह पतंजलि अपने मुनाफे को चौगुना करने में जुटी है, क्या उसी रफ्तार से पतंजलि से जुड़े किसानों का भी भला होगा?

केएमएसएस के अलावा उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) भी राज्य में पतंजलि ट्रस्ट के विस्तारवादी कदम का विरोध कर रही है. उल्फा चेयरमैन अभिजीत असोम का कहना है कि चिरांग जिले की 3800 हेक्टेयर जमीन भारतीय संविधान के अंतर्गत सिक्सथ शेड्युल्ड एरिया में आती है, जो किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है. उल्फा प्रमुख का कहना है कि 3800 हेक्टेयर में से केवल 400 हेक्टेयर निर्जन है, बाकि जमीन पर लोग बसे हैं. इससे पूर्व 2011 में असम की कांग्रेस सरकार ने पतंजलि को जमीन का आवंटन रद्द कर दिया था.

आसाम के अलावा महाराष्ट्र में भी कंपनी अपने पैर पसारने की तैयारी में है. फरवरी 2016 में महाराष्ट्र सरकार और आचार्य बालकृष्ण ने एक एमओयू पर साइन किया, जिसके तहत ऑरेंज प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए नागपुर में कटोल में 200 एकड़ जमीन और आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए एसईजेड में 450 एकड़ जमीन रियायती दरों पर आवंटित की जानी है. पतंजलि इस प्रोजेक्ट पर 2000 करोड़ रुपए निवेश करेगी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बाबा रामदेव से नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली और विदर्भ क्षेत्र में पाए जाने वाले औषधीय पौधों व जड़ी-बूटियों पर अनुसंधान कार्य का निवेदन किया है, ताकि यहां के गरीब आदिवासियों का जीवन-स्तर ऊंचा उठ सके. वहीं विपक्ष का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सस्ती दरों पर जमीन का आवंटन कर रही है. एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने बताया कि अगर सरकार की मंशा जंगली उत्पादों को बढ़ावा देने की होती, तो उसे अखबारों में विज्ञापन या टेंडर निकालना चाहिए था. स्वदेशी या मेक इन इंडिया के नाम पर सिर्फ पतंजलि को बढ़ावा देकर सरकार अन्य छोटी स्वदेशी कंपनियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है. कांग्रेस के नेता विलास मुत्तेवार कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास नहीं. बीजेपी का साथ, रामदेव बाबा का विकास हो रहा है. सरकार और पूरा प्रशासनिक अमला रामदेव बाबा के प्रोजेक्ट को सफल बनाने में जुटी है. हर भाजपा शासित राज्यों में औने-पौने दामों पर बाबा को जमीन का आवंटन किया जा रहा है.

अब जींस भी स्वदेशी

बाबा रामदेव से पूछा गया कि जींस तो विदेशियों का पहनावा है, फिर आप इसका देशीकरण कैसे करेंगे, इस पर वे कहते हैं कि अब हम जींस का भी स्वदेशीकरण करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने नूडल्स का किया है. यानी हर फायदे के धंधे पर बाबा की पैनी नजर है. वे कहते हैं कि हमें चीजों का भारतीयकरण करना है. युवाओं में जींस की अच्छी मांग है. इसीलिए पतंजलि ने विदेशी ब्रांड्स से टक्कर लेने के लिए स्वदेशी जींस लाने की तैयारी की है.

राशन दुकानों पर पतंजलि

मध्यप्रदेश सरकार पतंजलि के उत्पादों को राशन की दुकानों पर बेचने के लिए जगह उपलब्ध कराने जा रही है. अब इससे बाबा के उत्पादों का प्रचार-प्रसार होगा या राशन दुकानों का कायाकल्प, कहना मुश्किल है. हालांकि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि पतंजलि के उत्पादों की मार्केट में डिमांड है. इस कंपनी के उत्पादों की लोकप्रियता को भुनाकर राशन दुकानों का कायाकल्प किया जा सकता है. वहीं सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग कहते हैं, हम राशन दुकानों का बहुपयोगी इस्तेमाल कर उनको अत्याधुनिक बनाना चाहते हैं. पतंजलि के उत्पाद बेचने से उन्हें फायदा होगा. लेकिन सवाल तो ये है कि सिर्फ पतंजलि के उत्पाद की बिक्री को ही लेकर सरकार परेशान क्यों है? गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में 16,500 राशन की दुकानें हैं. इसके अलावा हजारों सहकारी समितियां हैं. वहीं मध्यप्रदेश सरकार बाबा के फुड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट को जमीन के लिए छूट के साथ-साथ सीएसटी और वैट में भी राहत देने जा रही है. इसके लिए सरकार को निवेश पॉलिसी में छूट के दायरे को भी बढ़ाना पड़ा. यानी अब पतंजलि अगर 500 करोड़ का निवेश करती है, तो उसे 1000 करोड़ रुपए के वैट और सीएसटी में छूट मिलेगी.

बोल बाबा, कितने करोड़

फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार, पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण 16 हजार करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं और सबसे अमीर भारतीयों में 48 वें स्थान पर हैं. वहीं चीन की एक पत्रिका हुरुन का दावा है कि आचार्य बालकृष्ण 25,600 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं. पत्रिका ने बालकृष्ण को सबसे अमीर भारतीयों में 25वें स्थान पर रखा है. पतंजलि की कारोबार वृद्धि दर 153 फीसद रही है. पतंजलि आयुर्वेद में बालकृष्ण की 97 फीसदी हिस्सेदारी है. पांच साल पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनके पास अपना बैंक अकाउंट भी नहीं है. फिर बालकृष्ण कैसे सबसे अमीर भारतीयों में शुमार हो गए?

सीआईएसएफ देगी सुरक्षा

योगगुरु के हरिद्वार स्थित फुड पार्क की सुरक्षा में सीआईएसएफ के सशस्त्र कमांडो तैनात किए गए हैं. यह सुरक्षा देश में अभी तक इन्फोसिस जैसी कुछ बड़ी कंपनियों को ही हासिल है. सीआईएसएफ के महानिदेशक सुरेंद्र सिंह ने जानकारी दी थी कि बल को इस संबंध में केंद्र से निर्देश मिला है. 35 सशस्त्र जवानों को इकाई पर तैनात किया जाएगा. हालांकि इस तैनाती का पूरा खर्चा पतंजलि वहन करेगी. हाल में फुड पार्क पर छिटपुट विरोध को देखते हुए अस्थायी तौर पर जवानों की तैनाती की गई थी.

डीआरडीओ का मिला साथ

देश के प्रमुख रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ ने खाद्य पदार्थों के निर्माण और बिक्री के लिए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के साथ करार किया है. इन खाद्य उत्पादों और हर्बल प्रोडक्ट्स को डीआरडीओ की प्रयोगशाला में विकसित किया गया है. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का कहना है कि सीबकथोर्न एक अनोखा उत्पाद है, जिसके निर्माण और बिक्री के लिए पतंजलि का सहयोग लिया जा रहा है. इसके अलावा डीआरडीओ में विकसित किए गए कई अन्य स्वास्थ्यप्रद उत्पादों के लिए भी पतंजलि ट्रस्ट की मदद ली जाएगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा को मिला शहाबुद्दीन टॉनिक

इर्शादुल हक

सितम्बर के पहले सप्ताह में भाजपा को शहाबुद्दीन की जमानत पर जेल से रिहाई का मामला हाथ लगा. शहाबुद्दीन न सिर्फ भाजपा के लिए अपराध पर राज्य सरकार को घेरने का मुद्दा साबित हुआ, बल्कि उसने इस मुद्दे को संप्रदाय आधारित वैचारिक लड़ाई का हथियार बनाने की कोशिश भी शुरू कर दी. मतलब स्पष्ट था, 'शहाबुद्दीन' जैसे शब्द ने भाजपा के अंदर जीवंत ऊर्जा का संचार कर दिया क्योंकि शहाबुद्दीन भाजपा के लिए अपराध, हिंसा, कानून व्यवस्था और वैचारिक लड़ाई का प्रतीक दिखने लगा. नतीजा यह हुआ कि भाजपा इस मुद्दे पर जबर्दस्त तरीके से आक्रामक हो गई और उसने इसे बड़े पैमाने पर भुनाने की कोशिश शुरू कर दी. वैसे तो इस मुद्दे पर प्रदेश भाजपा की पूरी इकाई ही मैदान में आ गई, लेकिन व्यावहारिक तौर पर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने के लिए सुशील मोदी ने मोर्चा संभाल लिया. हालांकि इस मुद्दे पर उसके पक्ष में कितना जनमत तैयार हुआ इसका सर्वेक्षण आधारित कोई परिणाम तो सामने नहीं आया, लेकिन इतना तो तय है कि 'शहाबुद्दीन' मुद्दे ने भाजपा में उत्साह का संचार जरूर कर दिया है. बीते चार-पांच सप्ताह में सुशील मोदी ने नियमित रूप से अखबारों में भेजे जाने वाले बयान में से 90 प्रतिशत बयान शहाबुद्दीन मुद्दे पर जारी किए. इस मामले में उनके तेवर इतने सख्त थे कि उन्हें काफी आलोचना भी सहनी पड़ी. एक बयान से तो हालत यह हो गयी कि जद यू के दो प्रवक्ताओं- नीरज कुमार और अजय आलोक ने प्रेस कांफ्रेंस कर मोदी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोकने की धमकी तक दे डाली. दरअसल सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि 'जब भाजपा-जद यू गठबंधन में साथ थे तो नीतीश कुमार ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को चुनाव मैदान में उतारने के लिए अपनी पार्टी से टिकट देने का निश्चय कर लिया था. लेकिन भाजपा के दबाव में नीतीश को अपना कदम पीछे हटाना पड़ा था'. मोदी के इस बयान से जद यू तमतमा गया और उसके प्रवक्ता ने मोदी से कहा कि 'या तो वे इस झूठ के लिए माफी मांगें या फिर मानहानि का मुकदमा फेस करने को तैयार रहें'. हालांकि जद यू के इस तेवर के बाद दोनों तरफ से खामोशी छा गयी और यह मुद्दा ज्यादा आगे नहीं बढ़ा. इसके पहले शहाबुद्दीन को लेकर भाजपा ने लालू प्रसाद के बेटे व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप पर भी हमला बोल दिया. वजह यह थी कि तेजप्रताप यादव के साथ एक कथित अपराधी मोहम्मद कैफ की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी. मोहम्मद कैफ वही कथित अपराधी है जिसके साथ कुछ दिन पहले शहाबुद्दीन के साथ फोटो देखे जाने पर हंगामा मचा था. बताया जाता है कि कैफ की तलाश पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में थी. हालांकि मोहम्मद कैफ का नाम राजदेव रंजन हत्या की चार्जशीट में नहीं था. फोटो वायरल होने और भाजपा के दबाव के बाद पुलिस की दबिश बढ़ी और नतीजे में कैफ को अदालत में सरेंडर करना पड़ा. यहां ध्यान देने की बात है कि कैफ ने पत्रकार हत्या मामले में सरेंडर नहीं किया, बल्कि एक अन्य विवाद में कैफ ने आत्मसमर्पण किया. तेजप्रताप यादव के साथ कैफ की तस्वीर वायरल होने के बाद सुशील मोदी ने सवाल दागा कि 'एक अपराधी के साथ फोटो सार्वजनिक होने के बाद यह जाहिर हो गया है कि लालू प्रसाद का परिवार अपराधियों को संरक्षण देता है ऐसे में क्या तेजप्रताप यादव इस्तीफा देंगे'? इस बयान के दूसरे दिन ही सुशील मोदी के लिए उनका बयान गले की हड्डी बन गया. दूसरे दिन तेजप्रताप यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट से अनेक तस्वीरें जारी कर दीं. इन तस्वीरों में कई अपराधियों के साथ सुशील मोदी, विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष नंदकिशोर यादव, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद व मुख्तार अब्बास नकवी की तस्वीरें थीं. इनमें से कुछ तस्वीरों में उस मोहम्मद कैफ की भी तस्वीर थी जिसके साथ शहाबुद्दीन व तेजप्रताप यादव की तस्वीर थी.

शहाबुद्दीन मामले में सियासी पार्टियों के शह-मात का खेल कई पहलुओं के साथ सामने आता रहा. कई मामलों में भाजपा आक्रामक हुई जिसके परिणामस्वरूप कभी सरकार को तो कभी राजद-जदयू को बैकफुट पर आना पड़ा या फिर भाजपा के कड़े तेवर के कारण सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा.

पटना हाई कोर्ट से राजीव रौशन हत्या मामले में जमानत मिलने के बाद सरकार एक हफ्ते तक खामोश रही. जैसे ही राजीव रौशन के पिता चंदा बाबू की तरफ से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, उसके तुरंत बाद राज्य सरकार ने भी इसी मामले में शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कराने के लिए उच्च अदालत में चुनौती दे डाली. गौरतलब है कि भाजपा ने इसके लिए कई बार सरकार को घेरने की कोशिश की थी. लेकिन इस मामले में अदालत में जाने के बावजूद राज्य सरकार को सुशील मोदी ने चैन से नहीं रहने दिया. दूसरे ही दिन मोदी फिर हमलावर हुए और कहा कि बिहार सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए अदालत गई क्योंकि अगर वह अदालत नहीं जाती तो सुप्रीम कोर्ट खुद ब खुद उसे पार्टी बना देती. इतना ही नहीं, जब राज्य सरकार अदालत पहुंच गई तो मोदी ने दूसरा आक्रमण शुरू कर दिया. इस बीच खबर आई कि प्रशांत भूषण के खिलाफ शहाबुद्दीन की पैरवी राम जेठमलानी करेंगे. वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद भी हैं, इसलिए फिर इस मामले को सुशील मोदी ने राजनीतिक रंग देते हुए सरकार पर प्रहार किया और कहा कि क्या राज्य सरकार जेठमलानी का मजबूत जवाब देने के लिए अपने कमजोर वकील को बदलेगी? मोदी के इस सवालिया लहजे के बयान के दूसरे दिन खबर आई कि राज्य सरकार ने अपना वकील बदल दिया है. हालांकि सरकार ने अपना वकील बदलने के पीछे के तर्कों को उजागर नहीं किया, लेकिन भाजपा ने इसे भी अपनी कामयाबी के रूप में लिया.

ऐसा नहीं है कि शहाबुद्दीन के नाम की सियासत में भाजपा का हर दांव सत्तारूढ़ गठबंधन पर बीस ही पड़ा. अनेक बार सुशील मोदी के अति उत्साह ने उन्हें भी बैकफुट पर ला दिया या फिर उन्हें सख्त आलोचना का शिकार होना पड़ा. मोदी ने एक सख्त बयान देते हुए पूरे लालू परिवार को घेरने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि लालू के नक्शे कदम पर ही उनके दोनों बेटे (तेज और तेजस्वी) चल रहे हैं और लालू का परिवार कभी सुधर नहीं सकता. मोदी ने यह भी कहा कि राजद ने आज तक शहाबुद्दीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है. मोदी के इस बयान के बाद तेज और तेजस्वी ने तो प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन राजद ने अपने प्रवक्ता प्रगति मेहता से कहलवाया कि मोदी अब इतने बौखला गये हैं कि वे अपने अनुभव से कम उम्र के लालू प्रसाद के बेटों को भी टारगेट करने लगे हैं. राजद इस बयान से इतना आहत हुआ कि उसने मोदी को 'अफवाह मियां' नाम दे डाला. दूसरी तरफ मोदी के इस बयान पर जद यू के प्रवक्ता संजय सिंह ने भी पलटवार करते हुए कुछ तस्वीरें जारी कर दीं. इन तस्वीरों में सुशील मोदी मोहम्मद बिलाल नामक हत्यारोपी के साथ दिख रहे हैं. बिलाल पर फोटो जर्नलिस्ट इंद्रजीत डे के बेटे पर गोली चलाने का आरोप है. स्वाभाविक है इन तस्वीरों के सार्वजनिक होने के बाद सुशील मोदी कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं थे, सो चुप रहे और शहाबुद्दीन से जुड़े अन्य मुद्दों की तरफ बढ़ चले. ■

feedback@chauthiduniya.com

सैंया भए कोतवाल तब डर काहे का

स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी संस्था के बारे में भेजी फर्जी रिपोर्ट

दरअसल, चंद्रवंशी स्वास्थ्य मंत्री हैं और वही विभाग नर्सिंग कॉलेज के संबंध में रिपोर्ट देता है. मंत्री ने पावर का दुरुपयोग करते हुए सिविल सर्जन से रिपोर्ट बनवाकर केन्द्र सरकार के नर्सिंग काउंसिल को भेज दी, ताकि उनके कॉलेज को मान्यता मिल जाये और नर्सिंग की पढ़ाई शुरू कराकर करोड़ों की कमाई की जा सके.

प्रशान्त शरण

मुख्यमंत्री रघुवर दास का यह बयान अक्षरशः सही प्रतीत हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि झारखंड के राजनेताओं ने केवल लूटने का काम किया है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी भी इस बयान को चरितार्थ करते ही दिख रहे हैं. उन्होंने अपने नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दिलाने के लिए मातहत अधिकारी से फर्जी रिपोर्ट बनवाकर नर्सिंग काउंसिल को भेज दिया, ताकि मान्यता मिलने पर अपने कॉलेज को भारी-भरकम अनुदान दिला सकें. स्वास्थ्य मंत्री की संस्था रामचंद्र चंद्रवंशी वेलफेयर ट्रस्ट ने सोहारी चंद्रवंशी नर्सिंग स्कूल में जीएनएम की पढ़ाई के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल को फर्जी रिपोर्ट भेजी है.

दरअसल, चंद्रवंशी स्वास्थ्य मंत्री हैं और वही विभाग नर्सिंग कॉलेज के संबंध में रिपोर्ट देता है. मंत्री ने पावर का दुरुपयोग करते हुए सिविल सर्जन से रिपोर्ट बनवाकर केन्द्र सरकार के नर्सिंग काउंसिल को भेज दी, ताकि उनके कॉलेज को मान्यता मिल जाये और नर्सिंग की पढ़ाई शुरू कराकर करोड़ों की कमाई की जा सके. झारखंड में नर्सिंग की पढ़ाई की मांग है और एक-एक छात्रों से दो-दो लाख रुपए तक फीस ली जाती है. राज्य सरकार भी कौशल विकास के तहत नर्सिंग का प्रशिक्षण करवाती है और इसका शुल्क खुद वहन करती है. इससे भी इस कॉलेज को अच्छी आय होने की उम्मीद थी. मंत्री ने नियम-कानून को तोड़ते हुए राज्य सरकार के अनुदान से अपने ही कैम्पस में हरिजन आदिवासी छात्रावास बनवाये. इस छात्रावास में रहने वाले आदिवासी छात्रों का खर्च राज्य सरकार उठाती है, पर इन छात्रावासों में सामान्य वर्ग के छात्रों को कमरा/बेड मुहैया कराया गया और उनसे छात्रावास की फीस वसूली गई.

स्वास्थ्य मंत्री जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां नर्सिंग कॉलेज खोलने को लेकर मारामारी मची हुई है. पलामू में रामचंद्र चंद्रवंशी वेलफेयर ट्रस्ट ने पलामू के विश्रामपुर एवं मेदिनीनगर के साथ ही गढ़वा में कई शैक्षणिक संस्थान खोले हैं. सबसे ज्यादा संस्थान विश्रामपुर में एक ही जगह पर ट्रस्ट के परिसर में हैं. यहां पर तकनीकी से लेकर व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान हैं. ट्रस्ट यहां जीएनएम की पढ़ाई भी शुरू करना चाहता है. पलामू प्रमंडल में जीएनएम की पढ़ाई के लिए कोई संस्थान नहीं है. पलामू प्रमंडल में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति की आबादी ज्यादा है. इनकी पढ़ाई के लिए सरकार छात्रवृत्ति भी देती है. हर वर्ष कल्याण विभाग से करोड़ों रुपये इस मद में संस्थान को मिलते हैं. अगर चंद्रवंशी ने यह संस्थान शुरू किया होता तो संस्थान को करोड़ों रुपयों का फायदा होना तय था.

इन सभी आरोपों को राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी सिरे से नकारते हैं. उनका कहना है कि उन्हें बदनाम करने के लिए विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा है. उनका 100 बेड का अस्पताल है, जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, अत्याधुनिक भवन एवं मशीनें हैं, तो उन्हें गलत प्रमाण-पत्र लेने की क्या आवश्यकता है, वे सभी अहर्ताएं पूरी करते हैं.

दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी की संस्था रामचंद्र चंद्रवंशी वेलफेयर ट्रस्ट ने जीएनएम कोर्स 2016-2017 के लिए स्वीकृति मांगी थी. इसके लिए आवेदन नर्सिंग काउंसिल को भेजा गया. आवेदन के साथ पलामू जिला निबंधन पदाधिकारी ने 28 अप्रैल, 2016 को सोहारी चंद्रवंशी अस्पताल के लिए जारी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की कॉपी भी दी. संस्थान की रिपोर्ट पर तत्कालीन सिविल सर्जन सह डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी डॉ. कलानंद मिश्रा ने अपनी मुहर लगा दी, साथ ही पचास हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जिसका नम्बर- 774499, दिनांक-03.03.2016 का बना हुआ नर्सिंग काउंसिल को भेजा गया. रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जीएनएम कॉलेज खोलने के लिए निर्धारित अर्हता में शामिल एक सौ बेड का अस्पताल पलामू जिले के विश्रामपुर नगर परिषद् के नावाडीह में है. इस अस्पताल का नाम सोहारी चंद्रवंशी अस्पताल है, जबकि इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी 'कॉसेट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम' पर है, जबकि सच्चाई यह है कि इस क्षेत्र में कोई अस्पताल ही नहीं है. इसकी पुष्टि विश्रामपुर नगर पंचायत की अध्यक्ष हलीमा बीबी भी करती हैं. उन्होंने कहा कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इस क्षेत्र में कोई अस्पताल भी चलता है.

जब प्रमाण-पत्र जारी करने वाले तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. कलानंद मिश्रा से इस अस्पताल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से इस अस्पताल का निरीक्षण किया था. अस्पताल भवन में अत्याधुनिक उपकरण थे, डॉक्टर थे, सभी चीज देखकर ही नियमानुसार प्रमाण-पत्र दिया गया. मैंने किसी के दबाव में कोई काम नहीं किया है. पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही मैं कोई काम करता हूं. जबकि वर्तमान में वहां पदस्थापित सिविल सर्जन डॉ. बेनेदिक मिंज ने कहा कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इस तरह का कोई प्रमाण-पत्र इस अस्पताल से जारी किया गया है. मुझे इस फाइल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है. वैसे कुछ-कुछ ऊपर से सुनने को मिल रहा है, पर मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं.

विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत, झारखंड विकास मोर्चा सुप्रीमो बाबुलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री द्वारा फर्जी कॉलेज चलाये जाने, फर्जी प्रमाण-पत्र लेने के मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. साथ ही राज्यपाल से स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी को अविलंब बर्खास्त करने की मांग भी की है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कोई झूठी रिपोर्ट नहीं भेजी - चंद्रवंशी

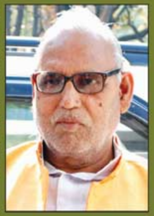

स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं. वे कहते हैं कि मैंने अपनी संस्था के संबंध में कोई भी फर्जी रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं दी है. मंत्री का यह कहना है कि अस्पताल कोई सामान तो है नहीं, जिसे छुपा दिया जाए. यह सब मेरी छवि को धूमिल करने के लिए विरोधियों की चाल है.

जब उनसे यह पूछा गया कि सोहारी चंद्रवंशी अस्पताल कितने बेड का है, तो उन्होंने कहा कि यह 100 बेड का बनाया गया है, इसमें अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं और यहां वरिष्ठ एवं विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इस अस्पताल में आईसीयू एवं आईसीसीयू की सुविधा भी है. इस क्षेत्र का यह सबसे अत्याधुनिक अस्पताल के रूप में जाना जाता है.

वहीं, लोगों का कहना है कि यहां कोई अस्पताल नहीं है. एक मकान में केवल ओपीडी संचालित होता है. जब स्वास्थ्य मंत्री को यह बताया गया कि वहां मेडिकल सामान है, पर अस्पताल नहीं तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उस समय अस्पताल में कोई मरीज नहीं रहा हो. अस्पताल नहीं है, यह आरोप बेबुनियाद है. फर्जी प्रमाण-पत्र मामले में उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई झूठी रिपोर्ट नहीं दी है. प्रमाण-पत्र सिविल सर्जन ने पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ही दी है. कोई भी वरीय अधिकारी झूठी रिपोर्ट क्यों देगा? ■

क्या कहता है नियम?

जीएनएम कॉलेज खोलने के लिए संस्थान के पास अपना एक सौ बेड का अस्पताल होना जरूरी है. अगर उस कॉलेज के पास अपना अस्पताल नहीं है तो उस संस्था का कम से कम तीन ऐसे अस्पताल से संबंधन जरूरी है, जिनके पास 100 बेड का अस्पताल हो. ऐसे संबद्ध अस्पतालों की कॉलेज से दूरी 15 से 30 किलोमीटर जबकि पहाड़ी एवं आदिवासी इलाके में 50 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए. अस्पताल के 75 प्रतिशत बेड पर मरीज भर्ती रहने चाहिए और अस्पताल में सामान्य बेड के साथ ही आईसीयू, आईआईसीयू, माइनर, मेजर ऑपरेशन थियेटर, गाइनिक, बच्चे, हड्डी, डेंटल, आईएनटी, न्यूरो वार्ड सहित अन्य सुविधाएं होनी चाहिए. ■

स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें - विपक्षी दल

मुख्यमंत्री रघुवर दास भले ही भ्रष्टाचार समाप्त करने को लेकर बड़े-बड़े दावे करें, लेकिन विवादों में घिरने के बाद भी अभी तक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी पर न तो कोई कार्रवाई हुई है और न ही मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कोई टिप्पणी की है. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चाईबासा में स्वयं सहायता समूहों को संबोधित करते हुए कहा था कि चौदह साल में झारखंड को यहां के नेताओं और मंत्रियों ने केवल लूटने का काम किया है. झारखंड गठन के 16 साल हुए हैं और लगभग साढ़े तेरह वर्षों तक यहां भाजपा ने ही शासन किया है. ऐसे में जाहिर है कि मुख्यमंत्री अपने दल के नेताओं पर हमला तो कर रहे हैं, पर विवादों में घिरे मंत्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं.

झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा एवं कांग्रेस के आला नेताओं ने कहा कि मंत्री ने गलत रिपोर्ट देकर अपने कॉलेज को करोड़ों रुपये का अनुदान दिलाने का काम किया है. विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कहते हैं, मुख्यमंत्री से लेकर संतरी तक को नहीं छोड़े जाने का दावा करते हैं, पर उनके मंत्री ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे हैं, तो मुख्यमंत्री उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री केवल जनता को गुमराह करने के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हैं? विपक्षी नेताओं ने अविलंब स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग मुख्यमंत्री से की है. ■

दलित उत्पीड़न में भाजपा शासित राज्य आगे

एसआर दारापुरी

राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा हाल में जारी की गई क्राइम इन इंडिया-2015 रिपोर्ट से एक बात फिर उभर कर सामने आई है कि भाजपा शासित राज्य दलित उत्पीड़न के मामले में देश के अन्य राज्यों से काफी आगे हैं. लगभग यही स्थिति वर्ष 2014 की भी थी. वर्तमान में भाजपा शासित राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गोवा और हिमाचल प्रदेश हैं. इनके अलावा कुछ अन्य राज्य जैसे ओड़ीशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार हैं, जहां दलित उत्पीड़न के मामले राष्ट्रीय दर (प्रति एक लाख दलित आबादी पर) से ज्यादा हैं. भाजपा शासित राज्यों व अन्य राज्यों में दलितों पर उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार घटित अपराधों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

दलितों पर 2015 में कुल घटित अपराध: इस वर्ष यह संख्या 45,003 है, जो 2014 में 47,064 से कम है, लेकिन 2013 की संख्या 39,408 से करीब 5,500 अधिक है. इसी प्रकार 2015 में प्रति एक लाख दलित आबादी पर घटित अपराध की राष्ट्रीय दर 22.3 है, जो 2014 में 23.4 से कम है, लेकिन 2013 की 19.6 से 2.7 अधिक है. इससे स्पष्ट है कि यद्यपि 2015 में कुल घटित अपराध में पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ कमी आई है, लेकिन यह 2013 की अपेक्षा काफी बढ़ा है. यह वृद्धि अधिकतर भाजपा शासित राज्यों में अपराध में बढ़ोतरी के कारण ही है.

दलितों पर वर्ष 2015 में घटित अपराधों में से उत्तर प्रदेश- 8,358, राजस्थान- 6,998, बिहार- 6,438, आंध्र प्रदेश- 4,415, मध्य प्रदेश- 4,188, ओड़ीशा- 2,305, महाराष्ट्र- 1,816, तमिलनाडु- 1,782,गुजरात- 1,046, छत्तीसगढ़- 1,028 तथा झारखंड- 752 अपराध घटित हुए हैं. इसी प्रकार 22.3 की राष्ट्रीय दर के विपरीत राजस्थान-57.2, आंध्र प्रदेश- 52.3, गोवा- 51.1, बिहार- 38.9, मध्य प्रदेश- 36.9, ओड़ीशा- 32.1, छत्तीसगढ़- 31.4, तेलंगाना-30.9, गुजरात- 25.7, केरल- 24.7, उत्तर प्रदेश- 20.2 रही है. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भाजपा शासित राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा तथा अन्य राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, ओड़ीशा, तेलंगाना, केरल, उत्तर प्रदेश में दलितों पर घटित अपराध की दर राष्ट्रीय दर से काफी अधिक है.

हत्या: 2015 में दलितों की हत्या के 707 अपराध हुए थे और राष्ट्रीय औसत 0.4 थी. इनमें से मध्य प्रदेश-80, राजस्थान- 71, बिहार- 78, महाराष्ट्र-42, ओड़ीशा-21, गुजरात-17, तमिलनाडु-48, तेलंगाना -17, हरियाणा-22, आंध्र प्रदेश-23 तथा उत्तर प्रदेश-204 थे. हत्या के अपराध की राष्ट्रीय औसत दर 0.4 थी, लेकिन भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश (0.7), राजस्थान (0.6), झारखंड (0.5), बिहार (0.5), उत्तर प्रदेश (0.5), हरियाणा (0.4) और गुजरात में (0.4) थी. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भाजपा शासित राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान में दलित हत्याओं की दर राष्ट्रीय दर से काफी अधिक रही है.

बलात्कार: वर्ष 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर दलित महिलाओं के साथ बलात्कार के कुल मामले 2,326 थे तथा राष्ट्रीय दर 1.2 था. इनमें से मध्य प्रदेश (460), उत्तर प्रदेश (444), राजस्थान (318), महाराष्ट्र (238), ओड़ीशा (129), हरियाणा (107), तेलंगाना (107), आंध्र प्रदेश (104), केरल (99), छत्तीसगढ़ (81), गुजरात (65),तमिलनाडु (43) और बिहार (42) में रहे. इसी प्रकार बलात्कार की राष्ट्रीय दर 1.2 थी, जबकि इसके मुकाबले मध्य प्रदेश (4.1), केरल (3.3), राजस्थान (2.6), छत्तीसगढ़ (2.5), हरियाणा (2.1), तेलंगाना (2.0), महाराष्ट्र (1.8), ओड़ीशा (1.8), गुजरात (1.6) और आंध्र प्रदेश (1.2) रही. इन आंकड़ों से भी स्पष्ट है कि दलित महिलाओं पर बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात में अपराध दर राष्ट्रीय दर से काफी अधिक रहे हैं.

दलित महिलाओं पर शील भंग के लिए हमला: 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर इन मामलों में कुल 2,800 अपराध घटित हुए तथा राष्ट्रीय दर 1.4 रहे. इनमें से मध्य प्रदेश- 777, उत्तर प्रदेश-756, महाराष्ट्र- 353, आंध्र प्रदेश-153, ओड़ीशा-155, हरियाणा-109, राजस्थान-107, कर्नाटक-60 और गुजरात-51 थे. इस प्रकार के अपराध की राष्ट्रीय दर 1.4 थी, जबकि यह मध्य प्रदेश-6.9, महाराष्ट्र-2.7, हरियाणा-2.1, केरल-2.2, ओड़ीशा-2.2, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना- 1.8, उत्तर प्रदेश-1.8 रही. इन आंकड़ों से भी स्पष्ट है कि भाजपा शासित राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा में दलितों महिलाओं पर शीलभंग के लिए हमले के अपराध की दर राष्ट्रीय दर से काफी ऊंची रही है.

दलित महिलाओं का अपहरण: वर्ष 2015 में इस प्रकार के कुल 687 अपराध हुए तथा राष्ट्रीय दर 0.3 रही. इस प्रकृति के अपराध उत्तर प्रदेश-415, राजस्थान-62, मध्यप्रदेश-43, गुजरात-37, महाराष्ट्र-34, हरियाणा-29, ओड़ीशा-22 और आंध्र प्रदेश- 10 थे. इसकी राज्यवार दर उत्तर प्रदेश-1.0, गुजरात- 0.9, राजस्थान-0.5, मध्य प्रदेश-0.4, महाराष्ट्र और ओड़ीशा-0.3 रही. इस विश्लेषण से भी स्पष्ट है कि इस अपराध में भी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की दर राष्ट्रीय दर से काफी ऊपर रही.

दलित महिलाओं का विवाह के लिए अपहरण: 2015 में पूरे देश में इस प्रकार के 455 प्रकरण हुए तथा राष्ट्रीय दर 0.2 रही. इनमें उत्तर प्रदेश-338, राजस्थान-28, गुजरात-20, मध्य प्रदेश-18, महाराष्ट्र-18 तथा मध्य प्रदेश-18 घटित हुए. इसकी राज्यवार दर उत्तर प्रदेश-0.8, गुजरात-0.5, मध्य प्रदेश और राजस्थान-0.2 रही. इससे स्पष्ट है कि इस अपराध में भी उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान, गुजरात और राजस्थान की दर राष्ट्रीय दर से ऊंची रही.

आगजनी: 2015 में आगजनी के कुल 179 मामले हुए तथा राष्ट्रीय दर 0.1 रही. इसमें से छत्तीसगढ़-43, उत्तर प्रदेश-30, मध्य प्रदेश-21, राजस्थान-21, तमिलनाडु-14, ओड़ीशा-15 तथा महाराष्ट्र-11 अपराध घटित हुए. उन्हीं छत्तीसगढ़-0.3, मध्य प्रदेश-0.2, राजस्थान-0.2, गुजरात- 0.2 की दर रही. इस से भी स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में आगजनी के अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही.

एससी/एसटी एक्ट के अपराध: इस एक्ट के अंतर्गत वर्ष 2005 में कुल 6,005 अपराध पंजीकृत हुए और राष्ट्रीय दर 3.0 रही. इनमें से मध्य प्रदेश-1, महाराष्ट्र-290, हिमाचल प्रदेश-74, गुजरात-190, हरियाणा-19, ओड़ीशा-1, राजस्थान-92 तथा तेलंगाना-358 पंजीकृत हुए. इस अपराध के अंतर्गत भाजपा शासित राज्यों में कम आंकड़ों का कारण इन राज्यों में इस अपराध का कम होना नहीं, बल्कि इस एक्ट का प्रयोग नहीं किया जाना है.

एससी/एसटी एक्ट का प्रयोग न किया जाना: उपरोक्त रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों से यह तथ्य उभर कर आया है कि लगभग सभी भाजपा शासित राज्यों में एससी/एसटी एक्ट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जिस कारण दलितों पर अत्याचार के मामले सामान्य कानून के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं. इससे दलितों को अत्याचार के मामलों में न तो कोई मुआवजा मिलता है और न ही दोषियों को कड़ी सजा. इन राज्यों में 6,009 आईपीसी अपराध के मामलों में इस एक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है. राज्यवार स्थिति यह है: आंध्र प्रदेश -2050, राजस्थान-1,040, छत्तीसगढ़-790, मध्य प्रदेश-638, ओड़ीशा-482, तेलंगाना-357, हरियाणा- 322, कर्नाटक-131. इन आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि भाजपा शासित राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओड़ीशा और कर्नाटक में भी एससी/एसटी एक्ट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जो दलितों के साथ बड़ा अन्याय और धोखा है.

अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार: 2015 में इस वर्ग पर 10,914 अपराध घटित हुए और अपराध की राष्ट्रीय दर 10.5 रही जो 2014 के कुल अपराध 11, 415 और राष्ट्रीय दर 11.0 से तो कुछ कम है, लेकिन 2013 के 6,793 अपराध और राष्ट्रीय दर 6.5 से काफी अधिक है. 2015 के कुल अपराध में से राजस्थान -3,207, मध्य प्रदेश-1,531, छत्तीसगढ़-1,518, ओड़ीशा-1,307, आंध्र प्रदेश-719, तेलंगाना-698, महाराष्ट्र-483, गुजरात-256 और झारखंड में 269 अपराध घटित हुए. इनकी राज्यवार दर राजस्थान-34.7, आंध्र प्रदेश-27.3, तेलंगाना-21.2, छत्तीसगढ़-19.4 और ओड़ीशा- 14.5 है जो राष्ट्रीय दर से काफी अधिक है.

उक्त रिपोर्ट के अनुसार 2015 में अनुसूचित जनजातियों पर इस वर्ष कुल 10,914 अपराध घटित हुए तथा अपराध की राष्ट्रीय दर 10.5 रही. इनमें से राजस्थान- 3,207, मध्य प्रदेश- 1,531, छत्तीसगढ़- 1,518, ओड़ीशा- 1,387, आंध्र प्रदेश- 719, तेलंगाना- 698 में अपराध घटित हुए. वहीं, केरल- 36.3, राजस्थान- 34.7, आंध्र प्रदेश- 27.3, तेलंगाना- 21.2, छत्तीसगढ़- 19.4, ओड़ीशा- 14.5, मध्य प्रदेश- 10.0 की दर रही. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि केरल, ओड़ीशा, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना को छोड़कर शेष भाजपा शासित राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश में अपराध की दर राष्ट्रीय दर से काफी ऊंची रही है.

हत्या: 2015 में अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध हत्या के 144 अपराध घटित हुए जिनमें से मध्य प्रदेश- 50, राजस्थान- 22, ओड़ीशा- 14, गुजरात- 13, महाराष्ट्र- 11 घटित हुए. इससे भी स्पष्ट है कि इस वर्ग पर भाजपा शासित राज्यों में हत्या के अधिक अपराध हुए.

बलात्कार: उक्त अवधि में पूरे देश में अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं पर बलात्कार के 952 अपराध घटित हुए और इसकी राष्ट्रीय दर 0.9 रही. इनमें से मध्य प्रदेश- 359, छत्तीसगढ़- 138, महाराष्ट्र- 99, ओड़ीशा- 94, राजस्थान- 80, केरल- 47, गुजरात और तेलंगाना- 44, तथा आंध्र प्रदेश- 21 में अपराध हुए. वहीं केरल- 9.7, मध्य प्रदेश- 2.3, छत्तीसगढ़- 1.8, तेलंगाना- 1.3, ओड़ीशा- 1.0, महाराष्ट्र- 0.9 की दर रही. इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि केरल को छोड़ कर शेष भाजपा शासित राज्यों में बलात्कार की दर राष्ट्रीय दर से काफी अधिक रही है.

महिलाओं पर शीलभंग के लिए हमले: 2015 में अनुसूचित जनजातियों पर इन मामलों में 818 अपराध घटित हुए तथा राष्ट्रीय दर 0.8 रही. इनमें से मध्य प्रदेश- 378, महाराष्ट्र- 146, छत्तीसगढ़- 86, ओड़ीशा- 65, तेलंगाना- 32 तथा आंध्र प्रदेश- 29 में अपराध घटित हुए. दर की दृष्टि से केरल- 3.9, मध्य प्रदेश- 2.5, महाराष्ट्र- 1.4, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश- 1.1, तेलंगाना- 1.0 की रही. इन आंकड़ों से भी स्पष्ट है कि केरल को छोड़ कर शेष सभी भाजपा शासित राज्यों में इस वर्ग पर सब से अधिक अपराध घटित हुए हैं.

एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत अपराध: 2015 में पूरे देश में अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के संबंध में इस एक्ट के अंतर्गत 6,275 अपराध पंजीकृत हुए. इनमें से राजस्थान- 1,409, मध्य प्रदेश- 1,358, ओड़ीशा- 691, महाराष्ट्र- 481, तेलंगाना और कर्नाटक- 386, छत्तीसगढ़- 373, आंध्र प्रदेश- 362 और गुजरात- 248, केरल- 165 घटित हुए. दर की दृष्टि से केरल- 34.0, राजस्थान- 15.3, आंध्र प्रदेश- 13.8, तेलंगाना- 11.7, मध्य प्रदेश- 8.9, ओड़ीशा- 7.2 की रही. इस विश्लेषण से भी स्पष्ट है कि केरल को छोड़ कर भाजपा शासित राज्य इस अपराध में भी अन्य से आगे हैं.

एससी/एसटी एक्ट का लागू न किया जाना: 2015 के दौरान अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध आईपीसी के 4203 मामले रहे हैं, जिनमें इस एक्ट का प्रयोग ही नहीं किया गया. इनमें से राजस्थान- 1,746, छत्तीसगढ़- 816, ओड़ीशा- 696, आंध्र प्रदेश- 352, तेलंगाना- 302 तथा मध्य प्रदेश- 171 में घटित हुए. दर की दृष्टि से राजस्थान- 18.9, आंध्र प्रदेश- 13.4, छत्तीसगढ़- 10.4, तेलंगाना- 9.2, ओड़ीशा- 7.3 रही. इन आंकड़ों से भी स्पष्ट है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओड़ीशा को छोड़ कर शेष भाजपा शासित राज्यों में एससी/एसटी एक्ट को लागू न करने की दर काफी ऊंची है.

दलित उत्पीड़न के मामलों में न्यायालय से सज़ा की दर: 2015 में दलित उत्पीड़न के मामलों में न्यायालय द्वारा निस्तारण के अनुसार इस वर्ष में 17,012 मामले निस्तारित किए गए, जिनमें से केवल 4,702 मामलों में ही सजा हुई तथा 12,310 मामलों में आरोपी दोष मुक्त हो गए. इस प्रकार सजा होने की दर केवल 27.6 प्रतिशत रही. इसी प्रकार उक्त अवधि में न्यायालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के 4,894 मामले निस्तारित किए गए जिनमें से केवल 1,349 मामलों में सजा हुई और 3,545 मामलों में आरोपी रिहा हो गए. इस मामले में भी सजा की दर केवल 27.6 ही रही. इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को उत्पीड़न के मामलों में न्याय दिलाने के लिए सरकारों की क्या प्रतिबद्धता है?

वर्ष 2015 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के मामलों के आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि भाजपा शासित राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा में इन वर्गों पर अत्याचार के मामले आंध्र प्रदेश, ओड़ीशा, तेलंगाना, कर्नाटक को छोड़ कर बहुत अधिक हैं. इन राज्यों में न तो एससी/एसटी एक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है और न ही दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. इन राज्यों में 2013 के मुकाबले में अत्याचार के मामलों में बहुत वृद्धि हुई है. यह भी सर्वविदित है कि सरकारी आंकड़ों में दिखाया गया अपराध वास्तविक आंकड़ों का एक छोटा हिस्सा होता है. कुल घटित अपराध तो इससे कहीं अधिक होते हैं. मोदी सरकार ने एकतरफ तो एससी/एसटी एक्ट में संशोधन करने का दिखावा किया है, दूसरी तरफ इस एक्ट को भाजपा शासित तथा कुछ अन्य राज्यों में लागू ही नहीं किया जा रहा है. गुजरात का दलित आक्रोश इसी की परिणति है. इन परिस्थितियों में दलितों को इस संबंध में गंभीरता से मनन करना चाहिए और दलित नेताओं और भाजपा शासित तथा अन्य राज्यों की सरकारों के विरुद्ध एससी/एसटी एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए जनांदोलन करना चाहिए. ■

(लेखक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं)

जैविक खेती

और कारवां बढ़ता ही जा रहा है...

शफीक आलम

एक कहावत है कि कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है, जो आसान न हो जाए. बस किसी मुश्किल को आसान करने के लिए पक्के इरादे और लगन की जरूरत है. आज से बीस साल पहले राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में एमआर मोरारका-जीडीसी रूरल रिसर्च फाउंडेशन ने एक मुश्किल काम अपने जिम्मे लिया था. ये काम था किसानों को रासायनिक खाद और पेस्टीसाइड रहित ऑर्गेनिक खेती के लिए तैयार करना. काम मुश्किल जरूर था, क्योंकि एक तो भारत में ऑर्गेनिक कृषि से हासिल उपज के लिए बाज़ार नहीं था, दूसरे ऑर्गेनिक खेती में शुरुआती कुछ वर्षों के दौरान उपज भी कम मिलने वाली थी. बहरहाल बड़ी मुश्किल से कुछ किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए मोरारका फाउंडेशन ने राजी किया. इलाके में ऑर्गेनिक खेती शुरू हुई और किसानों की सफलता देख धीरे-धीरे दूसरे लोग भी इससे जुड़ते गए. अब तो आलम ये है कि उनकी संख्या जो कभी हजारों में हुआ करती थी, अब लाखों में चली गई है. फाउंडेशन आज देश के कई राज्यों में ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान कर रहा है. यह बात गौरतलब है कि सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसे पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक राज्य घोषित किया गया है. सिक्किम के पूर्ण ऑर्गेनिक राज्य बनाने में मोरारका फाउंडेशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

देश में बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक खेती की जरूरत इसलिए है क्योंकि आज हर तरफ मुनाफाखोरी और जालसाजी का बाज़ार गर्म है. इस मुनाफाखोरी और जालसाजी की होड़ में खाने-पीने की चीज़ें भी शामिल हैं. आये दिन ऐसी ख़बरें देखने और पढ़ने को मिल जाती हैं कि फलों और सब्जियों को कैसे अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से कृत्रिम तरीके से तैयार किया जा रहा है. साथ ही दूध में कैसे मिलावट हो रही है? इस मिलावट के साथ, जो फसलों में रसायन और कीटनाशकों का प्रयोग होता है, वह भी सेहत के लिए अधिक नुकसानदेह है. हम अनजाने तौर पर खाने के साथ पेस्टीसाइड का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. अमेरिका के वाशिंगटन स्थित सेंटर फॉर एकोगेंटिक्स एंड एनवायर्नमेंटल हेल्थ के एक अध्ययन के मुताबिक लंबे समय तक पेस्टीसाइड के संपर्क में रहने या पेस्टिसाइड युक्त खाना खाने से सांस की परेशानी, याद्दाश्त की समस्या, चर्म रोग, मनोरोग, गर्भपात, कैंसर आदि बीमारियां हो सकती हैं. हालांकि किसी अध्ययन में ये साबित नहीं हुआ है कि ऑर्गेनिक पद्धति से की गई खेती से हासिल अनाज, फल और सब्जी आम तरीके से उगाये गए अनाज, फलों और सब्जियों से अधिक पौष्टिक होते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि रसायन और पेस्टीसाइड का उपयोग नहीं होने के कारण ऑर्गेनिक पद्धति से उपजाए गए अनाज या सब्जियों का उपयोग करने से उपरोक्त बीमारियों की आशंका कम हो जाती है.

लिहाज़ा, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसानों के हितों के लिए हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ने वाले संगठन किसान मंच से जुड़े देश के विभिन्न क्षेत्रों से आये किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंच के अध्यक्ष विनोद सिंह की अगुआई में शेखावटी का दौरा किया. यह प्रतिनिधिमंडल इस क्षेत्र में मोरारका फाउंडेशन के तत्वावधान में कामयाबी के साथ चल रही ऑर्गेनिक खेती को देखने और अपने इलाकों में ऑर्गेनिक खेती की संभावनाएं तलाशने यहां आया था. इन किसानों ने जहां एक तरफ नवलगढ़ और शेखावटी क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती कर रहे किसानों से मुलाक़ात कर खेती में इस्तेमाल हो रहे तकनीक का प्रत्यक्ष जायजा लिया, वहीं मोरारका फाउंडेशन के कृषि विशेषज्ञों से भी लंबी मुलाकात की और ऑर्गेनिक खेती के अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा की. दरअसल इन किसानों में से कई ऐसे थे जिन्होंने क्षेत्र में अपने इस्तेमाल के लिए रासायनिक खाद रहित खेती की शुरुआत की है.

सीधी (मध्य प्रदेश) के युवा किसान रणजीत सिंह चौहान, जो एमबीए हैं और किसान मंच से जुड़े हैं, अपनी यात्रा के बारे में बताते है कि मैं यहां ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी लेने के लिए आया था. हमारे यहां खेती में पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. मैं 150 एकड़ ज़मीन पर खेती करता हूं. अभी तक हम केमिकल फ़र्टिलाइज़र ही इस्तेमाल करते रहे हैं और इसलिए मेरी इच्छा ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानने की थी. यहां का अनुभव बहुत अच्छा रहा. आदमी घर पर ही कंपोस्ट बना सकता है और उसी से कीटनाशक बनाकर खेती कर सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है. मैंने यहां जो चीज़ें सीखी हैं, उसे अपने यहां जाकर करूंगा और धीरे-धीरे ऑर्गेनिक खेती से अनाज पैदा कर बाजार में उतारने की कोशिश करूंगा.

नागपुर से आए प्रताप गोस्वामी, जो किसान मंच की स्थापना से जुड़े हैं और पेशे से इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट (बम्बू प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग) हैं, बताते हैं कि विदर्भ के किसानों की हालत काफी दयनीय है. वहां ज़्यादातर किसान बुरे हालत में जीने को मजबूर हैं. यह कपास का बेल्ट है. 2002 के पहले कपास के बेल्ट में बहुत खुशहाली थी. एक ज़माना ऐसा था, जब एक तोला सोना और एक क्विंटल कपास की कीमत एक थी लेकिन आज कपास 3000 रुपए क्विंटल है और सोना 30000 रुपए के आस-पास है. कपास में बीटी कॉटन आने के बाद ये सब समस्याएं शुरू हुई. विदर्भ के 11 जिलों में से 6 कपास उत्पादन के लिए जाने जाते हैं. यहां रासायनिक खाद और कीटनाशकों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, जिसकी वजह से किसानों की लागत काफी बढ़ जाती है और सिंचाई की कमी होने से किसान बहुत तकलीफ में हैं. यहां मैंने किसानों को ड्रिप पद्धति से सिंचाई करते देखा, इससे निश्चित तौर पर पानी की खपत कम होगी. यहां के जैविक मॉडल और खाद के बारे में भी बेहतर जानकारी मिली. यहां पशुओं के गोबर और घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से कीटनाशक तैयार किए जाते हैं. ये सब नई चीज़ें सीखने को मिली हैं और इन चीज़ों को हम विदर्भ में भी किसानों को समझाएंगे. वहां के किसान भी इस तकनीक का फायदा उठा कर खुशहाल हो सकते हैं और अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं. हम मोरारका फाउंडेशन के माध्यम से वहां इन चीज़ों का प्रसार करेंगे. आर्थिक लाभ होने के कारण वहां के किसान इसका जल्द अनुसरण करेंगे.

नागपुर जिला किसान मंच से जुडे उल्लास धापाडेकर कहते हैं कि मैं पिछले कुछ वर्षों से खेती कर रहा हूं. इसमें मेरा तजुर्बा है कि रासायनिक खाद और कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों का एक चेन है. मुझे लगता है कि जो खाद हम इस्तेमाल करते हैं, वह फसल में मीठापन पैदा करता है,

जिसके कारण कीट फसलों की तरफ आकर्षित होते हैं. इसकी वजह से खाद के साथ-साथ पेस्टिसाइड की भी ज्यादा खपत होती है. इसकी वजह से किसान को फसल की कम कीमत मिल पाती है. मैंने देखा कि जो लोग यहां खेती कर रहे हैं, जैसे गाय के गोबर से खाद बना रहे हैं, वो काबिले तारीफ है और यह पेस्टिसाइड का तोड़ भी है. हम लोग धीरे-धीरे ऑर्गेनिक खेती की ओर आने की कोशिश करेंगे.

औरंगाबाद, महाराष्ट्र के धनंजय पाटील बताते हैं कि हमारे यहां प्याज की खेती अब किसानों के लिए नुकसान का कारण बन रही है. आज हमारा प्याज 50 पैसे किलो के हिसाब से बिक रहा है. गन्ने की खेती भी अब किसानों के लिए फायदे का सौदा नहीं रही है. कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार की उदासीनता को देखकर ऐसा लगता है कि अब किसानों को खुद ही वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल कर खेती में सुधार लाना होगा. हम किसान मंच के तत्वावधान में इसी नीयत से यहां नवलगढ़ में ऑर्गेनिक खेती देखने आये थे. यहां मैंने देखा कि यहां पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके का इस्तेमाल कर बाजरा का उत्पादन किया जाता है जो डेयरी फार्मिंग के लिए अच्छा है.

किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सिंह कहते हैं कि किसान मंच, जिसके संरक्षक कमल मोरारका जी हैं, किसान मंच और मोरारका फाउंडेशन दोनों एक ही सिलसिले की कड़ी हैं. यहां देश के कोने-कोने से जो भी किसान आए हैं वे अपने क्षेत्र में जाकर वहां ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करने जा रहे हैं. किसान मंच पूरे देश में मोरारका फाउंडेशन के साथ किसानों को ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग देगा. यह किसानों के एक समूह को सफलतापूर्वक ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी देने का पहला चरण था. आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए किसान मंच और मोरारका फाउंडेशन किसानों के बीच जाकर ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग देगा और किसानों को खेती करने के लिए प्रेरित करेगा. किसान मंच केवल किसानों की समस्याओं के लिए आंदोलन ही नहीं करता है, बल्कि किसानों की दशा और दिशा बदलने के लिए भी काम करता है.

किसान मंच की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरियाणा की निशा वर्मा बताती हैं कि किसान ऑर्गेनिक खेती के लिए तैयार तो हैं लेकिन उन्हें इसकी जानकरी नहीं है. मेरा यहां आने का मक़सद सिर्फ यह था कि मैं अपने क्षेत्र में जाकर वहां के किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित कर सकूं. हम देख रहे हैं कि लंबे समय तक यूरिया के इस्तेमाल से हमारी खेती चौपट हो रही है. यहां मैंने देखा कि किसान कम लागत पर ही खाद तैयार कर सकते हैं और हम पुरातन खेती की तरफ एक बार फिर लौट सकते हैं.

उम्मीद है कि एक दिन ऐसा होगा जब किसी किसान को अपने ऑर्गेनिक खेती को सर्टिफाई या सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी और अधिकतर किसान अपने खेतों में ज़हर डालना बंद कर देंगे. मोरारका फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक मुकेश गुप्ता ने किसानों से कुछ रोचक जानकारियां साझा की. रासायनिक खाद के इस्तेमाल के बारे में वे कहते हैं कि रासायनिक खाद का इजाद खेती के लिए नहीं किया गया था. द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान गिराए गए बमों में नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता था. युद्ध समाप्ति के बाद जब किसानों ने अपने खेत बोए तो जहां बम गिरे थे वहां की फसल सामान्य से अच्छी हुई. इसके बाद यूरिया के रूप में नाइट्रोजन का इस्तेमाल होने लगा. पेस्टीसाइड की कहानी भी कुछ ऐसी ही है.

ऑर्गेनिक खेती के अलावा मोरारका फाउंडेशन किसानों, छात्रों व महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी चला रहा है. एमआर मोरारका-जीडीसी रूरल रिसर्च फाउंडेशन किसानों को न सिर्फ जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, बल्कि उनके लिए बाज़ार की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सैकडों स्वयं सहायता समूह, सांझा रसोई गैस योजना चलाई जा रही है. किसान ऑर्गेनिक नर्सरी, डेयरी के अलावा राजस्थान जैसे क्षेत्र में मत्स्य पालन भी कर रहे हैं. फाउंडेशन ने छात्रों के लिए ई-लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई है. मोरारका फाउंडेशन ऑर्गेनिक खेती को राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के साथ-साथ देश के कई अन्य राज्यों में भी फ़ैलाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

> पाकिस्तान का लगातार यथास्थिति को बदलने की कोशिश शिमला समझौते का खुला उल्लंघन है. वे एक ऐसे समझौते का सम्मान नहीं करना चाहते हैं जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी ने बड़ी समझदारी के साथ किया था. पाकिस्तान की सेना इसे लेकर कभी खुश नहीं थी. यह सही है कि यह समझौता उस समय हुआ था जब पाकिस्तान सेना को पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और बांग्लादेश वजूद में आया था. लिहाज़ा सेना का उस समझौते में कोई दखल नहीं था. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब समय बदल गया है तो सेना उस समझौते का उल्लंघन करना शुरू कर दे. यह हर अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ़ है.

पाकिस्तान आतंक पैदा करने का कारखाना है

भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कुछ ठिकानों को निशाना बनाने के बाद देश में जश्न का माहौल है. जब आप यह घोषणा करें कि आप ने दुश्मन को तमाचा मारा है, तो लोगों का खुश होना स्वाभाविक है. बहरहाल, इस विषय में एहतियात से काम लेना चाहिए. सेना अपने सामान्य ऑपरेशन के दौरान ऐसी कार्रवाई करती है, लेकिन यह घोषणा और बहस करने जैसी बात नहीं है. यह ठीक है कि हाल में हमें पठानकोट और उड़ी में दो हमलों का सामना करना पड़ा. बदकिस्मती से यह बात सही है कि दोनों हमलों के लिए पाकिस्तान दोषी था, लेकिन हमारी तरफ से भी चूक हुई है. उड़ी में (जो अभी की घटना है) कैसे कोई हमारी सीमा के इतने अंदर आकर हमारे कैंप में घुस सकता है? हमारी सुरक्षा का क्या? जैसा कि मुझे बताया गया कि उड़ी कंपाउंड को बिजली के तारों से घेरा गया है और जो कोई उन तारों को छुएगा, तो उसे बिजली के झटके लग जायेंगे. ज़ाहिर है किसी ने उन तारों की बिजली काटी होगी. लिहाज़ा हमारी तरफ से कुछ न कुछ चूक हुई है.

दूसरे यह कि इस तरह के कैंप में आप केवल एक लेयर (परत) की सुरक्षा कैसे रख सकते हैं? इसमें कम से कम दो-तीन परत वाली सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए. उन्होंने पहली लेयर को तोड़ा और सीधे आकर हमें मार दिया. हमें आत्मविश्लेषण की जरूरत है और एक बार फिर यह काम सेना को करना है. यह आम बहस का विषय नहीं है. जवाबी कार्रवाई और किसी अन्य तरह की कार्रवाई को भी सेना के ऊपर छोड़ देना चाहिए. यह बिलकुल ठीक है कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट की सुरक्षा समिति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सब अपना काम करते रहें, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि जश्न मनाना और इस तरह से घोषणा करना ठीक है. शायद सरकार स्वयं कुछ हतोत्साहित महसूस कर रही होगी और अपने समर्थकों में जोश भरने के लिए यह घोषणा की होगी. हमें आशा करनी चाहिए कि इस संबंध में उचित रणनीति तैयार की जाएगी और पाकिस्तान भी यह समझ जाएगा कि यदि वह भारत में ऐसी गतिविधियां करेगा, तो यह उसके लिए आग के साथ खेलने जैसा होगा. मुझे ख़ुशी है कि अमेरिका और दूसरे देशों ने यह समझ लिया है कि यह लड़ाई कश्मीर के लिए नहीं है बल्कि यह साफ़ तौर पर आतंकवाद है और अब यह किसी तरह से नहीं चलेगा.

यह ज़रूर कहना चाहिए कि सुषमा स्वराज ने संयुक्तराष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में अच्छा भाषण दिया, हालांकि उन्हें पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए था. मुझे मालूम नहीं, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया. उन्होंने केवल एक देश कहा. मनमोहन सिंह ने पहले संयुक्तराष्ट्र संघ में पाकिस्तान का नाम लिया है. यह साफ़-साफ़ कहने में कोई नुकसान नहीं है कि क्षेत्रीय विवाद और उसका हल एक चीज़ है और अपने बगल में आतंक पैदा करने का स्थायी कारखाना बिल्कुल अलग चीज़ है. आतंक पैदा करने का कारखाना सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं है, दूसरे देशों को भी पाकिस्तान के इस कारखाने को नष्ट करने के लिए साथ आना चाहिए. यह समय की आवश्यकता है.

कश्मीर विवाद एक छोटा मामला है. शिमला समझौता इसके समाधान के लिए काफी है. अगर वे शिमला समझौते का पालन करते तो कश्मीर समस्या को हवा देने या उछालने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती. समझौता यह है कि जब तक बातचीत से समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक कश्मीर पर यथास्थिति बनी रहेगी. इसका मतलब यह है कि नियंत्रण रेखा का वैसे ही सम्मान होगा, जैसा अंतरराष्ट्रीय सीमा का होता है. पाकिस्तान का लगातार यथास्थिति को बदलने की कोशिश शिमला समझौते का खुला उल्लंघन है. वे एक ऐसे समझौते का सम्मान नहीं करना चाहते हैं जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी ने बड़ी समझदारी के साथ किया था. पाकिस्तान की सेना इसे लेकर कभी खुश नहीं थी. यह सही है कि यह समझौता उस समय हुआ था जब पाकिस्तान सेना को पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और बांग्लादेश वजूद में आया था. लिहाज़ा सेना का उस समझौते में कोई दखल नहीं था. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब समय बदल गया है तो सेना उस समझौते का उल्लंघन करना शुरू कर दे. यह हर अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ़ है. पिछली सरकारों द्वारा शिमला समझौते का उल्लेख संयुक्तराष्ट्र संघ और दूसरे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर क्यों नहीं किया गया, यह मेरी समझ में नहीं आता. शिमला समझौते का पालन होना चाहिए और अगर दोनों देशों द्वारा शिमला समझौते का पालन होता है तो कश्मीर समस्या किसी लड़ाई-झगड़े का कारण नहीं बनेगी. अगर कोई आखिरी समझौता हो जाता है, तो ठीक है, नहीं तो शिमला समझौता हालात से निपटने के लिए काफी है. इससे दोनों देशों के बीच कभी युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी.

दूसरे मामले विरोध-प्रदर्शन के हैं. पहले गुजरात में पटेल आंदोलन हुआ, अब महाराष्ट्र में मराठों का विरोध-प्रदर्शन चल रहा है. गुजरात के पटेल और महाराष्ट्र के मराठा न तो पिछड़े वर्ग से हैं और न ही दबे-कुचले हैं. दरअसल वे ऊंची जातियों से संबंधित हैं. महाराष्ट्र में अलग-अलग पार्टियों का मराठा नेतृत्व है. चूंकि देवेन्द्र फड़णवीस ब्राह्मण हैं और यही समस्या है. मराठा इसे पसंद नहीं करते. मराठा एक मराठा को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं. गुजरात में भी एक गैर पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया है, हालांकि इससे पहले आनंदीबेन मुख्यमंत्री थीं और उनका संबंध पटेल समाज से है. फ़िलहाल अमित शाह के उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाया गया है, बिलकुल वैसे ही जैसे हरियाणा में किया गया था. वहां एक गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया गया था. ये ऐसे मुद्दे हैं, जो बहुत ही भावनात्मक हैं और बिना किसी उद्देश्य के ये बड़े मोर्चे और विरोध-प्रदर्शन का रूप ले लेते हैं.

डॉ. अंबेडकर के समय में यह फैसला हुआ था कि अनुसूचित जातियों को दस साल के लिए आरक्षण दिया जाएगा. यह सच है कि हर दस साल के बाद इसे आगे बढ़ाया गया. अगर सभी पार्टियां एक साथ बैठ कर इसे बदलना चाहें, तो यह एक अलग विषय है. उन्हें एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए. ऊंची जातियां आरक्षण के लिए आंदोलन नहीं कर रही हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें आरक्षण नहीं मिल सकता. वे आरक्षण के सवाल को बहस में लाना चाहती हैं. जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था, तो उससे पिछड़ी जातियों को, खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार की पिछड़ी जातियों को, एक आवाज़ मिली थी. इन आंदोलनों की कोशिश उस आरक्षण को समाप्त करने की है. सभी पार्टियों के नेताओं को इसपर समझदारी के साथ बातचीत करनी चाहिए. इसके लिए सही रास्ता तमिलनाडु ने दिखाया है. तमिलनाडु ने 50 साल पहले एक समावेशी नीति अपनाई. तमिलनाडु में इस विषय पर कोई विरोध-प्रदर्शन नहीं मिलेगा क्योंकि वहां के पिछड़े पहले से ही समाज, शिक्षा, रोज़गार, और संभ्रांत वर्ग का हिस्सा बन गए हैं. बदकिस्मती से उत्तर भारत में हमने पिछड़ों को मुख्यधारा से अलग कर रखा है इसलिए उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आती है. मंडल कमीशन ने उन्हें एक हद तक मदद किया है, लेकिन जैसा कि होता है अब वे अपनी छवि बदलना चाहते हैं.

इन मुद्दों से ऐसे नहीं निपटा जा सकता. हमें अब थोड़ी तेज़ी दिखाते हुए इन वर्गों को मुख्यधारा में आवश्यक रूप से शामिल करना होगा, ताकि देश के विकास में उन्हें उचित हिस्सा मिल सके और आंदोलन नहीं हो सके. जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तो मुझे इसलिए दु:ख हुआ था क्योंकि हमने देखा कि छात्र राजधानी दिल्ली में आत्मदाह कर रहे थे. वो छात्र कौन थे? वे ऊंची जाति के छात्र थे. ऊंची जाति के लोगों ने यह समझा कि उनकी नौकरी जाने वाली है. इसमें विडंबना यह थी कि उस समय कोई नौकरी नहीं थी. न किसी को नौकरी मिलने वाली थी, न किसी की नौकरी जाने वाली थी. वे केवल सड़कों पर व्यर्थ अपनी जान दे रहे थे. मराठा आंदोलन भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है. हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से समझदारी की उम्मीद है कि हालात के हाथ से निकलने से पहले इन लोगों से बातचीत करे. देवेंद्र फड़णवीस एक सौम्य व्यक्ति हैं. वे अच्छा कर रहे हैं. भ्रष्टाचार और बिल्डर लॉबी से अभी उनका नाम नहीं जुड़ा है. यह महाराष्ट्र के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन उन्हें मराठा लॉबी से अवश्य बातचीत करनी चाहिए और यह पता करना चाहिए कि असल मामला क्या है? लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूं, पटेल और मराठा आंदोलन का मकसद पटेलों और मराठों के लिए कुछ हासिल करना नहीं है, बल्कि पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए जो भी किया गया है उसे समाप्त करना है. आशा करनी चाहिए कि सही दिशा में कदम उठाया जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

मत-मतांतर

युद्ध स्थायी समाधान का रास्ता नहीं : महात्मा गांधी

महात्मा गांधी की मान्यता थी कि दुनिया में कहीं भी, कभी भी हिंसा अथवा युद्ध से किसी भी समस्या या विवाद का स्थायी समाधान नहीं हुआ है. युद्ध से समस्या कुछ समय के लिए टल तो जाती है, बलवान कमजोर को हरा कर, उससे तात्कालिक रूप से जबरदस्ती अपनी बात मनवा तो लेता है, लेकिन हिंसा या युद्ध से कोई ऐसा समाधान नहीं निकलता जो पक्ष तथा विपक्ष दोनों को स्वेच्छा से स्वीकार्य हो. हिंसा का जवाब जब हिंसा से दिया जाता है, तो उससे हिंसा ही बढ़ती है, किसी समस्या का समाधान नहीं होता है. इसके विपरीत, गांधी की मान्यता थी कि असली संघर्ष समरूप शक्तियों के बीच न होकर परस्पर विरोधी ताकतों के बीच होता है. हिंसा के विरुद्ध संघर्ष, हिंसा की विपरीत ताकत, अहिंसा के द्वारा होनी चाहिए. अहिंसा ही हिंसा का अंत कर सकती है, उसे कम कर सकती है. हिंसा का जवाब यदि हिंसा से दिया जाएगा तो उससे हिंसा बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी. गांधीजी के सत्याग्रह दर्शन को ध्यान में रखते हुए जॉन बान्डयूरैंट इस निष्कर्ष पर पहुंची कि गांधीजी संघर्ष को स्वीकार करते हैं, पर हिंसा को नहीं. इसी आधार पर केएल श्रीधारानी ने गांधीजी के सत्याग्रह को हिंसा विहीन युद्ध की संज्ञा दी है.

गांधीजी की सत्य एवं अहिंसा में आस्था रहने के कारण ही सत्याग्रह में भी साध्य और साधन की एकरूपता है. साध्य उतना ही पुनीत होगा, जितना उसे प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधन. गांधीजी के अनुसार साध्य को साधनों से अलग नहीं किया जा सकता है. साध्य अथवा लक्ष्य उतना ही औचित्यपूर्ण होगा, जितना औचित्यपूर्ण उसकी प्राप्ति के लिए अपनाए गए साधन. इस प्रकार गांधीजी साधनों को साध्य से अलग नहीं करते हैं क्योंकि साध्य, साधनों की अंतिम कड़ी है अथवा अंतिम सीढ़ी है.

सत्याग्रह अन्याय के विरुद्ध एक ऐसा अहिंसक संघर्ष है, जिसमें मन, वचन तथा कर्म से हिंसा का त्याग कर, अहिंसा को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है. इसमें ऐसे साधनों को अपनाया जाता है, जो नैतिक, उचित तथा साध्य के अनुरूप हों, और जिनमें संघर्ष का टारगेट अथवा निशाना अन्याय होता है, अन्याय करने वाला नहीं. गांधीजी के अनुसार, सत्याग्रह असत्य व अन्याय के विरुद्ध एक ऐसा अहिंसक संघर्ष है जो नैतिक रूप से सक्षम व सतर्क हो. सत्याग्रह कमजोर, कायर अथवा असहाय का साधन नहीं है. जिस व्यक्ति की सत्य व न्याय में आस्था ही नहीं होगी, वह भले-बुरे, सत्य-असत्य, न्याय-अन्याय के भेद को कैसे जानेगा और जिसे अपने साध्य व साधनों का समुचित शिक्षण-प्रशिक्षण नहीं होगा, वह संघर्ष कैसे करेगा? इस प्रकार, गांधी के अनुसार, सत्याग्रह नैतिक रूप से सक्षम, सक्रिय व सतर्क लोगों द्वारा किया जाने वाला संघर्ष है, न कि असहाय, कायर अथवा डरपोक लोगों का. गांधी के सत्याग्रह का आधार सत्याग्रह की नैतिक शक्ति है. उसकी नैतिकता के मूल्यों के प्रति जागरूकता तथा उनमें आस्था वैसी ही होनी चाहिए, जैसी पारंपरिक हिंसक युद्ध में योद्धा की शारीरिक शक्ति तथा अस्त्र-शस्त्र की शक्ति के प्रति होती है. नैतिक शक्ति शारीरिक शक्ति से श्रेष्ठ होती है. सत्याग्रह संघर्ष में, हिंसक युद्ध की तुलना में अधिक बहादुरी की आवश्यकता

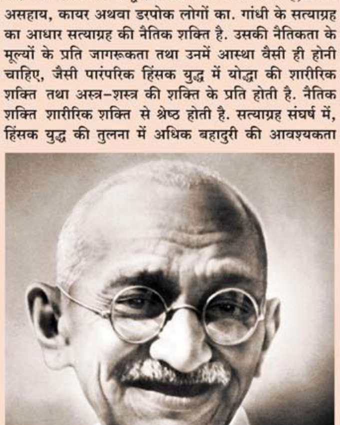

होती है. इस प्रकार सत्याग्रह बहादुरों एवं वीरों का संघर्ष है, न कि कायरों का. कायर तो टिक ही नहीं सकता.

गांधीजी ने आत्मपीड़न, आत्मत्याग अथवा आत्मबलिदान को सत्याग्रह की आत्मा का नाम दिया है. गांधीजी की मान्यता थी कि सत्याग्रही जिस बात को सत्य व न्यायोचित मानता है, उसे उसके लिए अपने आप को पीड़ित करना चाहिए, अपने तन को कष्ट देना चाहिए, न कि अपने सत्य को मनवाने के लिए अपने विरोधी को सताना, पीड़ित करना या मार डालना चाहिए. सत्य पर अडिग रहने के लिए अपना बलिदान देना तो न्यायोचित है, पर अपने विरोधी का बलिदान लेना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि सत्याग्रही का प्रतिपक्षी तो सत्याग्रही के कथित सत्य को सत्य मानता ही नहीं. इसके विपरीत यदि सत्याग्रही असत्य के विरुद्ध अपने संघर्ष में आत्म-बलिदान के रास्ते पर चलेगा और यदि सत्य व न्याय वास्तव में उसके साथ होगा, तो उसका बलिदान किसी नेक साध्य की प्राप्ति के लिए नेक साधन के रूप में स्वीकार किया जाएगा. दूसरी ओर यदि वह असत्य व अन्याय को सत्य व न्याय मानने का हठधर्म कर रहा होगा, तो उसका बलिदान उसके अपने हठधर्म का उचित दंड होगा. नैतिक नियम भी यही है कि हम अपनी गलतियों के लिए अपने आप को दंडित करें, न कि अपने विरोधियों को. विरोधियों को गलती का अहसास कराना सत्याग्रह द्वारा संभव है.

गांधीजी ने संघर्ष का लक्ष्य सदा बुराई को बनाया है, न कि बुरे अथवा बुराई करने वालों को. उनकी मान्यता थी कि यदि हम उस व्यक्ति के जो, किसी कारणवश, हमारा विरोधी हो गया है, विरोध का कारण जान लें और उसे दूर कर दें, तो हमारा विरोध अथवा विपक्षी हमारा दुश्मन न रहकर संभवत: हमारा दोस्त बन जाएगा. गांधीजी टॉलस्टॉय के इस कथन से सहमत थे कि यदि घृणा करनी ही हो तो पाप से करनी चाहिए, न कि पापी से. यदि पापी का पाप समाप्त हो जाएगा, यदि पापी पाप का साथ छोड़ देगा तो वह पापी न रहेगा, वह सुधर जाएगा, पुण्यात्मा हो जाएगा. दूसरी ओर, यदि पापी की पाप से मुक्ति कराने के बजाए उसे यातना दी जाए अथवा उसकी हत्या कर दी जाए, तो उससे उसका पाप समाप्त नहीं होगा, उसका रुख और कड़ा हो जाएगा, वह निष्ठुर हो जाएगा. इसलिए विपक्षी को सताने, पीड़ित करने या उसकी हत्या करने के बजाय, उसकी पाप से मुक्ति करानी चाहिए, जिससे उसका पाप समाप्त हो जाए, उसकी सोच बदल जाए, वह अपने विवेक व आत्मा की आवाज के अनुसार चलने लग जाए, अपने पाप को पहचान ले और उसका साथ छोड़कर, अपनी दैविक, तार्किक व सामाजिक प्रकृति का अनुसरण कर, एक नेक इंसान की तरह जीवनयापन करने लग जाये. ऐसा करने से उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा. वह अपराधी अथवा पापात्मा से पुण्यात्मा हो जाएगा, प्रतिपक्षी से सहपक्षी और फिर मित्र हो जाएगा. सत्याग्रह किसी नीति, कानून-व्यवस्था अथवा व्यवहार विशेष के विरुद्ध संघर्ष तक ही सीमित नहीं है. अपने व्यापक रूप में, सत्याग्रह सोचने और जीने का एक ऐसा मार्ग है, जो हमें आत्म-त्याग व अनेकानेक न्यायोचित तथा अहिंसक साधनों द्वारा तथा न्याय के रास्ते पर प्रशस्त करता है, असत्य, अन्याय व बुराई पर वार करता है तथा विरोध अथवा तथाकथित शत्रु का हृदय परिवर्तन कर उसे पहले सहपक्षी तथा अंत में मित्र बना देता है. जेम्स लूथर एडम्स ने गांधी के सत्याग्रह को सर्वथा सर्वमुखी प्रभावकारी सिद्धांत व साधन माना. जॉन बान्डयूरैंट ने गांधीजी के सत्याग्रह व दुराग्रह में मौलिक विभेद को स्वीकार किया है. उनके अनुसार दुराग्रही सत्य, न्याय व सदाचार पर अपना एकाधिकार साबित करने का प्रयत्न करता है. वह यह समझता है कि वह सही है, गलत हो ही नहीं सकता है और दूसरी ओर उसका विरोध करना गलत है, सही हो ही नहीं सकता है. वह अपने विरोधी अथवा विपक्षी को स्पष्टीकरण का अवसर दिए बिना ही उसकी बात अथवा व्यवहार को अपने पूर्व-निर्णय के आधार पर पहले ही गलत अथवा अनुचित मान लेता है और उस पर आक्रमण कर देता है. सत्याग्रही के मुकाबले में दुराग्रही के सोचने तथा संघर्ष करने का तरीका तर्क पर आधारित न होकर, पूर्व-निर्णय के सिद्धांत पर आधारित होता है. दूसरी ओर दुराग्रही के मन में (गलत होने पर भी) एक प्रकार का डर भी सताता है, उसको लगता है कि यदि सत्याग्रही की बातों को मान लेते हैं, तो समाज में मेरी इज्जत न होकर सत्याग्रही की इज्जत करने लगेंगे, मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी. इसीलिए दुराग्रही अपने विपक्षी को शत्रु मान लेता है, बुराई का पुतला मान लेता है तथा बुराई पर हमला करने के बजाय, बुरे पर हमला करता है. वह उसको सताता है, ब्लैकमेल करता है, उसे नीचा दिखाने और उसे अंतत: हराने के लिए हर संभव प्रयत्न करता है तथा उसे अपनी बात समझाने व कहने का अवसर भी नहीं देता है. दूसरी ओर सत्याग्रही ये मान कर चलता है कि उसका विरोधी सही हो सकता है और वह स्वयं गलत हो सकता है. यही मान कर वह अपने विरोधी को न केवल अपना पक्ष समझाता है, बल्कि उसका पक्ष भी सुनने, समझने तथा जहां तक संभव हो स्वीकार करने के लिए तत्पर रहता है. वह अपने विपक्षी को उसके पक्ष का संभावित विकल्प प्रस्तुत करता है जो उसे स्वीकार करने का अवसर देता है और उसके सामने ऐसे सत्याग्रही अपने तथाकथित शत्रु को मित्र बनाने का भरसक प्रयत्न करता है, जिससे दोनों मिलकर बुराई व अन्याय का मुकाबला कर सकें. इस तरह सत्याग्रह सत्य की राह है जिसपर चलकर अन्याय का प्रतिकार किया जाता है. ■

(चन्दन कुमार, शोधार्थी, अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा)

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

ग़िलानी साहब, आपका ये बयान दुखद है

आज एक अजीब सा सवाल दिमाग में घूम रहा है. क्या हम अपनी मांगों के समर्थन में इतनी दूर चले जाएं कि कब हमने सीमा रेखा लांघी, ये याद ही न रहे. कश्मीर में दुख है, दर्द है, तकलीफ है और आजादी के बाद या कश्मीर के भारत में विलय के शर्तनामे पर दस्तखत के बाद से जो गुस्सा है, उस गुस्से को दर्शाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके अपनाने पर कोई ऐतराज नहीं है. सरकार न सुने, उसे सुनाने के लिए बच्चों के हाथ में पत्थर हो, इससे भी समझा जा सकता है. लेकिन ये बात बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई तकरार होती है, उस तकरार में अगर पाकिस्तानी सैनिकों की मौत होती है तो उन सैनिकों के लिए नमाज-ए-जनाजा पढ़ने की अपील की जाए. जम्मू-कश्मीर में हुर्रियत के नेता सैयद अली शाह गिलानी ने ये अपील कर उन सभी लोगों के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया, जो कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए सरकार या जनता के सामने कश्मीर की सही स्थिति रखना चाहते हैं. लगभग ऐसी स्थिति बनी है कि भारत में होने वाले आतंकी हमलों के सूत्र का एक सिरा पाकिस्तान में नजर आता है. हमारे सिपाही शहीद होते हैं, उन पर एक सामान्य सा शोक प्रस्ताव और पाकिस्तान के सिपाही जब मारे जाते हैं, तो उनके लिए सार्वजनिक रूप से नमाज-ए-जनाजा की अपील मन को झकझोर देती है.

क्या कश्मीर के कुछ नेता पाकिस्तान के सवाल को, सीमा के सवाल को और कश्मीर के सवाल को एक मानते हैं या कश्मीर और कश्मीर के लोगों का सवाल अलग है और पाकिस्तान का सवाल अलग है, ये मानते हैं. पाकिस्तान जो भी, जैसा भी शोर करे, लेकिन उसने हुर्रियत नेताओं के गाल पर एक तमाचा मारा है, जब उसने संयुक्त राष्ट्र में भाषण देते हुए कश्मीर के हुर्रियत नेताओं का नाम नहीं लिया, गिलानी साहब का नाम नहीं लिया, बल्कि उसने बुरहान वानी का नाम लिया. बुरहान वानी को लेकर जो भी संशय हो, सवाल हो, कम से कम कश्मीर के लोग ये मानते हैं कि वह शौकिया नौजवान था, जो तस्वीरें खिंचवाकर और उसे फेसबुक पर लगाने में ज्यादा रुचि रखता था, आतंकी गतिविधियों से उसका रिश्ता नहीं था. अगर कश्मीरी ये मानते हैं, तब क्यों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूएन में बुरहान वानी को कश्मीर का सबसे बड़ा मुजाहिद बता दिया और सैयद अली शाह गिलानी समेत किसी भी नेता को इस लायक नहीं समझा कि कश्मीर की आजादी के लिए लड़ने वाले चेहरे के रूप में वहां उनका नाम सबूत के तौर पर लिया जा सके. दरअसल, ये बारीकियां बताती हैं कि पाकिस्तान खुद कश्मीर के मसले को हल करने में रुचि नहीं रखता, उसे उलझाने में ज्यादा रुचि रखता है. इसलिए हुर्रियत के सबसे बड़े नेता का ये बयान कि पाकिस्तानी सैनिकों के लिए नमाज-ए-जनाजा पढ़ी जाए, मन को परेशान करता है और उनसे दूर होने के संकेत भी बताता है. कश्मीर के जिन समझदार लोगों से बातचीत हुई, वो सब इसी राय के हैं. कश्मीर की तकलीफ, कश्मीर का दर्द अपनी जगह है, लेकिन उनका इलाज कम से कम उस तरीके से नहीं हो सकता, जिस तरीके से कश्मीर के कुछ नेता चाहते हैं और खास कर उस तरह से तो बिल्कुल ही नहीं, जो सीमा के सवाल को, पाकिस्तान के सवाल को, कश्मीर के लोगों के सवाल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं.

एक तरफ सरकार पाकिस्तान में किए गए सर्जिकल ऑपरेशन से खुश है, वहीं उसके साथ सारा देश भी खुश है. ये खुशी इसलिए भी है कि इन क्षणों को बहुत दिनों के बाद भारत के लोगों ने खुशी से जिया है. लेकिन इस सर्जिकल ऑपरेशन के बहुत पहले से महाराष्ट्र में कुछ ऐसा घट रहा है, जो बहुत चिंता का विषय है.

> **एक और बात चिंता में डालती है कि हमारी सरकारें या हमारी केंद्र सरकार लगातार असंवेदनशील होती जा रही है. जब तक आंदोलन शांतिपूर्ण रहता है, अहिंसक रहता है, उसके कानों में आंदोलन का दर्द, आंदोलन की मांगें, आंदोलन की चीखें नहीं पहुंचती हैं, लेकिन जिस दिन ये आंदोलन हिंसक हो जाता है, उसी दिन से सरकारें या सरकार दमन का रास्ता चुन लेती है, लोगों को भटकाने का रास्ता चुन लेती है.**

महाराष्ट्र में एक मराठा लड़की के साथ उसके पड़ोस के कुछ लड़कों ने वीभत्स बलात्कार किया. उस बलात्कार के विरोध में महाराष्ट्र में मराठा समाज खड़ा हो गया और उसने उस लड़की के लिए न्याय की मांग की. न्याय की ही मांग नहीं, त्वरित न्याय की मांग की और जिन्होंने बलात्कार किया है उन्हें फांसी की सजा देने की बात कही. दिल्ली में हुए बलात्कार के खिलाफ दिल्ली में जिस तरह से जनाक्रोश उमड़ा था, उससे ज्यादा व्यापक जनाक्रोश महाराष्ट्र में उभरा. हर शहर में जुलूस निकलने शुरू हुए. इन जुलूसों की संख्या एक, दो, दस, बीस, पच्चीस, पचास हजार नहीं, बल्कि लाखों में थी. ये जुलूस पूरे तौर पर शांतिप्रिय जुलूस थे. इन्हें किसी ने संगठित नहीं किया. इनके पीछे कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई सामाजिक संगठन नहीं था. स्थानीय लड़कियां जुलूस का नेतृत्व करती हैं और मंच पर आती हैं. और अब तो जुलूस की संख्या 10-15 लाख तक पहुंच गयी है.

राजनीतिक दलों ने अपनी उपस्थिति इन जुलूसों में बनानी चाही. मराठा नेताओं ने चाहा कि वे इन जुलूसों का नेतृत्व कर इन्हें अपने द्वारा किया पराक्रम बताएं. पर लोगों ने किसी भी राजनीतिक दल को न जुलूस का नेतृत्व करने दिया और न ही मंच पर जाने दिया. जितने बड़े मराठा नेता हैं, चाहे वो शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों, पृथ्वीराज चौहान हों या किसी भी पार्टी के छोटे या बड़े मराठा सरदार हों, प्रदर्शनकारी जनता ने उन्हें अपना नेता माना ही नहीं.

जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, तो उनकी एक ही मांग थी कि बलात्कारियों को फांसी दें. लेकिन तीन दिन बीतते-बीतते इसमें कई और मांगें जुड़ गईं. किसानों को पानी, बिजली, फसल का उचित भाव और मराठा समाज के बच्चों को आरक्षण.

ये जो मांगें जुड़ीं, इन पर बात करने के लिए सरकार अब तक आगे नहीं आई है. यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन मौन जुलूस के रूप में अपनी संख्या लगातार बढ़ाता जा रहा है. पूरे प्रदर्शन के दौरान इन पंक्तियों के लिखे जाने तक एक भी ठेला नहीं लुटा, एक भी दुकान नहीं तोड़ी गई, एक भी वाहन क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, हिंसा का कोई चिन्ह इस जुलूस में नहीं दिखा, जो अक्सर ऐसी जुलूसों में दिख जाता है. सर्जिकल ऑपरेशन की खुशी के बीच मराठा समाज अपने आंदोलन को और बड़ा बनाता जा रहा है और दिवाली से पहले मुंबई में डेढ़ करोड़ लोगों का जुलूस निकालने की योजना है. सबसे ज्यादा दुख की बात है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस आंदोलन की सभी मांगों पर चुप है. किसी के पास इन आंदोलनकारियों से बात करने का समय नहीं है.

एक और बात चिंता में डालती है कि हमारी सरकारें या हमारी केंद्र सरकार लगातार असंवेदनशील होती जा रही है. जब तक आंदोलन शांतिपूर्ण रहता है, अहिंसक रहता है, उसके कानों में आंदोलन का दर्द, आंदोलन की मांगें, आंदोलन की चीखें नहीं पहुंचती हैं, लेकिन जिस दिन ये आंदोलन हिंसक हो जाता है, उसी दिन से सरकारें या सरकार दमन का रास्ता चुन लेती है, लोगों को भटकाने का रास्ता चुन लेती है. एक ऐसी स्थिति पैदा कर देती है, जिसमें जनता एक तरफ हो जाती है और सरकार दूसरी तरफ. हमारे देश में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें अगर समय रहते मांगों का न्यायोचित या लोकतांत्रिक उत्तर आंदोलनकारियों को मिल जाता, तो स्थितियां कभी खराब नहीं होतीं. कश्मीर इसका एक सटीक उदाहरण है. 1990 के दशक में कुलदीप नैय्यर और जस्टिस सच्चर ने जेकेएलएफ के लोगों को इस बात के लिए मनाया था कि वो हथियार छोड़ें, उनकी मांगों पर सरकार ध्यान देगी. जेकेएलएफ के लोगों ने यासिन मलिक के नेतृत्व में हथियार छोड़ दिए. शांतिपूर्ण मांग रखी, जेल गए, हथियार बीएसएफ को सौंप दिए, लेकिन सरकार ने उनकी मांगें नहीं सुनी. आज हालात ये है कि कश्मीर के लोग एक तरफ हैं और सरकार दूसरी तरफ.

पूरे महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की चिंगारी आग बनकर फैल चुकी है. उत्तर भारत के लोग दस लाख लोगों के जुलूस की कल्पना नहीं कर सकते हैं और वह भी शांतिपूर्ण जुलूस, जिसका नेतृत्व किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है. इसमें नौजवान सबसे ज्यादा हैं, लेकिन कहीं एक पत्थर नहीं चला. मौन जुलूस है ये. दिल्ली के मीडिया, टेलीविजन और अखबारों में इस आंदोलन की कोई गूंज नहीं है, क्योंकि शायद हमारी मानसिकता ही हिंसा को सुख के चश्मे से देखने की बन गई है. अगर यही आंदोलन हिंसक होता, तो पूरा मीडिया इस आंदोलन को दिखाता. शांतिपूर्ण आंदोलन मीडिया की सुर्खी नहीं बन पाया है. शांतिपूर्ण आंदोलन टेलीविजन का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच पाया है.

अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास समय है कि वो इस आंदोलन से उपजी मांगों का देशव्यापी हल निकाले. महाराष्ट्र का ये आंदोलन, महाराष्ट्र के किसानों के शांतिपूर्ण विद्रोह का पहला कदम है. महाराष्ट्र के किसानों का ये शांतिपूर्ण आंदोलन, महाराष्ट्र के किसान नौजवानों का शांतिपूर्ण उद्घोष है. इसलिए आवश्यकता है कि केंद्र सरकार अपने उन सभी मंत्रियों और अधिकारियों को महाराष्ट्र के शांतिपूर्ण प्रदर्शन से उपजे सवालों का हल तलाशने में लगाए, जो सर्जिकल स्ट्राइक में नहीं लगे हैं. रक्षामंत्री, गृहमंत्री, सर्जिकल स्ट्राइक के परिणामों का विश्लेषण करें. उन्हें देश की सुरक्षा में जितना वक्त देना हो, दें. लेकिन महाराष्ट्र के किसानों के इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अनदेखा नहीं करना चाहिए. ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है. महाराष्ट्र का शांतिपूर्ण किसान आंदोलन ये बताता है कि हमारे विकास का ढांचा कितना त्रुटिपूर्ण है. अगर विकास के छींटे समाज के ज्यादातर वर्गों तक पहुंचते तो और आरक्षण की मांग नहीं होती. आरक्षण का रिश्ता सत्ता में हिस्सेदारी से है, आरक्षण का रिश्ता नौकरियों से नहीं है. सरकार तत्काल बात करे, अभी समय है. बाद में, महाराष्ट्र के गांवों से उठा ये शांतिपूर्ण जनांदोलन निराशा के आंदोलन में न तब्दील हो जाए, इसलिए सरकार को समय रहते कदम उठाना चाहिए. ऐसा हमारा विनम्र अनुरोध अवश्य है. ■

editor@chauthiduniya.com

» »

क्या कश्मीर के कुछ नेता पाकिस्तान के सवाल को, सीमा के सवाल को और कश्मीर के सवाल को एक मानते हैं या कश्मीर और कश्मीर के लोगों का सवाल अलग है और पाकिस्तान का सवाल अलग है, ये मानते हैं. पाकिस्तान जो भी, जैसा भी शोर करे, लेकिन उसने हुर्रियत नेताओं के गाल पर एक तमाचा मारा है, जब उसने संयुक्त राष्ट्र में भाषण देते हुए कश्मीर के हुर्रियत नेताओं का नाम नहीं लिया, गिलानी साहब का नाम नहीं लिया, बल्कि उसने बुरहान वानी का नाम लिया. बुरहान वानी को लेकर जो भी संशय हो, सवाल हो, कम से कम कश्मीर के लोग ये मानते हैं कि वह शौकिया नौजवान था, जो तस्वीरें खिंचवाकर और उसे फेसबुक पर लगाने में ज्यादा रुचि रखता था, आतंकी गतिविधियों से उसका रिश्ता नहीं था. अगर कश्मीरी ये मानते हैं, तब क्यों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूएन में बुरहान वानी को कश्मीर का सबसे बड़ा मुजाहिद बता दिया और सैयद अली शाह गिलानी समेत किसी भी नेता को इस लायक नहीं समझा कि कश्मीर की आजादी के लिए लड़ने वाले चेहरे के रूप में वहां उनका नाम सबूत के तौर पर लिया जा सके.

पाठकों की दुनिया

कश्मीरियों के दर्द को महसूस कीजिए

संतोष भारतीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखे अपने पत्र प्रधानमंत्री जी, ये कश्मीर का सच है (26 सितंबर- 02 अक्टूबर 2016) में कश्मीर की समस्या को लेकर चर्चा की है और वहां की सच्चाई से प्रधानमंत्री को अवगत कराया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कश्मीरियों से बात करनी चाहिए और जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर वह चाहते क्या हैं? कश्मीरियों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है. भारत की सरकारों द्वारा कश्मीरियों के साथ इतना छल किया गया है कि उन्होंने अब सरकारों पर विश्वास करना बंद कर दिया है. उन्हें लगता है कि उनके सारे फैसले दिल्ली से होते हैं. कश्मीरियों के सबसे लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया गया. कश्मीरियों के साथ हमेशा भेदभाव होता रहा है, यह सच है और इसे हमें स्वीकार करना होगा. उनके आजादी का गलत मतलब निकाला जाता है जो सरकार को समझने और उनके दर्द को महसूस करने की जरूरत है.

–वसीम अकरम, *अलीगढ़, उत्तर प्रदेश.*

कश्मीर का सच

संतोष भारतीय द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे पत्र प्रधानमंत्री जी, ये कश्मीर की सच्चाई है (26 सितंबर- 02 अक्टूबर 2016) को पढ़कर कश्मीर की सच्चाई सामने आती है. कश्मीर के बारे में जो न्यूज चैनलों पर दिखाया जाता है, इस खबर को पढ़ने का बाद पता चलता है कि वह एक कोरा झूठ है जिससे देश के लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है. जिस प्रकार इन पत्रकारों ने कश्मीर जाकर कश्मीरियों से बातचीत की, उनकी बातों को सुना और देश के सामने रखा है, उसी प्रकार बाकी पत्रकारों, सिविल सोसायटी के लोगों और दूसरे लोगों को भी कश्मीर जाना चाहिए. वहां के लोगों से बात करनी चाहिए और बताना चाहिए कि हिंदुस्तान के दिल में उनके लिए उतना ही प्यार है जितना बाकी हिंदुस्तानियों के लिए. सरकार को भी अपने नुमाइंदों को वहां के लोगों से बातचीत करने के लिए भेजना चाहिए और बताना चाहिए कि सरकार उनके खिलाफ नहीं है. सरकार उनके दर्द को महसूस करती है. उनके विकास, रोजगार और पढ़ाई के लिए कार्य कर रही है. सरकार को कश्मीरियों को भरोसा दिलाना चाहिए, जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी ने उनका दिल जीता था और अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कश्मीरियों के मन में आज भी इज्जत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाजपेयी की तरह ही कश्मीरियों का दिल जीतना और उनके अधूरे सपने को पूरा करना चाहिए.

–सीताराम तिवारी, *दानापुर, बिहार.*

कश्मीर में अशांति की वजह

आलेख-कश्मीर समस्या इतिहास के आईने में (26 सितंबर- 02 अक्टूबर 2016) पढ़ा. जानकारीपरक और तथ्यपरक है. इस आलेख में लिखी बातों को हर हिंदुस्तानी को पढ़ना और अब तक जो कश्मीर और कश्मीरियों के साथ हुआ, उसे समझना चाहिए. कश्मीरियों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने हक के बदले पैलेट गन की गोली मिली जो उनके साथ अन्याय है. वह जब भी अपनी बात कहना चाहते हैं, तो उन्हें भारत विरोधी बताकर अनदेखा कर दिया जाता है. आज कश्मीर में अशांति की वजह भारत की पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा की गईं गलतियां हैं जिसमें शेख अब्दुल्ला को जेल में डालना और फारूख अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त करना. जितने भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कश्मीर गए और उन्होंने कश्मीरियों से जो वादा किया उसे आज तक पूरा नहीं किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कश्मीरियों का दिल जीतने का बहुत बड़ा मौका है और वह कश्मीरियों से किए गए वादों को पूरा करें.

–आदिल अली, *जामिया, दिल्ली*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमिल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

सरकार की अनदेखी

लाखों इंदिरा आवास अधूरे पड़े हैं

राजेश सिन्हा

बिहार में लाखों अधूरे पड़े इंदिरा आवास को लेकर न केवल सियासी पारा चढ़ने लगा है, बल्कि नौकरशाहों के साथ-साथ बिहार सरकार की घिग्घी बंद होने लगी है. गरीब व आवास विहीन परिवारों के लिए आशियाना बनाने के नाम सत्ता पक्ष और विपक्ष की तकरार और समय-समय पर किए गए वादे भी किसी से छिपे नहीं हैं. हकीकत यह है कि बिहार में इंदिरा आवास योजना महज सियायी योजना बनकर रह गई है. गौरतलब है कि समय-समय पर इंदिरा आवास योजना की समीक्षा होती रहती है और उच्चाधिकारियों के द्वारा दिशा-निर्देश भी जारी किए जाते रहे हैं. लेकिन भ्रष्ट नौकरशाहों की वजह से इंदिरा आवास मामले में महज खानापूर्ति के सिवाय कुछ भी संभव नहीं हो सका है. अब जब लाखों इंदिरा आवास अधूरे पड़े हैं, तब विभागीय स्तर पर आवास को पूर्ण करने के नाम पर पसीने बहाए जा रहे हैं. लेकिन यह देखने के लिए किसी के पास समय नहीं है कि आखिर इंदिरा आवास का निर्माण धरातल पर संभव क्यों नहीं हो पा रहा है? यह बात अलग है कि ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविन्द कुमार चौधरी का दावा है कि सम्पन्न हुए पंचायत चुनाव के साथ-साथ तकनीकी वजहों से तीन-चार माह तक इंदिरा आवास के निर्माण कार्य में प्रगति संभव नहीं हो सकी.

दशकों से लूट परम्परा की शिकार होती रही इंदिरा आवास योजना की बातों को अगर दरकिनार कर पिछले चार वित्तीय वर्ष की चर्चा की जाए तो यह प्रमाणित हो जाएगा कि बिहार में इंदिरा आवास योजना भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़कर रह गई है. चार वित्तीय वर्षों के दौरान 19 लाख 38 हजार 945 इंदिरा आवासों की स्वीकृति तो दी गई, लेकिन महज 3 लाख 43 हजार 249 आवासों का निर्माण ही संभव हो पाया जो कई तरह के सवालों को जन्म देने के लिए काफी है. 15 लाख 95 हजार 696 आवासों को विभागीय स्तर पर अधूरा बताया जा रहा है. बात अलग है कि अधूरे बताए जा रहे आवास वास्तविक तौर पर अधूरे हैं अथवा निर्माण कार्य शुरू हुआ ही नहीं, के सवाल पर अधिकारी बगलें झांकने लगते हैं. ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा अधूरे पड़े इंदिरा आवास को पूरा करने के लिए केवल अभियान चलाया जा रहा है, बल्कि लाभ पाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का एलान भी किया जा रहा है.

इस वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम बैकलॉग पूरा करने की जिम्मेदारी जिलों को सौंपी गई है. ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर किसी तरह अधूरे पड़े इंदिरा आवास को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है. इतना ही नहीं वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जिला स्तरीय पदाधिकारियों को अधूरे पड़े इंदिरा आवास को पूर्ण करने के लिए अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है. उच्चाधिकारियों के आदेश को अमलीजामा कब तक पहनाया जायगा, यह कहना मुश्किल है. लेकिन बिहार के किसी भी इलाके में इंदिरा आवास निर्माण की स्थिति अच्छी नहीं है. कोसी इलाके में आवंटित इंदिरा आवासों में से 13 प्रतिशत इंदिरा आवास का निर्माण संभव हो सका है जबकि सीमांचल में महज 19 प्रतिशत इंदिरा आवास ही बनाए जा सके हैं. मिथिलांचल में 32 प्रतिशत इंदिरा आवास निर्माण का दावा किया जा रहा है, लेकिन मगध का हाल किसी से छिपा नहीं है. यहां चार वित्तीय वर्षों के दौरान इंदिरा आवासों में से महज 31 प्रतिशत इंदिरा आवास का निर्माण बताता है कि सरकार की कथनी व करनी में अंतर है. बिहार के अन्य इलाकों के आंकड़े भी चीख-चीख कर यह कह रहे हैं कि इंदिरा आवास के नाम पर बिहार में महज कागजी घोड़ा दौड़ाया जा रहा है. बिहार में गरीब व आवास विहीन परिवारों को छतदार मकान उपलब्ध कराने के ख्याल से इंदिरा आवास योजना के तहत सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध करायी गई है. लेकिन केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा लगातार दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बाद भी तकनीकी वजहों से इंदिरा आवास का निर्माण संभव नहीं हो सका है. जबकि इंदिरा आवास पाने वालों के बीच प्रथम किस्त की राशि का वितरण भी कर दिया गया है. स्वीकृत आवासों के निर्माण के लिए दो किस्तों में राशि भुगतान का प्रावधान है. शौचालय निर्माण को भी योजना में शामिल कर वित्तीय वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 में प्रति आवास 70 हजार रुपये दो किस्तों में देने का एलान किया गया था. ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जारी की गई राशि के साथ-साथ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये देना सुनिश्चित है. ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा प्रथम किस्त के रूप में 50 हजार रुपये जारी कर दिया गया है, लेकिन प्रावधान के अनुसार दूसरी किस्त की राशि अटकी पड़ी है. इधर जानकारों का कहना है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा आवास निर्माण पूर्ण करने के बाद शौचालय की राशि देने की बात कही गई थी. लेकिन राशि उपलब्ध नहीं कराए जाने की वजह से भवनों का निर्माण संभव नहीं हो सका. वित्तीय वर्ष 2014-2015 से 70 हजार रुपये की राशि 35-35 हजार के दो किस्तों में देने का प्रावधान है. लाभ पाने वालों के द्वारा छत तक घर के साथ शौचालय का निर्माण किए जाने के बाद दूसरे किस्त की राशि का भुगतान होना है. लेकिन प्रथम किस्त के रूप में मिली राशि इतनी कम थी कि मंहगाई के इस युग में आवास का निर्माण संभव नहीं हो सका. ■

> **दशकों से लूट परम्परा की शिकार होती रही इंदिरा आवास योजना की बातों को अगर दरकिनार कर पिछले चार वित्तीय वर्ष की चर्चा की जाए तो यह प्रमाणित हो जाएगा कि बिहार में इंदिरा आवास योजना भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़कर रह गई है. चार वित्तीय वर्षों के दौरान 19 लाख 38 हजार 945 इंदिरा आवासों की स्वीकृति तो दी गई, लेकिन महज 3 लाख 43 हजार 249 आवासों का निर्माण ही संभव हो पाया जो कई तरह के सवालों को जन्म देने के लिए काफी है.**

मुर्दों को आशियाना सजाने के लिए मिली इंदिरा आवास की राशि

खुले आसमान के नीचे जीवन गुजर-बसर करने वाले इंसानों को भले ही आशियाना नसीब नहीं हो पा रहा हो, लेकिन बिहार के कई इलाकों में मुर्दों को भी आशियाना उपलब्ध करा दिया गया है. शासक-प्रशासक की दरियादिली का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि इंदिरा आवास पाने की पात्रता नहीं रखने वाले कई धनाढ्य भी इंदिरा आवास पाने से वंचित नहीं रहे. यहां तक कि कई कुंवारों के प्रति दरियादिली दिखाते हुए उनकी मौसी, बहन तथा भाभी को भी पत्नी दर्शाकर इंदिरा आवास का लाभ दे दिया गया है. ऐसी बात नहीं है कि इस तरह का वाक्या पहली बार सामने आया है, दर्जनों बार इस तरह के मामलों को लेकर इलाका सुलगा और मामले की जांच का आदेश भी दिया गया. लेकिन जांच के नाम पर महज खानापूर्ति कर मामले को जमींदोज कर दिया गया. स्थिति अब यह है कि इंदिरा आवास पाने वालों के नाम विभागीय स्तर पर लगातार जारी किए जा रहे हैं, लेकिन फर्जी लाभ पाने वाले सामने आने से कतरा रहे हैं. बात अलग है कि मामले का भांडा फूटने के बाद विभागीय पदाधिकारी फर्जीवाड़ा करने वालों के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए सूद सहित राशि वसूलने की बात कर रहे हैं. अन्य इलाकों की बातों को फिलवक्त दरकिनार करते हुए अगर खगड़िया जिले की बात करें तो इस इलाके के लिए इस तरह का मामला नया नहीं है. लगातार दो-दो बार एक ही व्यक्ति को इंदिरा आवास का लाभ देने के आरोप में चौथम प्रखंड के बीडीओ सहित कई अन्य लोगों के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है. मामले को खंगालने की कोशिश शुरू होते ही कई पर कानूनी तलवार लटकी पड़ी है. जानकारों की अगर मानें तो पहले कुंवारे व्यक्तियों ने पंचायत सचिव की मिलीभगत से इंदिरा आवास का लाभ लिया. फिर तो परिपाटी ही बन गई और दूसरी की पत्नी को अपनी पत्नी घोषित कर फर्जीवाड़ा करते हुए इंदिरा आवास का लाभ लेना शुरू कर दिया गया. तुर्रा तो यह है कि रिश्ते को ताक पर रखते हुए मौसी और भाभी को भी अपनी पत्नी बताकर इंदिरा आवास का लाभ ले लिया गया है. यहां तक कि बहनों को भी फर्जीवाड़ा करने वालों ने पत्नी बना लिया और इंदिरा आवास की राशि डकार ली.

हास्यास्पद स्थिति यह है कि जरूरतमंद इंसानों को तो इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला, लेकिन मुर्दों को आशियाना मिल गया. चौथम प्रखंड के अंतर्गत जवाहरनगर के एक नाबालिग लाभार्थी तूफानी सदा ने अपनी भाभी सिरोमणी देवी को अपनी पत्नी बताकर इंदिरा आवास का लाभ ले लिया. प्रथम किस्त के रूप में तीस हजार रुपये लेते ही इस बात की कलई खुल गई और तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सुरेन्द्र कुमार ने सूद सहित उठाव की गई राशि जमा करने का आदेश जारी किया. सूद सहित राशि वसूलने में आखिर पेंच क्या है? यह तो सरकारी हुक्मरान ही जानें. लेकिन इसी प्रखंड के रोहियार पंचायत के बंगलिया गांव निवासी नाबालिग अंग्रेज सिंह ने अपनी मौसी सकुना देवी को अपनी पत्नी बताकर इंदिरा आवास का लाभ ले लिया. गजब तो तब हो गई जब परबत्ता प्रखंड के अंतर्गत कुल्हरिया निवासी सुनील कुमार ने अपनी सगी बहन उर्मिला को कागज पर पत्नी बनाया और सरकार बाबू की कृपा से इंदिरा आवास ले लिया. जानकारों की अगर मानें तो चौथम प्रखंड सहित अन्य प्रखंड के भी सैकड़ों कुंवारे और नाबालिगों के द्वारा पंचायत सचिव की मिलीभगत से इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है. मामले का खुलासा होने के बाद तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सुरेन्द्र कुमार ने तत्कालीन बीईओ संजय चौधरी को जांच करने का आदेश दिया था. बीईओ के द्वारा की गई जांच में मामला सत्य पाए जाने के बाद फर्जी लाभुकों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए सूद सहित उठाव की गई राशि जमा करने का आदेश जारी किया गया था. इतना ही नहीं पंचायत सचिव से भी स्पष्टीकरण मांगा गया था. बहरहाल, इस मामले में पंचायत सचिव के विरुद्ध कार्रवाई होगी अथवा अन्य मामलों की तरह यह भी मामला दफन होकर रह जाएगा, यह कहना तो शायद जल्दबाजी होगी. लेकिन इतना तय है कि लाभुकों के मामले में भौतिक सत्यापन बंद कमरे में ही किस तरह कर फर्जीवाड़ा की घटना को अंजाम दिया जाता है, यह बात प्रमाणित हो चुकी है. इधर रालोसपा के खगड़िया जिलाध्यक्ष अमित कुमार मंटू ने कहा है कि इंदिरा आवास मामले की अगर इमानदारी पूर्वक जांच की जाए तो कई सफेदपोशों का चेहरा बेनकाब होना तय है. जरूरतमंदों के बजाय धनाढ्य और पात्रता नहीं रखने वाले परिवारों को इंदिरा आवास उपलब्ध कराकर नौकरशाहों ने गरीब व आवास विहीन परिवारों की हकमारी की है. बार-बार फर्जी इंदिरा आवास मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग होती रही है, लेकिन जांच के नाम पर महज खानापूर्ति कर मामले को दबा दिया जाता रहा है. अगर इस तरह के मामले पर विराम नहीं लगा तो गरीब व आवास विहीन परिवारों के लिए रालोसपा के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा.

दूसरी तरफ खगड़िया के जनसम्पर्क पदाधिकारी कमल सिंह का कहना है कि जैसे-जैसे फर्जीवाड़ा का मामला सामने आता जा रहा है, वैसे-वैसे विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए उठाव की गई राशि वसूलने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. जल्द ही दोषियों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. बहरहाल, फर्जी इंदिरा आवास मामले की जांच होगी अथवा यह मामला भी अन्य मामलों की तरह दफन होकर रह जाएगा, यह आने वाला समय ही बताएगा. लेकिन अधूरे पड़े इंदिरा आवास मामले को लेकर नीतीश सरकार न केवल घिरती नजर आ रही है बल्कि सियासी पारा भी परवान चढ़ता जा रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

ईम्पोर्टेड केमिकल से तैयार, लैब टेस्टेड
पेन्ट डिस्टेम्पर
कोई भी हो
वॉल पुट्टी केवल ईटालियन वॉल पुट्टी
Laboratory Tested
Please Compare Lab Report
Laboratory Tested
Made from Imported Chemicals
ईटालियन
व्हाईट
वॉल पुट्टी
Slight Costly but Superior
लैब रिपोर्ट अवश्य चेक करें।
लैब रिपोर्ट हमारे सभी डीलर्स के यहां उपलब्ध है
प्रखण्ड स्तर या अपने क्षेत्र हेतू सप्लायर / डीलरशिप के लिए सम्पर्क करें।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com
सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाऐ
सीमेन्ट
कोई भी हो परन्तु
वाटरप्रूफिंग केमिकल सिर्फ
मिस्टर केमिस्ट
सीमेन्ट कोई भी हो लेकिन वाटरप्रूफिंग केमिकल मिस्टर केमिस्ट ही हो, क्योंकि मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग केमिकल ईम्पोर्टेड केमिकल से बनाया गया है, प्रत्येक पैक पर नम्बर युक्त होलोग्राम से नकल से पूरी तरह सुरक्षित १, ५, १०, २० एवं २०० लीटर होलोग्रामिक पैक में अब आपके यहां भी उपलब्ध। मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाए।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

आइएएस केके पाठक

माननीय रुकेंगे नहीं और हाकिम झुकेंगे नहीं

सूबे में इस साल अप्रैल में पहले आंशिक और फिर पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू कर दी गई. कड़क और इकबाली आइएएस केके पाठक को इस जिम्मेदारी के लिए सबसे उपयुक्त माना गया और उत्पाद व मद्यनिषेध विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया. अपनी इमानदारी, कामकाज में सख्ती, कानून के प्रति सम्मान को लेकर पाठक की बड़ी ख्याति रही है. अपने ऐसे अनेक गुणों के कारण ही वह बार-बार चर्चा में आते रहे हैं और कहीं लंबे समय तक टिक न पाना उनकी नियति बन गई है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

बिहार में एक नई स्थिति बन रही है. विधायिका और कार्यपालिका आमने-सामने आ रही हैं. बिहार विधान परिषद के तीन सदस्यों ने उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव और वरिष्ठ आइएएस केके पाठक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की नोटिस दी है. भारतीय जनता पार्टी के नवल किशोर यादव, लालबाबू प्रसाद व रजनीश कुमार ने इसी तरह की सूचना अलग-अलग दी है. परिषद के इन तीनों सदस्यों का कहना है कि विधान परिषद में कही गई बातों के प्रतिवाद में वकील की नोटिस भेज कर केके पाठक ने उनके विशेषाधिकार का हनन किया है. परिषद ने इन तीनों सदस्यों की सूचना को ग्रहण कर लिया है और इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाना है. केके पाठक ने इन तीनों को वकील के जरिए नोटिस भिजवाया है. इसमें परिषद में उत्पाद व मद्यनिषेध के कामकाज को लेकर की गई टिप्पणी का हवाला देकर उनसे माफी मांगने या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है. हालांकि नवल किशोर यादव ने दावा किया है कि उन्होंने इस विभाग या सूबे में शराबबंदी को लेकर सदन में कोई बात कही ही नहीं है. इसी साल जुलाई के अंतिम दिनों बिहार की नई उत्पाद नीति को लेकर विधान मंडल के दोनों सदनों में काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी. इस चर्चे की शुरुआत भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष के नेता के तौर पर की थी. इसमें भाजपा के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया था, पर वह इनमें शामिल नहीं थे. फिर भी उन्हें नोटिस भेज दिया गया है. लेकिन उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, यदि कहा भी होता तब भी केके पाठक का यह कदम विधायिका की मर्यादा पर हमला है. यह निरंकुश मानसिकता की उत्कट अभिव्यक्ति है और इस पर लगाम लगाना बहुत जरुरी है. इन नोटिसों को उन्हें विचार के लिए स्वीकार किया जाना है.

सूबे में इस साल अप्रैल में पहले आंशिक और फिर पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू कर दी गई. कड़क और इकबाली आइएएस केके पाठक को इस जिम्मेदारी के लिए सबसे उपयुक्त माना गया और उत्पाद व मद्यनिषेध विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया. अपनी इमानदारी, कामकाज में सख्ती, कानून के प्रति सम्मान को लेकर पाठक की बड़ी ख्याति रही है. अपने ऐसे अनेक गुणों के कारण ही वह बार-बार चर्चा में आते रहे हैं और कहीं लंबे समय तक टिक न पाना उनकी नियति बन गई है. किसी इकबाली राजनेता या उच्च अधिकारी या अपने अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारी के विरोध के कारण हर जगह उन्हें पदमुक्त होना पड़ा है. अपने इन्हीं गुणों की वजह से उत्पाद व मद्यनिषेध विभाग से उनकी विदाई हुई. नालंदा जिले की जिस घटना को लेकर पाठक को विभाग छोड़ना पड़ा, उसमें विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उनके स्टैंड से काफी संतुष्ट थे, लेकिन इससे क्या? विशेषाधिकार हनन नोटिस का तो उन्हें सामना करना ही होगा, वह जिस किसी विभाग में पदस्थापित रहें. हालांकि यह विस्मयकारी है कि एक वरिष्ठ आइएएस को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि विधानमंडल या संसद में उठे मसलों का खंडन (या सफाई) सदनो में ही हो सकता है. ऐसे मसले पर कानूनी नोटिस विवेक-सम्मत नहीं है. कई हलकों में माना जा रहा है कि केके पाठक ने समझ-बूझ कर ही ऐसा किया होगा, उनके पास कोई ठोस तर्क जरूर होगा. विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति क्या फैसला लेती है या पाठक क्या तर्क देते हैं, यह तो अभी देखना है. लेकिन शराबबंदी अभियान की कमजोरियों पर सवाल उठाने वाले-वे चाहे जिस हलके के हों- इस आइएएस के निशाने पर रहे हैं, यह खबर बार-बार आती रही है. भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने विधान परिषद में मुख्यमंत्री से कह दिया था कि विभाग के कामकाज की आलोचना करने के कारण उक्त अधिकारी ने उन पर दस-दस मुकदमे कर दिए. मोदी ने इस अधिकारी पर अंकुश लगाने की बात कही थी. मोदी जब ऐसा कह रहे थे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में ही थे. लेकिन इन बातों पर कोई टिप्पणी नहीं की थी.

इस विशेषाधिकार सूचना पर परिषद की समिति के रूख का पता बैठक के बाद ही चलेगा. माना जा रहा है कि इसे

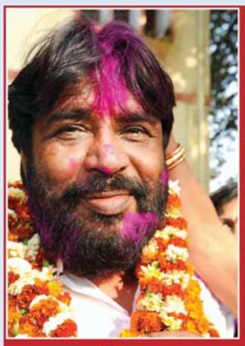
नवल किशोर यादव

लालबाबू प्रसाद

रजनीश कुमार

विचार के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा. इसके बाद ही सत्ता राजनीति के रूख का भी संकेत मिल सकेगा. बेहतर शासन व्यवस्था के लिए जरुरी है कि सत्ता के सभी अंग समन्वित और सुचारू रूप से काम करें. इसीलिए सरकार का राजनीतिक नेतृत्व अपने किसी अंग को नाराज नहीं करना चाहता है.

यह कहना कठिन है कि इस बार सूबे के सीनियर आइएएस अधिकारी को लेकर दाखिल इस विशेषाधिकार नोटिस का भविष्य क्या होगा? लेकिन फिलहाल राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा अभी भले कम हो, खामोश नौकरशाही इसकी भावी परिणति की प्रतीक्षा कर रही है. यह सही है कि केके पाठक मिलनसार और लोकप्रिय अधिकारी नहीं हैं. यह भी सही है कि अपने गैर समझौतावादी और अड़ियल रवैये के कारण अपने प्रत्येक पदस्थापन से विवादित होकर ही वे मुक्त होते रहे हैं. लेकिन यह भी सच है कि नियम-कानून का अक्षरश: पालन करने के साथ-साथ कई अन्य मामले में उनकी जोड़ का अधिकारी कम ही मिलता है, उन्हें मिसाल के तौर पर याद किया जाता है. इसके साथ ही एक बात और उत्पाद व मद्यनिषेध विभाग के प्रधान सचिव पद से उनकी विदाई की पृष्ठभूमि की वजह वह अपने सहकर्मियों के साथ-साथ अनेक सामाजिक समूहों में सकारात्मक छवि हासिल कर चुके हैं. पाठक ने सूबे के मुख्य विपक्षी दल भाजपा और इसके सबसे कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी को ही निशाने पर ले रखा था. यह उनके लिए और इस लिहाज से सरकार लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है.

बिहार के सत्ताधारी महागठबंधन के लिए प्रशांत किशोर का मसला भी कम परेशानी का कारण नहीं है. प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार के सात निश्चय के कार्यान्वयन के संदर्भ में उन्हें सरकार को सलाह देनी है. सात निश्चय से संबंधित विभागों को प्रशांत किशोर के साथ तालमेल बना कर काम करना है. बिहार विकास मिशन की पूरी व्यवस्था को पटरी पर लाने की अनौपचारिक जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी. लेकिन वह पिछले कई महीनों से बिहार से अपनी टीम के साथ बाहर हैं. कांग्रेस ने पहले तो पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने चुनाव अभियान की रणनीति के लिए उन्हें दल सलाहकार बनाया, फिर उत्तर प्रदेश भेज दिया. फिलहाल, वह अपनी टीम के साथ लखनऊ में जमे हैं और कांग्रेस की चुनावी रणनीति तैयार कर उसे सार्थक बनाए रखने की कोशिश में जुटे हैं. बिहार के राजनीतिक हल्कों में कहा जा रहा है कि वह कांग्रेस के नम्बर एक परिवार और नीतीश कुमार के बीच अनौपचारिक तौर पर सेतु का काम कर रहे हैं. इसलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद भी उनके बिहार से बाहर रहने की ही संभावना है.

मुख्यमंत्री के सात निश्चयों को जमीन पर उतारने की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. सातों निश्चय के लिए सरकार धन जारी कर रही है, विकास मिशन के लिए उपयुक्त कर्मियों की खोज तेज कर दी गई है. यह सब कुछ प्रशांत किशोर की गैर मौजूदगी में हो रहा है. विधानसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति और नौकरशाही में सबसे अधिक चर्चित नाम बन गया था. मुखयमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक व प्रशासनिक निर्णयों में उनकी राय की अहमियत बढ़ गई. जदयू संगठन को नया आकार देने, इसके कार्यालयों को हाई-फाई और पदाधिकारियों को हाई-प्रोफाइल बनाने की उन्होंने पहल आरंभ कर दी. प्रशासन के स्तर पर नौकरशाही को अधिक सक्रिय, जिम्मेदार, परिणाम-मुखी और आईटी सेवी बनाने का रोड-मैप तैयार कर लिया. वस्तुत: सूबे में महगठबंधन सरकार में एक नया सत्ता केंद्र विकसित होने लगा था. राजनीति और प्रशासन में बहुत बड़े तबके को यह स्थिति स्वीकार नहीं थी. देश में सत्ता से दूर होती जा रही कांग्रेस को प्रशांत किशोर में एक सीढ़ी दिखी, कांग्रेस का ऑफर आया और बहुतों ने राहत की सांस ली. बिहार का मौजूदा नेतृत्व प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा ही संवेदनशील है. इस मसले पर उठने वाले सवालों का तुरंत जवाब मिलता रहा है. यह सत्ता शराबबंदी को लेकर भी इसी तरह संवेदनशील है. शराबबंदी अभियान की किसी भी गड़बड़ी को उजागर करने के किसी के भी प्रयास को सत्ता अपना विरोध ही मानने लगी है. विपक्ष इन दोनों मसलों पर सरकार को बार-बार घेर रहा है. इसी माहौल में केके पाठक के खिलाफ विशेषाधिकार का मसला उठ आया है. यह अनेक संभवनाओं को समेटे हुए है. राजनेताओं व नौकरशाहों का बड़ा तबका इस नाजुक मसले पर सरकार के रूख की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है. सरकार के रूख से इन तबकों को अपनी भावी कार्य योजना तैयार करने में मदद मिलेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

"टी.आई." ब्राण्ड शटरपत्ती
क्वालिटी में सर्वोत्तम

मजबूती हमारी सुरक्षा आपकी.....
AL TM
अलीगढ़ लॉक्स
प्रा.लि.
पीरमुहानी, जगत जननी माता मन्दिर के नजदीक, पटना-3
फोन : 0612-3293208, 6500301, Email : aligarhlocks@gmail.com
❖ अपने क्षेत्र बिहार का प्रथम एवं एकमात्र TM प्रतिष्ठान ❖ नक्कालों से सावधान
❖ कृपया हमारे इस नाम से मिलते-जुलते प्रतिष्ठान को देख भ्रमित न हों।

मासिक के प्रति सजगता
सेहतनामा

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
गया के शिवम नर्सिंग होम की डॉ. रीना सिंह ने महिलाओं में मासिक धर्म में बरती गयी कोताही को लेकर चिंतित दिखीं और बतायी की महिलाएँ पीरियड के समय होने वाले दर्द को इग्नोर कर देती हैं हलांकि हल्का दर्द सामान्य बात है लेकिन असहनीय दर्द या थोड़ा सा भी दर्द महसूस हो तो महिलाओं को गायनो डॉक्टरनी से सम्पर्क अवश्य करना चाहिए। अक्सर महिलाएं पेट दर्द की शिकायत करती हैं और कुछ तो दर्द की गोली भी खाती हैं। दर्द का एक प्रमुख कारण बच्चेदानी में सिकुड़न माना गया है। लेकिन महिलाओं में बाद में भी यदि इस तरह दर्द की समस्या आये तो अवश्य गायनो डॉक्टरनी से सम्पर्क करना चाहिए। यह यूटरस में बीमारी का संकेत है। कई महिलाओं को अति मासिक (ज्यादा रक्त स्राव) की समस्या होती है उसके प्रति भी जागरूक होना आवश्यक है। एक स्वस्थ्य नारी की पहचान उसके मासिक धर्म के नियत समय पर होना है। इसका चक्र 28 दिनों का होता है और 50 के उम्र के आसपास बन्द हो जाता है। निश्चित समय पर या मासिक अन्तराल पर औरतों में होने वाले अति रक्त प्रवाह को जो लम्बे समय तक होता है उसे मेनोराजिया कहते हैं (जब रक्त 80 एम.एल. या 7 से 8 दिनों तक हो) सामन्य तौर पर यह समझा जा सकता है कि मासिक धर्म के समय अतिरक्त स्राव हो तो आप एक अच्छे ग्यानोकोलोजिस्ट से सम्पर्क करें और इसका इलाज करायें इनका मानना है कि बच्चे एक या दो ही रखें इससे अधिक होने पर भी अति रक्तस्राव की समस्या हो सकती है बच्चेदानी में संक्रमण न पकड़ने दें। इसके लिए मासिक पिरियड के समय पैड का प्रयोग करें। यदि देहात में हैं तो साफ सूती कपड़े को गर्म पानी में उबालकर फिर सूखा कर ही इसे प्रयोग करें। डॉ. राखी ने महिलाओं को सलाह देते हुआ बताया कि इसके प्रति सजग रहें और मासिक की अनियमितता के अलावा यदि अति रक्तस्राव की समस्या है तो तुरन्त अच्छे ग्यानोकॉलोजिस्ट से सम्पर्क करें। फास्ट फूड की लत, हमेशा तनाव में रहना या शराब पीना या गर्भाशय से सम्बन्धित कोई बीमारी होना. मासिक के दौरान भी कई महिलाओं को बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। आइये अब जानते हैं कुछ कुछ घरेलू उपाय • करेले का नियमित सेवन करें. • पीरियड के दौरान ड्राई फ्रूट्स और नट्स खाएँ. ग्रीन टी पिएँ. • इस दौरान आपको केला खाना चाहिए. इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और दर्द भी दूर होगा • पालक, पत्ता गोभी, कद्दू आदि खाएँ. • कब्ज पैदा करने वाले चीज पीरियड्स के दौरान न खाएँ. • खट्टी चीजों, भूने हुए चीजों और प्रोटीन से भरी दालों का सेवन न करें. ▪ भारती
डॉ. रीना सिंह
मगध मेडिकल कॉलेज गया
शिवम नर्सिंग होम, गया
Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.
A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil
Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg
Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

बलिया

इस बाढ़ से हमने कुछ नहीं सीखा

बाढ़ आने के बाद बड़ी-बड़ी योजनाएं लागू की जाती हैं और लोगों को एक आशा की किरण दिखाई देती है कि उनको कोई सुरक्षित ठिकाना मिल जाएगा. लेकिन अफसोस है कि करीब पचास वर्षों में कोई स्थायी इंतजाम नहीं हो पाया. बाढ़ पीड़ितों और बाढ़ को रोकने के लिए करोड़ों रुपये जारी होते हैं, पर सवाल यह है कि बाढ़ खत्म होने के बाद ये पैसे कहां चले जाते हैं?

मोहन सिंह

कवि-मित्र निलय उपाध्याय, बीएचयू हिंदी विभाग के प्रो. सदानंद साही और लेखक रामाज्ञा राय के साथ बलिया तक की यात्रा हुई. यह जानने और समझने की कोशिश की गई कि गंगा के किनारे बसे लोगों को बाढ़ ने इस बार क्या संदेश दिया? ये सवाल इसलिए मौजूं हैं कि पिछले चार-पांच दशक में कम से कम बलिया में दर्जनों गांव बाढ़ की कटान से देश के नक्शे से गायब हो गए. इन गावों के ज्यादातर सम्पन्न और सवर्ण लोगों की बस्तियां तो आबाद हो गईं. दलित और पिछड़ी जातियों का जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है और वो आज सड़क के किनारे जीवन-यापन करने के लिए मजबूर हैं. सरकार के लिए ये महज आकड़े हैं. बाढ़ हर साल उजाड़ती है, लेकिन नई बस्ती बसाने का इंतजाम नहीं होता. सरकारी राहत शिविर भी चलते हैं. स्वयं सेवी संस्थाएं भी दयाभाव से राहत सामग्री लेकर पहुंचती हैं. सड़क किनारे रंग-बिरंगे तिरपाल की नई बस्तियां आबाद नजर आती हैं. बाढ़ उतरने के साथ ही आम आदमी से जुड़े जरूरी सवाल लूट की एक नई कहानी पैदा कर गंगा की कोख में समा जाते हैं.

गौरतलब है कि दूबे छपरा, उदई छपरा और गोपालपुर जैसे कुछ गांव अब गंगा के कटान से विलीन होने के कगार पर हैं. इन गांवों के सुरक्षा का इंतजाम किसी सरकारी मदद से नहीं हुआ. वर्षों पहले गीता प्रेस जैसी संस्था स्थानीय लोगों के आग्रह और मदद से उन गांवों के चारों तरफ एक बांध बनवाया जो बाढ़ के समय सुरक्षा कवच का काम करता रहा. इस बांध से हर साल गंगा की लहरें अपनी ताकत की जोर आजमाइश कर टकरातीं और लौटती रहीं. समय बीतने के साथ बांध बूढ़ा हो गया. बाढ़ के पहले मरम्मत का इंतजाम होना चाहिए था जो पहले नहीं हुआ. स्थानीय लोग बांध से मिट्टी खोदकर अपने घर ठीक करते रहे. स्थानीय निगरानी और सामाजिक जिम्मेदारी का अहसास अब लोगों में उतना नहीं है. इसलिए इस बार की बाढ़ ने बांध के अस्थिपंजर को तोड़ते हुए दर्जनों गांवों को अपनी जद लेने में कामयाब हुई. इन गांवों में प्रसिद्ध साहित्कार हजारी प्रसाद द्विवेदी का गांव ओझवलिया स्थानीय सांसद भरत सिंह का सांसद आदर्श गांव भी है. गाजीपुर-हाजीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के बाएं तरफ स्थित इस गांव की दुर्दशा का आकलन इस तथ्य से ही हो जाता है कि आदर्श गांव का शिलापट्ट सड़क पर चित्त पड़ा है. अब कहा यह जा रहा है कि गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के पास लम्बे समय से 13 करोड़ रुपये का फंड अरसे से पड़ा है. जब गंगा की मार पड़ी तो इस फंड की सूध आई. स्थानीय विधायक और प्रदेश मंत्री नारद राय कहते हैं कि ''12 करोड़ से अधिक परियोजना के लिए बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना से अनुमति लेनी होती है'' बाढ़ विभाग के अधिकारी कुमार गौरव बताते हैं कि ''यह बांध करीब तीस साल पुराना है जो काम हुए भी हैं वह टुकड़ों में. प्रस्ताव पटना गया है और अनुमति मिलते ही काम शुरू हो जाएगा'' कहा जाता है कि जो पीढ़ी इसिहास से सबक नहीं लेती इतिहास उसे सजा देता है. बलिया में आई बाढ़ से नहीं लगता, किसी ने कोई सबक सीखा है. बाढ़ से पैदा हुई चुनौती का इंतजाम तो नाकाफी है ही. बाढ़ के खतरे से बड़ी आबादी को कैसे बचाया जाए इतनी भी समझ हमारी सरकारों में नहीं है. वरना क्या वजह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे रुद्रपुर से दूबे छपरा तक यू-सेप में बने बालू के टीले को नहीं हटाया जा रहा है? इस काम को करने में करीब पचास से सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे. बालू का टीला हट जाने से नदी का प्रवाह सीधा हो जाएगा. राष्ट्रीय राजमार्ग से नदी की धारा सीधे नहीं टकराएगी. गंगा का प्रवाह दक्षिण और पूर्व की तरफ होने से जलपोत परिवहन भी सुगम हो सकता है. यह काम बाढ़ का पानी उतरने के साथ ही शुरू हो सकता है, लेकिन असल बात यह है कि सन् 1971, 78 और 2003 में आई बाढ़ से अब तक किसी ने कोई सबक नहीं ली.

जो पीढ़ी इसिहास से सबक नहीं लेती इतिहास उसे सजा देता है. बलिया में आई बाढ़ से नहीं लगता है, किसी ने कोई सबक सीखा है. बाढ़ से पैदा हुई चुनौती का इंतजाम तो नाकाफी है ही. बाढ़ के खतरे से बड़ी आबादी को कैसे बचाया जाए इतनी भी समझ हमारी सरकारों में नहीं है.

अब चिंता है कि एक बांध बन जाए, तो ओझवलिया के साथ-साथ भड़सर, भीमपट्टी, धरनीपुर, सुजनीपुर, विशुनपुरा, हरिहरपुर-जवही और नंदपुर आदि गांवों को बाढ़ से छुटकारा मिल जाए. बाढ़ के साथ हर वर्ष बड़ी-बड़ी योजनाएं भी लागू की जाती हैं और स्थानीय लोगों को आश रहती है कि इस बार उनको कोई सुरक्षित ठिकाना मिल जाएगा. लेकिन अफसोस की बात यह है कि करीब पचास वर्षों में कोई मुक्कमिल इंतजाम नहीं हो पाया. बाढ़ पीड़ितों और बाढ़ को रोकने के लिए हर साल करोड़ों रुपये जारी होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि पैसे कहा जाते हैं? पेशे से वकील और स्थानीय बुद्धिजीवी अजय उपाध्याय बताते हैं कि जितना खर्च पिछले तीस-चालीस साल में राष्ट्रीय राजमार्ग को बचाने के लिए खर्च हुआ है. उतने खर्च में तो चीन की दीवार खड़ी हो जाती. जाहिर है कि बाढ़ आपदा प्रबंधन में खर्च पैसे का लेखा-जोखा बाढ़ उतरने के बाद कहां गायब हो जाता है? यह अपने आप में जांच और गहन शोध का विषय है.

ऐसे तमाम लोग जो राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अपना बसेरा बनाकर रह रहे हैं. उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि गंगा में आई बाढ़ से जब उनका आशियाना उजड़ जाता है, तो वह कहीं न कहीं अपनी बस्तियां आबाद कर लेते हैं. लेकिन अब उनको यह डर सता रहा है कि गाजीपुर-हाजीपुर मार्ग फोरलेन हो जाएगा, तो वे लोग क्या करेंगे और कहां रहेंगे? बाढ़ पीड़ित स्थानीय युवक कूलभूषण गुस्से में नजर आते हैं और उनका गुस्सा जायज भी है. उनका कहना है कि ''बाढ़ के समय सरकारी अमले की ज्यादा चिंता राष्ट्रीय राजमार्ग को बचाने की होती है. लोगों को बचाने की नहीं'' गौरतलब है कि सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में बलिया जाकर एलान किया कि गाजीपुर से हाजीपुर तक फोरलेने सड़क बनाने का डीपीआर तैयार हो गया है. औपचारिकता पूरी कर निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. लेकिन सवाल है कि क्या मंत्री जी की नजर-ए-इनायत उन बस्तियों को किसी भी तरह आबाद करने की होगी जो फोरलेन सड़क बन जाने तक उजड़ जाएंगी? ■

feedback@chauthiduniya.com

गंगा की समस्या को हमने समझा ही नहीं...

निलय उपाध्याय बताते हैं कि गंगा में मूलतः चार तरह की समस्याएं हैं-पहला बंधन, दूसरा विभाजन, तीसरा प्रदूषण और चौथा गाद. ये समस्याएं मानव निर्मित हैं. जाहिर है कि इसका समाधान हमे भी करना है. अकेले सरकार के बूते यह संभव नहीं है. प्रदूषण सिर्फ गंगा में ही नहीं, उन तमाम नदियों में है जो गंगा की सहायक नदियां हैं और गंगा में आकर मिलती हैं. इसके लिए मूलतः नदी में जल की कमी ही जिम्मेदार है. बाढ़-बरसात को छोड़कर बाकी समय गंगा में कम से कम उत्तर प्रदेश के कई शहरों में गंगा में घुटने तक पानी भी नजर नहीं आता. उद्योगों से निकलने वाले कचरे नदी में बेरोक-टोक बहाए जा रहे हैं. कानपुर और बनारस इसकी बेहतर मिशाल हैं. कानपुर का चमड़ा उद्योग तो इसके लिए बदनाम हो चुका है. अकले बनारस में अस्सीघाट से आदि केशव घाट के बीच 84 नाले अनवरत गंगा में प्रवाहित हो रहे हैं. गंगा तट के किनारे रहने वाले लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में जल-मल गंगा में बहाया जाता है. अधिकतर ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े हैं और जो चालू हैं वो इसलिए नहीं चलाए जाते, ताकि डीजल की चोरी हो सके. निलय उपाध्याय बताते हैं अहमदाबाद में जल निकासी की बेहतर व्यवस्था है. शोधित जल से दूसरे कई काम होते हैं और बचे अपशिष्ट से उर्बरक बनाया जाता है. निलय उपाध्याय का कहना है कि यह काम अगर अहमदाबाद में हो सकता है, तो देश के दूसरे शहरों में क्यों नहीं? गंगा सेवा समिति के अध्यक्ष कन्हैया त्रिपाठी बताते हैं, ''गंगा की धारा को अविरल कर दिया जाए तो गंगा कूंड़े-कचरे को अपने साथ बहा ले जाएगी. गंगा की अविरलता के बिना निर्मल धारा संभव ही नहीं है. गंगा सेवा समिति की मांग है कि गंगा में बालू खनन पर लगी पाबंदी हटाई जाए, ताकि नदी का पाट दुरुस्त हो और घाट पर पानी का दबाव कम हो.'' बनारस में गंगा किनारे घाट पर पानी के बढ़ते दबाव के प्रति आगाह करते हुए नदी वैज्ञानिक प्रो. यूके चौधरी कहते हैं कि ''बनारस में गंगा किनारे के घाट अंदर से खोखले हो चुके हैं. भूंकप का हल्का झटका भी इन्हें जमीनदोंज करने के लिए काफी होगा.'' गंगा में गाद और भराव की समस्या को समझने के लिए गंगा के पथ और प्रवाह को समझना जरूरी है. एक अध्यन के मुताबिक हरिद्वार से वाराणसी तक गंगा प्रति कोस 12 इंच ढलान के साथ बहती है. वाराणसी से भागलपुर तक दस इंच, आठ इंच और छह इंच तक घटती चली जाती है. झारखंड में साहबगंज और राजमहल के बीच गंगा का प्रवाह प्रति कोस आठ इंच है. मतलब ढलान कम होगी तो गाद और भराव अधिक होगा. बाढ़ और बरसात में नदी के साथ आई मिट्टी से नदी के गर्भ में यह गाद और भराव हर साल बढ़ रहा है. इसे निकालने और साफ करने का काम आज तक शुरू नहीं हुआ. बिहार में गंगा कुछ भरी हुई और साफ दिखती है तो उसकी वजह है हिमालय से निकली वो नदियां जो उसमें मिलती हैं. गंगा पर अत्याचार और अतिक्रमण यहां भी कम नहीं है. जल निकासी की समस्या यहां भी नाकाफी है जैसे कि पूरे देश में है. पर हालात इतने भयावह नहीं हैं कि शहर के नाले को नदी में गिरने से रोक दिया जाए तो नदी ही सूख जाए. क्या उत्तर प्रदेश के लोग ऐसा दावा कर सकते हैं कि गर्मी के दिनों में अगर शहर के नाले को रोक दिया जाए तो मिर्जापुर, इलाहाबाद और कानपुर के आस-पास नदी का प्रवाह कहीं नजर आएगा? फिर भी गंगा पर बांध और बिजली घर बनाए जाने के समर्थक हर उस शख्स को विकास विरोधी ठहराने में एक मिनट की देरी नहीं करेंगे जो ऐसे अटपटे सवाल उठाने की जुर्रत करें. लेकिन सवाल हमारी मूलगामी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा है. गंगा के जल को बाजार में बेचने के लिए डाकघरों के हवाले कर कोई चुप कैसे रह सकता है. बनारस के लोग सवाल कर रहे हैं कि गंगा नदी हो गई तो क्या उसको मां कहना बंद कर दें. उनके किनारे से हट जाएं, बसना छोड़ दें. गंगा के नाम पर होने वाले तीर्थ व्रत त्योहार सब छोड़ दें. जाहिर है कि गंगा की मौजूदा मुसीबत तो हमारी वजह से है. इसका निदान तो ढूढ़ना ही पड़ेगा. ■

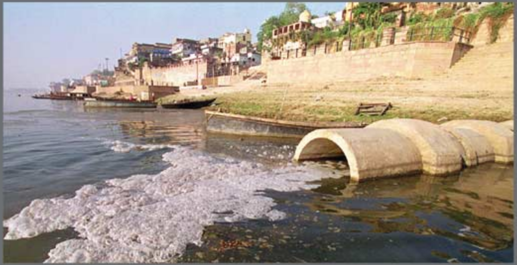

विधानसभा चुनाव के पहले यूपी में बसपा का ग्राफ नीचे

छवि की छाया से माया हलकान

2007 में सत्ता तक पहुंचाने वाला ब्राह्मण भी मायावती की कार्यशैली से दूर होता जा रहा है. ब्राह्मण नेता बृजेश पाठक का पार्टी छोड़ना बसपा के प्रति ब्राह्मणों की नाराजगी अभिव्यक्त करने वाला ही साबित हुआ है. ऐसे में केवल दलित एवं अल्पसंख्यक मत से बसपा को मनोवांछित लाभ नहीं मिल सकता. यह भी साफ है कि मुस्लिम मतदाता बसपा के ही पक्ष में रहेगा, यह तय नहीं है.

सूफी यायावर

उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले बसपा का ग्राफ नीचे उतरता दिखाई दे रहा है. बसपा के संस्थापक कांशीराम की रणनीति और मायावती की आक्रामक राजनीतिक कार्यशैली के कारण पार्टी 1989 से लेकर 2012 तक उठान पर रही, लेकिन अब उसमें थकान दिख रही है. लोकसभा चुनाव 2014 में बसपा के खाते में एक भी सीट नहीं आई. हालांकि राजनीतिक प्रेक्षक हार-जीत को सियासत का एक-दूसरे से जुड़ा हुआ पहलू ही मानते हैं. उनका कहना है कि 1984 के लोकसभा चुनाव में दो सीट पाने वाली भाजपा की आज केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है. 1984 में भाजपा को लोकसभा चुनाव शून्य हासिल हुआ था, लेकिन 2014 में उसे 80 में से 73 सीटें मिलीं. 1952 से 1989 तक 1967 और 1977 की कुछ अवधि को छोड़ दें तो कांग्रेस की सरकार लगातार रही. 1989 के बाद जो राजनीतिक बदलाव आया, उसका फायदा बसपा को मिला. बसपा ने पहले ब्राह्मण बनिया और राजपूतों के खिलाफ आक्रामकता दिखा कर दलितों को अपने साथ जोड़ा और फिर सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय का नारा देकर सवर्णों को भी अपने साथ जोड़ लिया. नतीजा यह हुआ कि 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी.

सत्ता मिलने के बाद बसपा नेता मायावती और उनके सहयोगी भ्रष्टाचार से बच नहीं सके. बसपा काल में घोटाले दर घोटाले हुए और कानून व्यवस्था पर भी संकट आया. एनआरएचएम घोटाला, दो-दो मुख्य चिकित्साधिकारियों की हत्या हुई, खनन घोटाला, मिड-डे मील घोटाला, शराब घोटाला, पार्क घोटाला, स्मारक घोटाला, लखनऊ से लेकर नोएडा तक जमीन घोटाला, पंचायत एवं विधान परिषद चुनावों में परिवारवाद एवं भाई भतीजावाद जैसे तमाम मुद्दों ने बुरी तरह घेर लिया. नतीजतन वर्ष 2012 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सपा सरकार बनी.

बसपा के राजनीतिक सफर पर समग्र नजर डालें तो पाएंगे कि 1989 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 13 सीटें मिली तो 1991 में 12 सीटें. 1993 में कांशीराम ने सपा नेता मुलायम सिंह यादव से चुनावी गठबन्धन करके दलित एवं पिछड़ों के गठबन्धन पर चुनाव लड़ा जिसका अप्रत्याशित लाभ मिला. 1991 की 12 सीट बढ़कर 67 हो गई और मत 9.52 प्रतिशत से बढ़कर 11.11 प्रतिशत हो गया. मत प्रतिशत कम बढ़ा, क्योंकि गठबन्धन में मात्र 126 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ी थी, लेकिन सीटें पांच गुना से अधिक बढ़ीं. चुनाव बाद बसपा एवं सपा की मुलायम सिंह यादव की गठबन्धन की सरकार बनी. सत्ता पाने के लिए दलित एवं पिछड़ों का गठबन्धन तो कारगर रहा लेकिन सत्ता चलाने का प्रयोग असफल रहा. बसपा ने समर्थन वापस लिया तो 02 जून 1995 को गेस्ट हाउस कांड घटित हो गया. इस घटना में बसपा को भाजपा एवं कांग्रेस दोनों दलों ने अपने-अपने तरीके से समर्थन दिया. गेस्ट हाउस कांड में भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी सहित भाजपा के कई नेताओं ने मायावती को बचाया. भाजपा के समर्थन से मायावती के नेतृत्व में बसपा एवं भाजपा गठबन्धन की सरकार बनी. बसपा में सरकार बनाने की क्षमता विकसित होने का कांशीराम का पहला सपना तो पूरा हुआ लेकिन सर्वसमाज को जोड़ने का उनका एजेंडा अधूरा रह गया. हालांकि 1996 में कांग्रेस से चुनावी गठबन्धन करके पूरा किया. 1993 में पिछड़ा-दलित गठबन्धन एवं 1996 में कांग्रेस गठबन्धन से सवर्ण एवं अल्पसंख्यक तो जुड़े, पर यह भी दीर्घजीवी नहीं रहा. बसपा को 1993 की तुलना में अधिक 296 सीटों पर चुनाव लड़ने से मत प्रतिशत 19.65 प्रतिशत हो गया लेकिन सीटें 67 ही रह गईं. चुनाव बाद किसी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू हुआ. बाद में भाजपा ने छह-छह महीने के लिए सत्ता साझा करने का

बसपा प्रमुख मायावती के लिए 2017 का विधानसभा चुनाव चुनौती है. बसपा संस्थापक कांशीराम ने जिस तरह दलित को सम्मान और सत्ता में भागीदारी की कार्ययोजना बनाई थी उसका नीजी लाभ मायावती ले चुकी हैं. वर्तमान राजनीतिक माहौल में विधानसभा 2017 के लिए बसपा का ग्राफ ठहरा हुआ है. बसपा के राजनीतिक सफर एवं चुनावी परिणाम स्पष्ट है कि पार्टी को अपने दलित आधार वोट बैंक को बनाए रखने के साथ-साथ अन्य वर्गों को भी जोड़ना जरूरी है.

समझौता करके दूसरी बार मायावती नेतृत्व में गठबन्धन सरकार बनाई. बसपा ने छह महीने की सरकार का समय तो पूरा किया, लेकिन भाजपा को मौका नहीं दिया और समर्थन वापस ले लिया. इस समर्थन वापसी के बाद विधानसभा में मार-पीट की घटना घटी. राजनीतिक दलों को तोड़कर कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाने में सफल रही और कार्यकाल पूरा किया. भाजपा की आन्तरिक कलह में कल्याण सिंह को कुर्सी गंवानी पड़ी और पहले राम प्रकाश गुप्ता और फिर राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने.

राजनाथ के ही नेतृत्व में 2002 में विधानसभा चुनाव हुआ. इस चुनाव में बसपा अकेले लड़ी जिसमें मत प्रतिशत बढ़कर 23.18 प्रतिशत और सीटें 67 से 98 हो गईं. 2002 विधानसभा चुनाव में भी किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला. राष्ट्रपति शासन लागू हुआ. कुछ माह बाद तीसरी बार भाजपा के समर्थन से मायावती के नेतृत्व में बसपा एवं भाजपा गठबन्धन की सरकार बनी. इस तरह बसपा विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में मजबूत राजनीतिक दल बनकर खड़ी हो गई. 2007 में बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही. भ्रष्टाचार और सत्ता-संसाधनों की लूट के कारण बसपा इस दरम्यान काफी बदनाम हो गई. इससे समाजवादी पार्टी फिर विकल्प के रूप में उभरी और 2012 में सपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनी. अखिलेश यादव के नेतृत्व में पांच वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. अब बसपा 2007 की तरह अकेली मजबूत पार्टी नहीं रह गई है. भाजपा पूरी ताकत से अति-पिछड़ों तथा सवर्ण और दलित मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास करती हुई चुनाव मैदान में उतर रही है. 1989 के बाद कांग्रेस भी नेता एवं मुद्दों के साथ मैदान में सक्रिय है, लेकिन दूसरी तरफ बसपा को साथ 2007 जैसी स्थिति नहीं है.

बसपा प्रमुख मायावती के लिए 2017 का विधानसभा चुनाव चुनौती है. बसपा संस्थापक कांशीराम ने जिस तरह दलित को सम्मान और सत्ता में भागीदारी की कार्ययोजना बनाई थी उसका नीजी लाभ मायावती ले चुकी हैं. वर्तमान राजनीतिक माहौल में विधानसभा 2017 के लिए बसपा का ग्राफ ठहरा हुआ है. बसपा के राजनीतिक सफर एवं चुनावी परिणाम स्पष्ट है कि पार्टी को अपने दलित आधार वोट बैंक को बनाए रखने के साथ-साथ अन्य वर्गों को भी जोड़ना जरूरी है. इसके साथ-साथ भ्रष्टाचार और धन-लोलुपता की छवि से उबरना भी मायावती के लिए बहुत कठिन चुनौती है. राजनीतिक दृष्टि से भी बसपा के लिए 2017 की स्थितियां विपरीत हैं. 2012 में बसपा को मिले 25.91 प्रतिशत वोट में भी सेंध लग चुकी है, क्योंकि बसपा के इस वोट में 7 से 8 प्रतिशत मत अति-पिछड़ों एवं सवर्णों का भी था. मायावती 2007 की तरह दलित-ब्राह्मण कार्ड के स्थान पर दलित-अल्पसंख्यक समीकरण बनाने पर जुटी हैं, लेकिन वह 2007 की तरह कारगर साबित होगा ऐसा नहीं दिखता है. बसपा के अति-पिछड़ी जाति एवं दलित व ब्राह्मण नेता पार्टी छोड़ रहे हैं. बसपा में अल्पसंख्यकों को अधिक टिकट देने के कारण दलितों का पलड़ा भाजपा की तरफ झुकता दिख रहा है. सपा सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में सत्ता का लाभ उठाने में अव्वल यादव रहे और दूसरे नंबर पर मुस्लिम रहे. इससे नाराज समुदायों के भाजपा की तरफ ध्रुवीकृत होने की संभावना है. पिछड़ी जाति की आबादी 52 प्रतिशत है. इनमें यादव, कुर्मी पहले ही बसपा से अलग हैं. बसपा के आधार वोट बैंक में शामिल रही अतिपिछड़ी जाति, मसलन, मौर्य, कश्यप, प्रजापति व अन्य जातियां भी भाजपा के साथ जुड़ती नजर आ रही हैं. दयाशंकर सिंह प्रकरण से राजपूत मतदाता बसपा से बहुत दूर चले गए हैं. 2007 में सत्ता तक पहुचाने वाला ब्राह्मण भी मायावती की कार्यशैली से दूर होता जा रहा है. ब्राह्मण नेता बृजेश पाठक का पार्टी छोड़ना बसपा के प्रति ब्राह्मणों की नाराजगी अभिव्यक्त करने वाला ही साबित हुआ है. ऐसे में केवल दलित एवं अल्पसंख्यक मत से बसपा को मनोवांछित लाभ नहीं मिल सकता. यह भी साफ है कि मुस्लिम मतदाता बसपा के ही पक्ष में रहेगा, यह तय नहीं है. मुस्लिम मतदाता का समाजवादी पार्टी से रुझान कम नहीं हुआ है. सपा पर भ्रष्टाचार एवं परिवारवाद के आरोप लगाने का बसपाई फार्मूला भी कारगर नहीं रहा क्योंकि इन आरोपों से वह खुद भी घिरी हुई है. मायावती पर टिकट बेचने के गंभीर आरोप और तमाम वरिष्ठ नेताओं के पलायन ने भी बसपा के राजनीतिक प्रभाव को काफी कम कर दिया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मायावती का मुस्लिम प्रेम!

एसआर दारापुरी

आजमगढ़ रैली में मुसलमानों को फुसलाने के लिए मायावती ने कहा कि निर्दोष मुसलमानों को आतंक के मामलों में झूठा फंसाया जाता है. मायावती का यह कथन केवल चुनावी जुमला है. यह सर्वविदित है कि मायावती के 2007 वाले मुख्यमंत्रित्व काल में सबसे अधिक निर्दोष मुसलमान को आतंकी मामलों में फंसाया गया था. मायावती के शासनकाल में गोरखपुर के तीन बम विस्फोट कांडों (22 मई 2007) समेत वाराणसी कचहरी विस्फोट कांड (23 नवम्बर 2007), फैजाबाद कचहरी विस्फोट कांड (23 नवम्बर 2007) और लखनऊ कचहरी विस्फोट कांड (23 नवम्बर 2007) में कई मुसलमान बेमानी फंसाए गए थे.

इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि 2008 में जब आतंक के मामलों में इंडियन मुजाहिदीन ग्रुप के कुछ लोग अन्य राज्यों में पकड़े गए थे तो उन्होंने यह स्वीकार किया था कि उत्तर प्रदेश में उक्त बम विस्फोट उन्होंने किए थे. इसकी सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस को भी प्राप्त हो गई थी परन्तु उससे पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस इन मामलों में दूसरे लोगों को पकड़ कर जेल भेज चुकी थी. होना तो यह चाहिए था कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इन निर्दोष लोगों को जमानत पर छुड़वा देना चाहिए था और सही मुजरिमों को पकड़ना चाहिए था. परन्तु ऐसा नहीं किया गया. इन्हीं निर्दोष लोगों में खालिद मुजाहिद भी था जिसकी बाद में फैजाबाद से बाराबंकी अदालत में पेशी पर लाते समय संदिग्ध मौत हो गई थी. इन आरोपों में बंद किए गए कुछ लोग हाल में छूट गए हैं और अधिकतर अभी भी जेलों में सड़ रहे हैं. अतः आजमगढ़ रैली में मायावती का कथन अगर सही है तो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार मायावती ही हैं.

वर्ष 2007 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थीं तो उसी समय दिल्ली में बाटला हाउस मुठभेड़ कांड हुआ था. मुठभेड़ में आजमगढ़ के तीन लड़के मारे गए थे और आजमगढ़ को आतंक की नर्सरी घोषित किया गया था. इस पर जब उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में यह कहा जाने लगा कि दूसरे राज्यों की पुलिस उत्तर प्रदेश से आतंकियों को गिरफ्तार करके ले जा रही है लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो इस पर उत्तर पुलिस ने भी फर्जी मुठभेड़ की एक योजना बनाई. इसमें 4/5 अक्टूबर 2007 की रात में सेना और पुलिस द्वारा मिल कर सेना के कार्यालय पर लखनऊ छावनी में फर्जी आतंकी हमला दिखाने की योजना बनाई गयी. इस मुठभेड़ में सेना और पुलिस को शामिल होना था और दो कश्मीरी आतंकवादियों को मार गिराया जाना था. किसी तरह इस षड्यंत्र की खबर सामाजिक कार्यकर्त्ता संदीप पांडेय को मिल गई. उन्होंने एक सेवा निवृत्त पुलिस महानिदेशक से इसे रुकवाने का अनुरोध किया. फिर तत्कालीन पुलिस महानिदेशक से बातचीत की गई और उक्त फर्जी मुठभेड़ को रुकवाने के लिए आग्रह किया गया. संदीप पांडेय ने इसके बारे में रात में ही प्रेस को सूचित भी कर दिया था. मुठभेड़ तो टल गई, पर एंटी टेररिस्ट स्क्वायड ने संदीप पांडेय को पूछताछ के लिए कई बार एटीएस मुख्यालय बुलाया था. यह बहुत खेद की बात है कि जिन दो कश्मीरी लड़कों को लखनऊ में फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने की तैयारी थी, उन्हें बाद में 25 जनवरी 2008 को दिल्ली गाज़ियाबाद बार्डर पर मार गिराया गया. इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री के रूप में मायावती ने मुसलमानों को कितनी सुरक्षा दी थी और कितना न्याय दिया था. मायावती के सख्त प्रशासन की यही परिभाषा है.

मायावती के मुख्यमंत्रित्व काल में ही 6 फरवरी 2010 को सीमा आज़ाद और उसके पति को इलाहाबाद में माओवादी होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन पर गंभीर आपराधिक आरोपों के साथ-साथ देशद्रोह का आरोप भी लगाया गया था. सीमा आज़ाद एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्त्ता भी हैं. सीमा आज़ाद पीयूसीएल उत्तर प्रदेश की संगठन सचिव भी हैं. उन्होंने इलाहाबाद में बालू का अवैध खनन करने वाले माफिया के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी. सीमा ने मायावाती के प्रिय प्रोजेक्ट गंगा-एक्सप्रेस-वे के लिए जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण किए जाने का भी कड़ा विरोध किया था. इस कारण तथा रेत माफिया के इशारे पर सीमा आज़ाद को माओवादी कह कर गिरफ्तार किया गया. उसे कई साल तक जेल में रहना पड़ा. जिला न्यायालय ने सीमा आजाद और उसके पति को उम्र कैद की सजा सुना दी है जिसके विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील चल रही है. इस घटना से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मायावती ने मुसलामानों के साथ-साथ खनन माफिया के इशारे पर किस तरह सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया. सीमा आज़ाद के मामले में जब पीयूसीएल के एक प्रतिनिधिमंडल ने मायावती के उस समय के चहेते अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध) बृजलाल से, जो अब भाजपा में चले गए हैं, मिलने का समय मांगा तो उन्होंने यह कह कर मना कर दिया कि आप लोग तो माओवादियों की हिमायत करते हैं.

आतंकवाद के मामले में मायावती के एकपक्षीय दृष्टिकोण का हाल यह था कि कानपुर बम विस्फोट मामले में दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. 23 अगस्त 2008 को हुई उस घटना में बजरंग दल के दो कार्यकर्त्ता बम बनाते समय मारे गए थे. मौके से बम बनाने का बहुत सा सामान भी मिला था. इस मामले में पुलिस ने इसे केवल एक घटना मान कर इसके पीछे के गिरोह का पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया. बाद में यह भी पता चला था कि जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में बम विस्फोट करके मुसलामानों के विरुद्ध माहौल पैदा करने का षडयंत्र चल रहा था. लिहाजा, अब जो मायावती यह कह रही हैं कि निर्दोष मुसलमानों को आतंक के मामलों में झूठा फंसाया जाता है तो उसके लिए वह स्वयं सबसे अधिक दोषी हैं क्योंकि उनके समय में ही उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक निर्दोष मुसलमान युवक आतंक के मामलों में फंसाए गए थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

दिलचस्प प्रसंगों की किताबें

अनंत विजय

अभी पिछले दिनों युवा पत्रकार- लेखक यासिर उस्मान की किताब फिल्म अभिनेत्री रेखा पर प्रकाशित हुई है. किताब का नाम है-रेखा, द अनटोल्ड स्टोरी. इस किताब के बाजार में आने के पूर्व ही खूब हलचल शुरू हो गई थी. तमाम अंग्रेजी के अखबारों और पत्रिकाओं ने इस किताब के अंश और लेखक के इंटरव्यू आदि छापने शुरू कर दिए. सोशल साइट्स पर भी इसको लेकर चर्चा रही. देखते-देखते इस किताब के पक्ष में उत्सकुता का बड़ा माहौल बन गया. उत्सुकता के इस माहौल ने किताब की मांग बढ़ा दी और प्रकाशन के चंद दिनों के बाद ही यासिर की किताब का पहला संस्करण बिक गया. अंग्रेजी में लिखी गई इस किताब को लेकर अंग्रेजी के अखबारों में कितना उत्साह था यह कवरेज में दिखाई दे रहा था. कवरेज को देखकर मन में यह सवाल भी घुमड़ रहा था कि हिंदी के अखबारों में किसी हिंदी के किताब को लेकर इतनी उत्सकुकता क्यों नहीं दिखाई देती है. याद नहीं पड़ता कि किसी हिंदी लेखक की किताब प्रकाशित होते ही किसी भी राष्ट्रीय अखबार में आधे पन्ने का इंटरव्यू प्रकाशित हुआ हो. खैर- रेखा द अनटोल्ड स्टोरी को मिली कवरेज या उसकी विषय वस्तु पर चर्चा करना अवांतर है. इस विषय पर फिर कभी विस्तार से चर्चा होगी.

हाल के दिनों में अंग्रेजी में उन चुनिंदा फिल्मी अभिनेत्रियों पर किताबें आईं जिनके जीवन के बारे में जानने की पाठकों के अंदर प्रबल इच्छा दिखाई देती रही है. पाठकों की इस इच्छा का प्रकटीकरण इन अभिनेत्रियों को लेकर उठे किसी प्रसंग के दौरान पाठकों की ललक से लगता रहा है. रेखा इन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिनका जीवन एक तिलस्म की तरह रहा है और उनके जीवन से जुड़ी कई किवदंतियां सुनाई देती रही हैं. अमिताभ से उनके संबंध से लेकर उद्योगपति मुकेश अग्रवाल की शादी और फिर अग्रवाल की खुदकुशी जैसी घटनाएं रेखा के जीवन में पाठकों को झांकने के लिए उकसाती रही हैं. यासिर की किताब में इस तरह के प्रसंगों की भरमार है.

एक अन्य अभिनेत्री हैं स्मिता पाटिल. भारतीय फिल्म इतिहास में स्मिता पाटिल सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली और संवेदनशील अभिनेत्रियों में से शीर्ष पर रहीं. जब मैथिली राव ने उन पर किताब लिखी तो पाठकों के मन में स्वाभाविक तौर पर ये जानने की इच्छा हुई थी कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें स्मिता पाटिल ने अपने से उम्र में काफी बड़े और शादीशुदा अभिनेता राज बब्बर से शादी की और फिर दोनों साथ नहीं रह सके. स्मिता पाटिल की इस जीवनी में उनकी जिंदगी का ये पन्ना गायब है. लेखिका ने स्वीकार किया है कि उसकी स्मिता पाटिल से मुलाकात नहीं हुई थी और राज बब्बर से उनकी इस जटिल संबंध के बारे में बात नहीं हो पाई. इस मायने में मैथिली की ये किताब यासिर उस्मान की किताब से थोड़ी अलग है. स्मिता पाटिल की ये जीवनी अन्य जीवनियों से भी थोड़ी अलग है. इसमें अमुक जगह पैदा हुई, अमुक जगह लालन पालन हुआ, अमुक जगह स्कूल शिक्षा ली और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए अमुक जगह गईं शैली नहीं अपनाई गई है. स्मिता पाटिल एक ऐसी कलाकार थीं जिन्हें इक्कीस साल की उम्र में नेशनल अवॉर्ड मिल गया था.

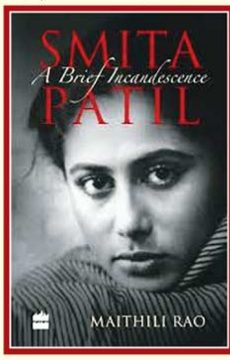

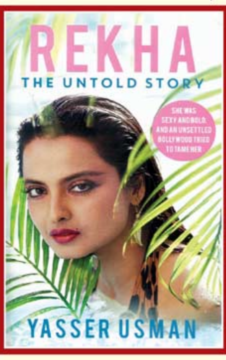

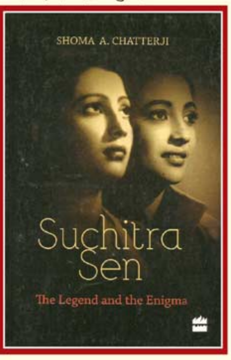

मैथिली राव की ये किताब हमें इस बेहतरीन अदाकारा की जिंदगी से जुड़ी दिलचस्प दुनिया में लेकर जाती है. इस किताब में भले ही राज बब्बर के बारे में बात ना हो लेकिन स्मिता और शबाना के रिश्तों पर लेखिका ने विस्तार से लिखा है. स्मिता पाटिल की बात शबाना आजमी के बगैर अधूरी रहती है. स्मिता पाटिल और शबाना आजमी में जबरदस्त स्पर्धा थी और लोग कहते हैं कि साथ काम करने के बावजूद उनमें बातचीत नहीं के बराबर होती थी. हालांकि किताब के लॉन्च के वक्त शबाना ने स्मिता पाटिल के बारे में बेहद स्नेहिल बातें की और यहां तक कह डाला कि उनका नाम शबाना पाटिल होना चाहिए था और स्मिता का नाम स्मिता आजमी होना चाहिए था. मौथिली राव ने स्मिता पर किताब लिखते वक्त तमाम तरह के लोगों से बात की लेकिन गंभीरता से गॉसिप को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ती चली गई.

रेखा और स्मिता के अलावा एक और अभिनेत्री में पाठकों की रुचि है वो हैं अनु अग्रवाल. 1990 में महेश भट्ट की फिल्म आशिकी के सुपर हिट होने के बाद अनु अग्रवाल भी हिट हो गई थीं. सफलता के कुछ दिनों बाद ही अनु अग्रवाल फिल्मी परिदृश्य से गायब हो गईं. वन फिल्म वंडर के नाम से बॉलीवुड में मशहूर अनु अग्रवाल ने खुद ही आत्मकथात्मक संस्मरण लिखी है जो कि अनुयूजअल, मेमॉयर ऑफ अ गर्ल हू केम बैक फ्रॉम द डेड के नाम से प्रकाशित हुई है. करीब पौने दो सौ पन्नों की इस किताब में अनु अग्रवाल ने खुलकर अपनी जिंदगी के उन पन्नों को खोला है जिसके बारे में पाठकों में जानने की इच्छा दिखाई देती है. अनु अग्रवाल का क्या हुआ? वो कहां गायब हो गईं? उन्होंने फिल्म के बाद मॉडलिंग का अपना करियर क्यों छोड़ दिया? आदि आदि. अनु अग्रवाल अपने रंग को लेकर बेहद सटीक टिप्पणी करती हैं, वो कहती हैं कि अस्सी के दशक तो फिल्मों में जो फेयर वही लवली माना जाता था लेकिन फिर उसने अपनी सांवलेपन को ही अपनी ताकत बनाया. अनु अग्रवाल ने 1980 में दिल्ली से मुंबई आने और फिर एक संगीतकार के प्रेम में पड़ने के किस्से को विस्तार से लिखा है. अनु अग्रवाल ने आशिकी की सफलता के बाद दो तीन फिल्मों में काम किया और उसके बाद एक भयंकर हादसे का शिकार हो गईं और सालों तक कोमा में रहीं. कोमा से वापस आने के बाद अनु योग और अध्यात्म में लीन हो गईं और इस किताब में दो अध्याय उनके इन अनुभवों पर है. अध्यात्म से लेकर ब्रह्म और भ्रम पर अनु ने विस्तार से लिखा है. कहना न होगा कि इन किताबों से पाठकों की ज्ञानझुधा की पूर्ति होती है.

स्मिता पाटिल, अनु अग्रवाल और रेखा पर किताबों के प्रकाशन के आसपास ही शोमा चटर्जी की किताब सुचित्रा सेन पर प्रकाशित हुई थी. किताब का नाम था-सुचित्रा सेन द लीजेंड एंड द एनिग्मा. किताब के शीर्षक से ही साफ है कि लेखिका इस लीजेंड की पहेली के बारे में इस किताब में बात करना चाह रही है. किया भी उन्होंने यही है. सुचित्रा सेन के बारे में भी तमाम तरह की किंवदंतियां चलती रही हैं. उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने सत्यजित राय की फिल्म ठुकरा दी थी. सुचित्रा सेन के बारे में ये भी कहा जाता था कि फिल्मों के छोड़ने के बाद वो सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आती थीं. कहा तो ये भी जाता है कि वो अपने लुक को लेकर बेहद संवेदनशील थीं. फिल्मों से जुड़े लोग ये भी कहते हैं कि सुचित्रा सेन ने इस वजह से दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थीं कि उनके फैन उनको बढ़ी उम्र के साथ देखें. अब इस किताब में भी लेखिका कभी सुचित्रा सेन से मिली नहीं बल्कि एकाधिक बार सिर्फ उनसे फोन पर बात हुई थी. इस किताब में लेखिका ने सुचित्रा सेन के बारे में कई दिलचस्प तथ्य बताए हैं जैसे सुचित्रा सेन पहली ऐसी अभिनेत्री थीं जो मां बनने के बाद फिल्मों में आईं और छा गईं. उनकी बेटी मुनमुन सेन के साथ भी ऐसा हुआ. शाहरुख की फिल्म बाजीगर से जुड़ा भी एक बेहद दिसलचस्प तथ्य इस किताब में है.

एक के बाद एक इस तरह की किताबों के अंग्रेजी में प्रकाशित होने के बाद फिर से ये सवाल खड़ा होने लगा है कि फिल्मों पर हिंदी में लिखने वाले लेखक गंभीरता से इस तरह का कोई प्रयास क्यों नहीं करते हैं. हिंदी में ज्यादातर लेखक फिल्मी समीक्षाओं के संग्रह को छपवाने में रुचि रखते हैं. हिंदी के प्रकाशकों को भी इस दिशा में काम करने की जरूरत है. उनको भी फिल्मों पर गंभीर लेखन करने वाले हिंदी लेखकों को चिन्हित करना होगा और उनको उन अभिनेता-अभिनेत्रियों पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना होगा ताकि उन पाठकों को हिंदी भाषा की ओर आकृष्ट किया जा सके जो कहानी कविता उपन्यास से इतर हिंदी में कुछ दिलचस्प पढ़ना चाहते हों. हिंदी पाठकों के बीच भी फिल्मों को लेकर पढ़ने की चाहत है लेकिन उनकी इस चाहत को पूरा करने का गंभीरता से उपक्रम नहीं किया जा रहा है और लेख आदि को सजा संवारकर किताब के रूप में पेश कर उनको भरमाने की कोशिश होती है. अगर हमें हिंदी को विस्तार देना है तो हमें कोशिश करनी होगी कि उन विधाओं और उन शख्सियतों के बारे में किताबें छापें जो नए पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट कर सकें. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

आशीर्वाद रजत जयंती महोत्सव सम्पन्न

हिंदी भाषा हमारी विवशता नहीं, हमारा सम्मान है. हम अपनी भाषा का सम्मान करें तो वह हमारा सम्मान बढ़ायेगी... यह विचार थे पुलिस महानिरीक्षक कैसर ख़ालिद के. उत्तर मुंबई से सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा मैं दक्षिण भारतीय होकर भी हिंदी का सम्मान बढ़ाने आया हूं. हिंदी की वजह से मुंबई ने मुझे लोकसभा का सांसद बनाया. वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शुक्ल ने कहा कि हिंदी स्वीकार्य भाषा है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है. सुप्रसिद्ध फिल्कार व्ही. शांताराम के पुत्र व पूर्व शेरिफ किरण शांताराम ने कहा कि शांताराम जी ने मराठी से ज्यादा हिंदी फिल्मों का निर्माण किया. फिल्म कलाकार अखिलेन्द्र मिश्र ने अपने तेजस्वी भाषण में कहा कि हिंदी भाषा ही नहीं, हमारी संस्कृति है. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हरीश भिमानी ने बताया कि हिंदी को लेकर हमारे प्रयास बहते पानी की तरह है. जबतक हिंदी विज्ञान और व्यापार की भाषा नहीं होगी तबतक रोजी-रोटी की भाषा नहीं हो सकती. हमें हिंदी को रोजी की नहीं रोज की भाषा बनाना है. हिंदी तबतक रहेगी जब तक संस्कृति रहेगी और संस्कृति को कौन नष्ट कर सकता है. चौथी दुनिया के संपादक संतोष भारतीय ने कहा कि हिंदी का भविष्य तभी उज्ज्वल होगा जब हम इसे प्रौद्योगिकी की भाषा बनायेंगे. उक्त विचार थे मुंबई की सुप्रसिद्ध संस्था आशीर्वाद के रजत जयंती समारोह में आयोजित हिंदी रोज़ी-रोटी की भाषा... में जो मुंबई दूरदर्शन केन्द्र में सम्पन्न हुआ.

समारोह में प्रमुख अतिथि माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने विशेष संदेश में कहा कि अपनी मातृभाषा से सबको प्यार होता है किंतु अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हमारी मौसी हैं. हमें, इनसे भी प्यार कम नहीं है, फिर हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है. उन्होंने अपील की कि सभी अध्कारियों और कर्मचारियों को हिंदी में सतत काम करते रहना चाहिए. हिंदी सभी भाषाओं को एकजुट करने की कड़ी है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

अभिव्यक्ति पर पाबंदी है और विपक्ष गायब है-प्रो. चौथी राम यादव

लोकसभा चुनाव-2014 के बाद परिस्थितियां तेजी से बदली हैं और यह पहली बार है कि लेखकों के लिखने और बोलने एवं उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं और लेखकों की हत्याएं हो रही हैं. यह शुद्ध रूप से उग्र हिंदुत्ववादी आरएसएस की सरकार है जो कि अपनी पूर्ववर्ती एनडीए सरकार से भी भिन्न है. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी लेखकों और मीडिया पर इस तरीके के हमले नहीं हुए. आरएसएस का निच्छद्म राज है और विपक्ष गायब है.

ये बातें वरिष्ठ साहित्यकार एवं आलोचक प्रो. चौथी यादव ने सोमवार को मैदागिन स्थित पराड़कर स्मृति सभागार में वनांचल लेखक एवं पत्रकार मंच तथा रीडिंग रूम्स पब्लिकेशन, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'साहित्य और मीडिया में सत्ता की घुसपैठ' विषयक गोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता कही. उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने चाय का नारा दिया जो बिहार विधानसभा आते-आते गाय में बदल गया. पहली बार तो चाय चल गई लेकिन गाय पर जनता ने मोदी को बाय-बाय कर दिया. उन्होंने संक्षेप में इसे कहा, लोकसभा में चाय-चाय, विधानसभा में गाय-गाय, जनता ने कर दिया बाय-बाय.

सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतक चौधरी राजेंद्र ने बात को आगे बढ़ाते हुए नेहरू और इंदिरा के जमाने में साहित्य और पत्रकारिता में सत्ता की घुसपैठ के उदाहरण गिनाए. उन्होंने कहा कि साहित्य से नमक नहीं खरीदा जा सकता. ऐसे में लेखक और मीडिया समाज को क्या बदलेंगे जब मक्सिम बुर्की रूस को टूटने से नहीं बचा पाये. राजनीतिक कार्यकर्ता सुनील यादव ने सवाल उठाया कि सत्ता अगर मीडिया में घुसपैठ कर रही है तो पत्रकारों ने भी सत्ता के सामने अपना समर्थन कर दिया. उन्होंने कहा कि साहित्य मीडिया की तुलना में ज्यादा जन पक्षधर है. उन्होंने सत्ता के देखने के नजरिये पर बात की और कहा कि सबसे अहम सवाल सत्ता के पुनर्गठन का है और यह है कि वे औजार क्या हों जिससे सत्ता को बदला जाये. कार्यक्रम में युवा कथाकार मनीष आवारा के पहले कहानी संग्रह 'वापसी' का विमोचन किया गया. सोनभद्र के जिला पंचायत अध्यक्ष अनिल यादव के मुख्य अतिथित्व में आयोजित हुए इस समारोह में मनीष आवारा के कहानी संग्रह पर कथाकार रामानुज मिश्र ने संग्रह में शामिल एक कहानी 'समर्पण' पर विशेष चर्चा करते हुए कहा कि मनीष की कहानियों में ग्रामीण संवेदना झलकती है और स्त्री पात्रों की प्रधानता है. समारोह के मुख्य अतिथि एवं जिला पंचायत अध्यक्ष, सोनभद्र अनिल यादव ने कहा कि मनीष आवारा की कहानियां यथार्थ से परिचय कराती हैं और उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में सोनभद्र का नाम ऊंचा किया है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साईं वंदना

साईं-साहित्य के कुछ आधार

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस पृथ्वी पर अवतार, सद्गुरु एवं अन्य संत जन भिन्न-भिन्न स्थानों पर विभिन्न कालों में महान एवं दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन करने में समर्थ होते हैं. उनमें से कुछ महान पुरुष जैसे कि भगवान बुद्ध, भगवान ईसामसीह, मुहम्मद साहब और गुरुनानक ने नये धर्मों की स्थापना भी की. औरों ने मानव-जाति के बेहतर जीवन और अपने संपर्क में आने वाली जीवात्माओं के आध्यात्मिक विकास के लिए नये मार्ग दिखाये हैं. जब वे ईश्वर द्वारा सौंपे गये ईश्वरीय एवं सर्वजागतिक कार्य करते हैं, तब प्रकृति की महाशक्तिशाली अदृश्य शक्तियों की सहायता उन्हें स्वतः ही प्राप्त होती है. उनमें ऐसी अलौकिक शक्तियों का होना और उनके द्वारा उनको प्रयोग में लाना उनका महत् स्वभाव है. उनकी ये शक्तियां उन शक्तियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं जो मनुष्य-समेत सभी प्राणियों में विद्यमान हैं. उन्हें 'दिव्य-शक्ति' कहते हैं. हिंदू परंपरा में 'देवता' शब्द इसी 'दिव्य' शब्द से बना है. जब सद्गुरु मानव-रूप में कार्य करते हैं, तो वे अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार मानवीय एवं दैविक शक्तियों तथा गुणों को व्यवहार में लाते हैं. जैसे मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता और शक्ति के कारण पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों में सबसे बढ़कर है, वैसे ही ये दिव्य शक्तिशाली विभूतियां अत्यधिक उन्नत बुद्धि एवं अपार क्षमता से युक्त रहती हैं, जो कि मनुष्य की क्षमताओं से कहीं आगे हैं. जैसे किसी पशु का उपचार करते समय मनुष्य को हमेशा यह नहीं सोचना पड़ता है कि उसे पशु-चिकित्सा या औषधि-विज्ञान का ज्ञान है, वैसे ही सद्गुरु भी जब किसी मनुष्य अथवा अन्य प्राणी की भौतिक और आध्यात्मिक सहायता या उससे व्यवहार करते हैं तो वे अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए सहज रूप में करते हैं. यह उनमें विद्यमान दया का महान गुण है, जो उन्हें दूसरों की सहायता करने और लोगों का दुख वहन करने के लिए प्रेरित करता है.

दूसरी ओर जब लोग ऐसे ईश्वरीय व्यक्तियों के साक्षात संपर्क में आते हैं, तो वे उनकी चमत्कारपूर्ण आध्यात्मिक शक्तियों की लीला देखकर बहुत आश्चर्य-चकित एवं भाव-विह्वल हो जाते हैं. साथ ही जिस प्रकार दयालु होकर लोगों के कल्याण के लिए सद्गुरु इन शक्तियों का उपयोग करते हैं, उससे लोग भाव-विभोर हो उठते हैं. यही है- भक्ति की आरंभिक अवस्था. श्री शिरडी साईं बाबा जब देही-रूप में थे, तब जो भी उनके संपर्क में आया, सभी के साथ ऐसा ही होता था. किसी भी व्यक्ति की किसी भी समस्या का (चाहे वह सांसारिक या आध्यात्मिक हो) तुरंत दीर्घकालिक समाधान करने में बाबा की क्षमता व्यापक एवं अचूक थी. यहां तक कि खापर्डे, बूटी, काका साहेब दीक्षित, चांदोरकर आदि जैसे उस समय के अत्यधिक प्रभुत्व-संपन्न और समर्थ लोग भी बाबा के समक्ष अति साधारण लगते थे. इसलिए अपने भौतिक या सामाजिक स्तर को भूलकर वे बाबा के प्रति पूर्णतया समर्पित एवं नतमस्तक हो जाते थे.

श्री साईंनाथ महाराज के दिव्य व्यक्तित्व से पूर्णतः अभिभूत और उनकी दया के अत्यधिक ऋणी होकर ये भक्त बाबा की महिमा का प्रचार एवं प्रसार करते रहते थे. विभिन्न सामाजिक मेलजोल के दौरान जब भी उन्हें अवसर मिलता था, वे बाबा का यशोगान किया करते थे. दासगुण जैसे उनके उत्साही एवं निष्ठावान भक्तों ने कीर्तनों, गाथाओं और लोकवार्ताओं के द्वारा महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में बाबा का नाम बहुत प्रसारित किया. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बनें आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

देर आये दुरुस्त आये गम्भीर की टीम इंडिया में वापसी

रोहित शर्मा को लगातार फ्लॉप होने के बावजूद टीम में मौका दिया जा रहा है जबकि गौतम गम्भीर ने घरेलु क्रिकेट में लगातार रन बनाने के बावजूद उनके चयन की उपेक्षा की जा रही थी. खैर काफी समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे गौतम गम्भीर को आखिर टीम इंडिया में दोबारा खेलने का मौका मिला है.

सैयद मोहम्मद अब्बास

भारत और न्यूजीलैंड के बीच में क्रिकेट सीरीज शुरू हो गई. इस सीरीज में टीम इंडिया एक बार फिर अपनी धरती पर मजबूत लग रही है. स्पिनरों के बल पर टीम इंडिया ने पहले टेस्ट में इसकी शुरुआत करते हुए न्यूजीलैंड को पराजित भी किया. दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. इस टीम में चोटिल केएल राहुल के स्थान पर गम्भीर को टीम इंडिया में शामिल किया गया है. गौतम गम्भीर की 2 साल बाद भारतीय टीम में वापसी हुई है. घरेलु स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने के बाद चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है. दूसरी ओर ईशांत शर्मा की जगह जयंत यादव भी टीम इंडिया में नया चेहरा हैं.

दरअसल मुख्य चयनकर्ता के रूप में अपनी आखिरी पारी खेल चुके संदीप पाटिल ने गौतम गम्भीर को नजरअंदाज कर दिया था लेकिन अब ऐसा नहीं है गम्भीर भी अब टीम इंडिया में अपना जलवा दिखाने को बेताब हैं. बता दें कि गम्भीर को पहले टेस्ट में न शामिल करने पर संदीप पाटिल की चौतरफा आलोचना भी हो रही थी. संदीप पाटिल ने अपने कार्यकाल में कई बड़े फैसले किये हैं. उनके चयनकर्ता रहते हुए भारतीय क्रिकेट में काफी बदलाव देखने को मिला. इसी दौर में सचिन को संन्यास लेना पड़ा जबकि वीरू जैसे खिलाड़ी को भी संन्यास के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा. दरअसल उनके आखिरी चयन में भी कुछ खामियां दिख रही थीं. उन्होंने रोहित शर्मा को लगातार फ्लॉप होने के बावजूद टीम में मौका दिया है जबकि गौतम गम्भीर ने घरेलु क्रिकेट में लगातार रन बनाने के बावजूद उनके चयन की उपेक्षा की जा रही थी. खैर यह बात तो होती रहती है. किसी को मौका मिलता है तो किसी को नहीं. काफी समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे गौतम गम्भीर को आखिर टीम इंडिया में दोबारा खेलने का मौका मिला है. गम्भीर को न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना होगा ताकि टीम इंडिया में उनकी जगह मजबूत हो सके. गम्भीर के करियर पर नजर दौड़ायी जाये तो विवाद भी उनके साथ रहा है. हाल में गम्भीर लगातार टीम इंडिया के कप्तान पर भी हमला बोल रहे थे. किसी दौर में टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद ओपनर के रूप में शामिल रहे गौतम गम्भीर अब अपने पुराने साथियों पर अक्सर निशाना साधते हुए दिखायी देते हैं. अभी हाल में उन्होंने धोनी की फिल्म की आलोचना की है, हालांकि बाद में वह पलट गये थे. इतना ही नहीं पूर्व में वह विराट पर भी ताने कसते दिखे हैं. करियर को उड़ान देने में लगे गम्भीर लम्बे समय से टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे. इससे पहले उनके चयन न होने पर सवाल भी खड़े किये जा रहे थे. इसके तार कभी धोनी से जोड़े जाते थे तो कभी विराट पर इसका सारा ठीकरा फोड़ा जाता था.

जानकारों की माने तो गम्भीर का धोनी व विराट के साथ रिश्ता बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा है. अक्सर मैदान पर गम्भीर अपने नाम की तरह गम्भीर नहीं दिखते हैं बल्कि मैदान पर वह विरोधी टीम से भिड़ते हुए दिखे हैं. याद करिये आईपीएल 2013 का वह मैच जब विराट से गम्भीर की तू-तू मैं हो गई थी. इतना ही नहीं दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि साथी खिलाड़ियों को बीच-बचाव करना पड़ा था. हाल ही में एक रणजी मैच के दौरान बंगाल के कप्तान मनोज तिवारी से भी उनका विवाद हो गया था. उनका खराब बर्ताव भी टीम इंडिया में वापसी का रोड़ा साबित हो रहा था. सीनियर और जूनियर के चक्कर में भी गम्भीर का अब राष्ट्रीय टीम में जगह बनाना मुश्किल दिख रहा था. अभी हाल में ही माही और विराट की कप्तानी को लेकर भी गम्भीर ने तीखा प्रहार करते हुए बोला कि सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि दस खिलाड़ी टीम को जीताते हैं. उनका कहने का मतलब है कि पूरी टीम का प्रदर्शन ही मायने रखता है. टीम जीतती है तो इसमें पूरी टीम का योगदान रहता है न सिर्फ कप्तान का. इतना ही नहीं उन्होंने धोनी को मैच फिनिशर होने की बात से भी इन्कार किया जबकि वह विराट को अब टीम इंडिया का सबसे बड़ा मैच फिनिशर बता रहे हैं. साथ ही गौती ने धोनी की कप्तानी पर भी सवाल उठाया था.

हाल के दिनों में अगर गौतम गम्भीर के प्रदर्शन पर नजर दौड़ायी जाये तो इतना तो साफ है कि उनका प्रदर्शन घरेलु क्रिकेट में शानदार रहा है. दिलीप ट्रॉफी के दौरान गम्भीर ने अपने बल्ले का लोहा मनवा कर चयनकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित किया था. गम्भीर ने दिलीप ट्रॉफी की पांच पारियों में 71.20 के औसत से 356 रन बनाये थे. आईपीएल में उनका बल्ला रनों का अम्बार लगा रहा है लेकिन चयन के नाम पर मौका तक नहीं दिया जा रहा था. आईपीएल नौ में गौती के बल्लों से अच्छे रन निकले. उन्होंने आईपीएल के 15 मैचों में 501 रन बनाये, जबकि दिलीप ट्रॉफी की पांच पारियों में भी उनके बल्ले की ताकत देखने को मिली. उन्होंने 321 रन बनाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए अपना दावा भी पेश किया. इससे पूर्व रणजी के रण में जबकि 2014-15 रणजी सीजन में 9 मैचों में 43 की औसत से 569 रन बनाये. इसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल था. करीब दो साल पूर्व गम्भीर ने आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में उतरे थे लेकिन बल्ले की नाकामी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था. ओवल टेस्ट में उनके बल्ले से केवल तीन रन ही निकले थे. गौतम गम्भीर ने भारत की ओर से 56 टेस्ट की 100 पारियों में 4046 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने नौ शतक भी जड़े हैं. खराब फॉर्म के चलते उनको टीम से बेदखल कर दिया गया था. यह बात भी सत्य है कि भारत की कई शानदार जीत के गवाह रहे हैं गौतम गम्भीर. मौजूदा समय में उनकी दावेदारी थोड़ी कमजोर इसलिए लग रही थी, क्योंकि टीम में अभी चार सलामी बल्लेबाज मौजूद हैं. उनमें रोहित शर्मा, शिखर धवन, मुरली विजय और लोकेश राहुल के रूप में मौजूद है. अब केएल राहुल के चोटिल होने के बाद बतौर सलामी बल्लेबाज टीम में शामिल किया गया है.

दूसरी ओर रोहित शर्मा भी टेस्ट टीम में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. टेस्ट टीम में उनकी जगह बनती नहीं दिख रही थी लेकिन रोहित अब भी टीम में बने हुए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने पहले टेस्ट में कुछ रन बनाये. रोहित शर्मा भले ही वन डे के सफल बल्लेबाज माने जाते हों लेकिन टेस्ट में फुस्स साबित होते हैं. उन्होंने 18 टेस्ट मैचों में केवल दो शतक की मदद से 946 रन बनाये हैं. 32.62 औसत भी उनका कोई खास नहीं रहा है. यह टेस्ट क्रिकेट में अच्छा औसत नहीं माना जाता है. इतना ही नहीं उनकी आखिरी की छह पारियों पर नजर दौड़ायी जाये तो उनके चयन पर सवाल खड़ा किया जा सकता है. उन्होंने वेस्टइंडीज सीरीज में भी रन नहीं बनाये थे. न्यूजीलैंड से पूर्व उन्होंने आखिरी छह टेस्ट पारियों 41, 09, 00, 01, 23 और 02 रन का स्कोर बनाया है लेकिन अब भी वह चयनकर्ताओं की पहली पसंद बने हुए हैं. उनका खामोश बल्ला रनों के लिए तरस रहा है. उन्होंने सात पारियों में एक बार केवल अर्धशतक जमाये हैं. इससे पूर्व दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वह केवल एक रन ही बना सके. ऐसे में उनके चयन को लेकर विवाद तो होना ही है. रोहित अगर घरेलु जमीन पर रन बना भी देते हैं, तो कोई आम बात नहीं होगी लेकिन विदेशी धरती पर उनका पैर तक नहीं चलता है. अगर गेंद में थोड़ी सी स्विंग हो तो रोहित की बल्लेबाजी की पोल भी खुल जाती है. टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. उन्होंने पिछली सात टेस्ट में 288 रन ही बना सके हैं. उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है लेकिन वह किसी तरह से टीम में जगह बचाने में कामयाब रहे हैं. चेतेश्वर पुजारा का भी बल्ला भी अरसे से खामोश चल रहा है, हालांकि उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया है. कुल मिलाकर देखा जाये तो गम्भीर को मिले मौके को भुनाना होगा. गौतम गम्भीर को अपने बल्ले की दहाड़ से अपने आलोचकों को करारा जवाब देना का सुनहरा मौका है. ■

पंकज आडवाणी ने भी बढ़ाया देश का मान

गीत सेठी के बाद पंकज आडवाणी

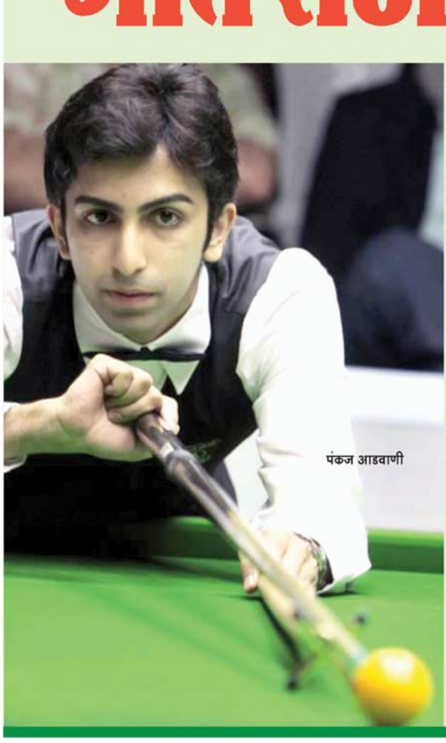

पंकज आडवाणी

भारत में क्रिकेट को भगवान की तरह पूजा जाता है. यहां कोई विराट का दीवाना है तो कोई धोनी का. क्रिकेट में अपार धन अक्सर खिलाड़ियों को शोहरत और दौलत से रूबरू कराता है. दरअसल इस खेल की लोकप्रियता के आगे अन्य खेल दम तोड़ने की कगार पर पहुंच गये हैं लेकिन यह बात भी सत्य है कि अन्य खेलों के खिलाड़ियों का प्रदर्शन विश्व स्तर का नहीं होता है. इस कारण से यह खेल पिछड़ भी जाते हैं. बात अगर क्रिकेट की जाये तो इसमें सचिन ने खूब नाम कमाया. आलम तो यह है कि उन्हें अब रिकॉर्ड पुरुष कहा जाता है. दूसरे खेलों में चेस और स्नूकर ऐसे खेल हैं जिसकी चर्चा बेहद कम की जाती है. हालांकि इस खेल में भारतीय खिलाड़ी लगातार अपनी अलग पहचान बना रहे हैं. विश्वनाथन आनंद एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने खेल में सचिन से कम नहीं हैं. उन्होंने चेस की दुनिया में भारत को कई बार गौरव के पल दिये हैं. उसी तरह स्नूकर में पंकज आडवाणी लगातार अपने प्रदर्शन से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं. स्नूकर में पंकज आडवानी कोई नया नाम नहीं है. वह लगातार देश के लिए कई खिताब अपने नाम कर चुके हैं. स्नूकर में उनका कद अब बढ़ गया है कि क्योंकि उन्होंने अभी हाल में 6 रेड स्नूकर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ा दिया है. इस देश की विड्मना देखिये उनकी जीत की चर्चा तक नहीं होती है.

गीत सेठी

भारत में स्नूकर जैसे खेल को लेकर उत्साह नहीं देखा जाता है लेकिन इसमें भाग लेने वाले कई भारतीय खिलाड़ियों की तूती पूरे विश्व में बोलती है. पंकज आडवानी से पूर्व किसी जमाने में गीत सेठी इस खेल में देश का गौरव हुआ करते थे. इंग्लिश बिलियर्ड्स के पेशेवर खिलाड़ी गीत सेठी ने 90 के दशक में कई खिताब जीतकर इस खेल में भारत को शीर्ष पर पहुंचाया. 1992, 93, 95, 98 और 2006 में विश्व प्रोफेशनल बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप जीतकर पूरी दुनिया में अपना डंका बजवाया. गीत सेठी ने विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स का खिताब 85, 87, 2001 में जीतकर भारत का झंडा बुलंद किया. उन्हीं की तरह अब पंकज आडवाणी स्नूकर व बिलियर्ड्स जैसे खेल में भारत का नाम रौशन कर रहे हैं. उन्होंने दस साल की आयु में बिलियर्ड्स खेल में अपनी रूचि दिखानी शुरू कर दी. वह अपने बड़े भाई के साथ अक्सर इस खेल की जानकारी लेने लगे. 17 साल की आयु में पंकज स्नूकर के राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का खिताब जीतकर अपना लोहा मनवाया. पंकज ने एशियन गेम्स में भारत के लिए दो स्वर्ण पदक साल 2005 और 2010 में जीता था. पंकज ने मात्र 19 वर्ष की आयु में तीन विश्व खिबात जीतकर नया इतिहास रच डाला. यह भी संयोग है कि स्नूकर व बिलियर्ड्स दोनों वर्गों में परस्पर कामयाबी हासिल की है. इतना ही नहीं उन्होंने सात बार विश्व चैम्पियन रहे गीत सेठी को करीब छह घंटे के कड़े संघर्ष के बाद पराजित कर सेठी को चौंका दिया. मशहूर क्यू खिलाड़ी पंकज ने 15 बार के वर्लड चैम्पियन बनने का गौरव प्राप्त किया. उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 2009 में पद्मश्री, 2005-06 में खेल रत्न और 2004 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला. लगातार खिताब जीतने वाले इस खिलाड़ी को एक बार फिर पद्म पुरस्कार देने की सिफारिश की गई है. कुल मिलाकर अगर बिलियर्ड्स और स्नूकर में भारत अगर इतना चमक रहा है तो वह केवल पंकज आडवाणी जैसे स्टार खिलाड़ियों की बदौलत. ■

भारत में स्नूकर जैसे खेल को लेकर उत्साह नहीं देखा जाता है लेकिन इसमें भाग लेने वाले कई भारतीय खिलाड़ियों की तूती पूरे विश्व में बोलती है. पंकज आडवानी से पूर्व किसी जमाने में गीत सेठी इस खेल में देश का गौरव हुआ करते थे.

feedback@chauthiduniya.com

ऋतिक रोशन ने किया कृष 4 का एलान

अपनी फिल्मों की ऐलान के लिए एक्टर्स आजकर नए-नए तरीके आजमाते हैं, लेकिन ऋतिक रोशन ने कृष 4 का एलान करने के लिए जो तरीका खोजा है, वो एकदम निराला है.

ऋतिक के डैड राकेश रोशन आजकल कृष की पटकथाप में बिजी हैं. कुछ दिन पहले ख़बर आई थी कि इसमें उनकी मदद ऋतिक के बेटे रेहान और रिदान कर रहे हैं. अब ऋतिक ने भी कृष 4 की घोषणा कर दी है, मगर इसमें उनकी मदद कर रहे हैं खुद गणपति बप्पा. ऋतिक ने सोशल मीडिया में गणपति की एक बड़ी सी प्रतिमा का फोटो शेयर किया है, जिसमें बप्पा कृष 4 का कॉस्ट्यूम पहने हुए दिखाई दे रहे हैं. इस फोटो पर ऋतिक ने कैप्शन लिखा है-कृष 4 के लिए गणपति का आशीर्वाद.

कृष 4 इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है. बच्चों के बीच बेहद हिट ये बॉलीवुड की पहली सुपर हीरो फ्रेंचाइजी है. इसकी शुरुआत कोई मिल गया से हुई थी, जिसमें ऋतिक ने एक ऐसे युवक का रोल निभाया था, जो मंदबुद्धि है, लेकिन एक एलियन से सुपर पॉवर्स मिलने के बाद वो तीक्ष्ण बुद्धि हो जाता है.■

अजय ने कहा...

यहां के अवॉर्ड पैसा बनाने वाले होते हैं

अजय देवगन यूं तो बहुत ही कम बोलते हैं लेकिन आजकल वो पूरे फॉर्म में हैं और काफी लोग इस बात से थोड़ा परेशान हैं. कुछ दिन पहले उन्होंने केआरके और करण जौहर की मिट्टीपलीत करने की कोशिश की थी और अब वो दो टूक हर बॉलीवुड एक्टर पर निशाना साध चुके हैं.

देश-विदेश के प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल्स में प्रशंसा और कई अवॉर्ड्स से नवाजी जा चुकी फिल्म *पार्च्ड* के निर्माता अजय देवगन से जब पूछा गया कि आमतौर पर वह किसी अवॉर्ड फंक्शन्स में हिस्सा नहीं लेते, जबकि *पार्च्ड* कई अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सवों में पुरस्कार पा चुकी है. इस पर अजय देवगन ने धमाकेदार जवाब दिया.

अजय देवगन ने कहा कि ये उस तरह के अवार्ड नहीं हैं जो हमारे यहां (बॉलीवुड) बांटे जाते हैं, जहां नाच गाना होता है और जो पहले आ जाए उसको अवार्ड थमा दिया जाता है.

मैं वैसे अवॉर्ड में नहीं जाता हूं. वो अवॉर्ड्स, अवॉर्डस नहीं होते. वो आप भी जानते हैं. वो टीवी शो होते हैं. अजय ने वॉर्ड शोज को पैसा कमाने का उपक्रम बताते हुए कहा उन अवॉर्ड्स शोज में जितने ज्यादा एक्टर्स आएंगे, जितने ज्यादा भरेंगे. उतना ज्यादा चैनल उसे खरीदेगा और उतने ज्यादा उससे पैसे बनेंगे. ये पैसे बनाने वाले अवॉर्ड्स हैं.

अब ज़ाहिर सी बात है कि अजय देवगन का निशाना शाहरूख खान से लेकर करण जौहर तक सब पर था. अजय देवगन यहीं नहीं रूके उन्होंने आगे कहा कि ये अवार्ड शो नहीं होते हैं, इन्हें टीवी शो कहा जाता है. अब उनकी ये एक बात कितने लोगों को गुस्सा दिलाएगी पता नहीं लेकिन अवार्ड शो के बारे में कई एक्टर्स काफी कुछ कह चुके हैं. अजय देवगन ने तो अवार्ड शो का उसी ज़माने से बॉयकॉट कर दिए थे जब फिल्म *ज़ख्म* और *द लेजेंड ऑफ भगत सिंह* के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला लेकिन किसी भी अवार्ड शो में उन्हें पूछा तक नहीं. वैसे अजय देवगन के अलावा कई बॉलीवुड स्टार ने भी ऐसे अवार्ड शो का बायकॉट किया है.

अक्षय ने बताया, परफॉर्मेंस दो अवार्ड लो

अक्षय कुमार ने एक बार साफ कहा था कि कितने लोग उन्हें परफॉर्मेंस के लिए अप्रोच कर चुके हैं. जितने लोग अवार्ड शो में परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें एक अवार्ड दे ही दिया जाता है.

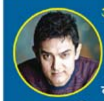

आमिर खान का दर्द

आमिर खान ने भी अवार्ड शो का काफी समय से बॉयकॉट कर दिया हैं. कारण था उनकी फिल्म लगान को अवार्ड शो में जगह नहीं मिला और उनका कारण गलत भी नहीं था. आमिर तो अपनी प्रोड्यूस फिल्मों की क्लिप भी नहीं देते नॉमिनेशन के लिए.

रणवीर सिंह-सोनाक्षी सिन्हा

रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा ने यूं तो अवार्ड शो बॉयकॉट नहीं किए हैं पर उन्होंने अपनी फिल्म लुटेरा के लिए जमकर शिकायत की थी और साफ कहा था कि उनकी फिल्म के साथ नाइंसाफी की गई.

प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा ने भी *मैरी कॉम* के लिए अवार्ड न मिलने पर खुलकर नाराज़गी ज़ाहिर की थी और ये अवार्ड गए थे *हैप्पी न्यू ईयर* के लिए दीपिका पादुकोण को.

आशुतोष गोवारिकर

आशुतोष गोवारिकर तो आईफा अवार्ड में इतने नाराज़ हो गए थे कि बेस्ट फिल्म *जोधा अकबर* की ट्रॉफी लेते वक्त उन्होंने माइक पर कहा कि प्रियंका मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं पर तुम्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कैसे मिल गया जब ऐश्वर्या राय जोधा अकबर के लिए नॉमिनेटेड थी, ये मैं नहीं समझ पाया!

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

फ्लैश बैक

रेखा : द अनटोल्ड स्टोरी

बिन ब्याही मां की बेटी हैं रेखा, पिता के थे चार महिलाओं से संबंध

प्रवीण कुमार feedback@chauthiduniya.com

एक्ट्रेस रेखा की ऑटोबायोग्राफी *रेखा : द अनटोल्ड स्टोरी* इन दिनों चर्चा में है. इस बुक में उनकी लाइफ के कई राज़ खोले गए हैं. हालांकि, इसके पहले भी रेखा को लेकर कई बातें कही जा चुकी हैं. लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि वे उनके पैदा होने तक उनके माता-पिता ने शादी नहीं की थी. इसके अलावा उनके पिता के संबंध चार महिलाओं से थे. रेखा का एक भाई और उनकी छह बहनें हैं. बगैर शादी के सिंदूर और शूटिंग के सेट पर रेखा को किए गए चुम्बन सहित कई अन्य चौकाने वाले किस्सों का जिक्र है.

मद्रास (अब चेन्नई) में जन्मीं रेखा तमिल सिनेमा के जाने माने एक्टर दिवंगत रामास्वामी, (जिन्हें जैमिनी गणेशन के नाम से जाना जाता है) की बेटी हैं. जैमिनी गणेशन के संबंध चार महिलाओं से रहे हैं. 1940 में महज 19 साल की उम्र में उन्होंने अलामेलु से शादी की थी. इसके बाद उनके एक्ट्रेस पुष्पावली, सावित्री और जूलियाना से संबंध रहे. ख़बरों की मानें तो उनकी जिंदगी में आई आखिरी महिला जूलियाना उनसे 36 साल छोटी थीं. अलामेलु से जैमिनी को चार बेटियां हुईं, जिनमें से तीन (रेवती, कमला, जयलक्ष्मी) डॉक्टर और एक (नारायणी) जर्नलिस्ट हैं. पुष्पावली से दो बेटियां हुईं, जिनमें से रेखा बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं.

रेखा की शादी पर रहा सस्पेंस

1973 में रेखा का अफेयर बॉलीवुड एक्टर विनोद मेहरा से रहा. कहा जाता है कि दोनों ने शादी कर ली थी. हालांकि, इस बात की ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई थी. रेखा ने एक इंटरव्यू के दौरान शादी की ख़बर को अफवाह बताते हुए विनोद को अपना शुभचिंतक बताया था. विनोद के अलावा, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से उनके अफेयर ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. 1990 में रेखा की शादी दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई थी, जिन्होंने सालभर के अंदर सुसाइड कर लिया था. रेखा आज भी अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं और शादीशुदा महिलाओं की तरह लाइफ जीती हैं. हालांकि, इसके पीछे का राज अब भी बरकरार है.

किस वजह से रेखा के साथ अमिताभ ने नहीं किया काम?

जया बच्चन के कहने पर ही अमिताभ ने रेखा के साथ एक्टिंग करना छोड़ दिया था. जब रेखा ने सवाल किया तो बिग बी ने कहा, मैं कुछ भी नहीं बता सकता. मुझसे इस बारे में न पूछिए. किताब में 1978 के उनके एक चर्चित इंटरव्यू का भी ज़िक्र है, जिसमें रेखा ने कहा था कि उन्हें किस तरह जया के दर्द का अहसास हुआ-मैंने एक बार पूरी बच्चन फैमिली को देखा था. वे फिल्म *मुकद्दर का सिकंदर* के ट्रायल शो के लिए प्रोजेक्शन रूम में आए थे. जया आगे की कतार में बैठी थीं, जबकि उनके माता-पिता पीछे थे. मैं जया को साफ-साफ देख सकती थी. हमारे *लव सीन* देखते हुए उनके चेहरे से आंसू गिर रहे थे. एक हफ्ते बाद फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई मुझे बता रहा था. निर्माता से साफ कह दिया गया था कि वे मेरे साथ काम नहीं करेंगे. हर किसी ने मुझे सूचना दे दी, लेकिन उन्होंने इस विषय में एक शब्द नहीं कहा.

बगैर शादी के सिंदूर

22 जनवरी, 1980 को ऋषि कपूर और नीतू की शादी हुई. नीतू ने अपनी करीबी दोस्त रेखा को भी बुलाया था. पार्टी में मनमोहन देसाई के साथ अमिताभ बच्चन एक कोने में खड़े थे, जबकि जया बच्चन, सास तेजी बच्चन के साथ बैठी थीं. इस बीच सफेद रंग की साड़ी व मंगलसूत्र पहने और माथे पर लाल रंग की बिंदी लगाए हुए रेखा पहुंचीं. मांग में भरा चटख सिंदूर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था. फोटोग्राफर्स का अटेंशन रेखा की ओर था, जबकि रेखा हर पल सीनियर बच्चन को देख रही थीं. दोनों ने 5 मिनट तक बातचीत भी की. जया ने कुछ देर तो खुद को संभाले रखा, फिर वे रोने लगीं. लोग चर्चा कर रहे थे- क्या रेखा ने फिर से शादी कर ली है? कुछ दिन बाद रेखा ने बताया था कि एक फिल्म की शूटिंग के लिए वे खास गेटअप में थीं और शादी की पार्टी में सीधे पहुंच गई थीं.

जब 15 साल की रेखा के साथ जबरदस्ती हुई

बात 1969 की फिल्म *अनजाना सफर* के समय की है. उस दिन रेखा और विश्वजीत के बीच एक रोमांटिक सीन फिल्माया जाना था. जैसे ही डायरेक्टर राजा नवाथे ने एक्शन बोला, विश्वजीत ने रेखा को अपनी बाहों में लिया और चुम्बन करने लगे.

रेखा एकदम अवाक थीं. इस चुम्बन के बारे में उन्हें नहीं बताया गया था. कैमरा रोल होता रहा. लेकिन इस दौरान न डायरेक्टर ने कट बोला और न ही विश्वजीत ने रेखा को चुम्बन करना बंद किया. पूरे पांच मिनट तक वे रेखा को चुम्बन करते रहे. इस दौरान वहां मौजूद यूनिट मेंबर्स सीटियां बजा-बजाकर चीयर कर रहे थे. रेखा की आंखें बंद थीं. लेकिन उनके निकलते आंसू साफ नज़र आ रहे थे.

विश्वजीत ने अपने इस सीन पर सफाई देते हुए कहा था कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. यह सब उन्होंने डायरेक्टर राजा नवाथे के कहने पर किया. यह एन्जॉयमेंट के लिए नहीं था, बल्कि फिल्म के लिए जरूरी था. हालांकि, रेखा उस समय गुस्से में थीं, क्योंकि उन्हें धोखा दिया गया था.■

मनसे ने कहा-नहीं आएगी पूरी फिल्म

मुश्किलों में ऐ दिल है मुश्किल

आगामी महीने दीवाली के मौके पर प्रदर्शित होने जा रही निर्माता निर्देशक करण जौहर की फिल्म पाकिस्तान द्वारा उड़ी में किए गए हमले के कारण अब मुश्किलों में फंसती नज़र आ रही है. इस फिल्म के प्रदर्शन पर अब संशय के बादल मंडराने लगे हैं. इसका कारण यह है कि बॉलीवुड के कुछ सितारों द्वारा पाकिस्तानी कलाकारों के बहिष्कार की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ राजनीतिक लोगों ने उन फिल्मों के बहिष्कार की बात शुरू कर दी है जिनमें पाकिस्तानी कलाकार काम कर रहे हैं.

बता दें कि करण जौहर की इस फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान और इमरान अब्बास ने काम किया है. भारत में पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध होता रहा है, लेकिन उड़ी आतंकी हमले के बाद यह स्वर तीखा हो गया है. उन लोगों की आलोचना शुरू हो गई है जो पाकिस्तानी कलाकारों को अपनी फिल्मों में अवसर देते हैं. गायक अभिजीत तो इस मामले में लगातार बोलते आ रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अपने एक बयान में करण जौहर को दलाल तक कह दिया था.

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने धमकी दी है कि सभी पाकिस्तानी एक्टर और कलाकार भारत छोड़ दें. मनसे नेता अमेय खोपकर ने कहा है कि अगर पाकिस्तानी कलाकार भारत नहीं छोड़ते हैं तो वे खुद उन्हें पकड़कर बाहर करेंगे और पीटेंगे भी. मनसे ने पाकिस्तानी कलाकारों वाली फिल्मों को भी रिलीज़ नहीं होने देने की धमकी दी है. वहीं शिवसेना ने भी पाकिस्तानी कलाकारों के बायकॉट का समर्थन किया है. उन्होंने आगे ये भी कहा कि पाकिस्तानी तो मार खाएंगे ही, साथ ही साथ डायरेक्टर/प्रोड्यूसर को भी पीटेंगे.■

प्रियंका बनीं दुनिया में टीवी की 8वें नंबर की हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस

कमाई के मामले में दीपिका से आगे प्रियंका

11 मिलियन डॉलर (करीब 73 करोड़) की कमाई के साथ प्रियंका इस लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं.

फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली और कमाई करने वाली टीवी एक्ट्रेसस की लिस्ट जारी की है. इसमें 73 करोड़ की कमाई के साथ प्रियंका चोपड़ा 8वें नंबर पर हैं. प्रियंका भारत की पहली ऐसी टीवी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने दुनियाभर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फोर्ब्स लिस्ट में जगह बनाई हैं. पहले नंबर पर सोफिया वर्जारा हैं.

फोर्ब्स की लिस्ट में टीवी सीरीज मॉर्डन फेमिली की कोलंबिया-अमेरिकन एक्ट्रेस सोफिया वर्जारा 288 करोड़ रुपये (43 मिलियन डॉलर) की कमाई के साथ पहले नंबर पर हैं. 11 मिलियन डॉलर (करीब 73 करोड़) की कमाई के साथ प्रियंका इस लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं.

बता दें, पिछले साल प्रियंका की दो बॉलीवुड फिल्में *बाजीराव मस्तानी* और *जय गंगाजल* रिलीज हुई हैं. इसके अलावा वे अमेरिकन टीवी शो *क्वांटिको* में नज़र आईं. जल्द ही वे अपकमिंग फिल्म *बेवॉच* में ड्वेन जॉनसन, पामेला एंड्रेसन, जैक एफ्रॉन और कैली रोहबैक के साथ दिखाई देंगी. यह उनकी हॉलीवुड डेब्यू फिल्म होगी. फिल्मों और टीवी शोज के अलावा प्रियंका एंडोसमेंट्स के लिए करोड़ों रुपये लेती हैं. कमाई का आंकड़ा जून 2015 से जून 2016 का है.■

दीपिका को ऐसे छोड़ा पीछे

अगस्त महीने में फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे ज्यादा फीस पाने और कमाई करने वाली एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी की थी, जिसमें दीपिका पादुकोण 10वें नंबर पर थीं. जून 2015 से जून 2016 तक उनकी कमाई 67 करोड़ आंकी गई थी. प्रिंयका और दीपिका की कमाई में 6 करोड़ का अंतर है. दीपिका भी हॉलीवुड फिल्म कर रही हैं, लेकिन उन्होंने कोई टीवी शो नहीं किया है.■